



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

वर्ष : 18

अंक : 3

RNI No. DELIN/2000/9036

सामाजिक न्याय संदेश

जुलाई-अगस्त-सितंबर 2022

समता, समानता और समरसता का वाहक

ISSN No. 2455-6181



दिव्यांगजन विशेषांक - 1



सत्यमेव जयते

डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

15 जनपथ, नई दिल्ली - 110001

Disabilities Awareness Calender

January

04 Jan. – World Braille Day

February

01-07 Feb. – Children's Mental Health Week

01-28 Feb. – Low Vision Awareness Month

08 Feb. – International Epilepsy Day

March

01 Mar – International Wheelchair Day

21 Mar – World Down Syndrome Day

30 Mar-5 Apr – World Autism Awareness Week

April

02 April – World Autism Awareness Day

07 April – World Health Day

11 April – World Parkinson's Day

17 April – World Hemophilia Day

May

04-10 May – Deaf Awareness Week

18-04 May – Mental Health Awareness Week

June

17-23 June – Learning Disability Week

19 June – World Sickle Cell Day

September

23 September – International Day of Sign Language

October

05-11 Oct. – Dyslexia Awareness Week

06 Oct. – World Cerebral Palsy Day

08 Oct. – World Sight Day

15 Oct. – White Cane Day

24 Oct. – World Polio Day

December

03 Dec. – International Day of Persons with Disabilities

प्रकाशक

डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
15, जनपथ, नई दिल्ली-110001

ई-मेल :

sndaic123@gmail.com

वेबसाइट :

www.daic.gov.in

प्रकाशक व मुद्रक

श्री विकास त्रिवेदी

निदेशक

डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र,
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता
विभाग) के लिए मुद्रित।

अस्वीकरण

“सामाजिक न्याय संदेश” में
प्रकाशित सामग्री में शोध पत्र,
अभिमत, विचार, दृष्टि आदि
लेखकों के हैं। डीएआईसी अथवा
संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं
है। समस्त कानूनी मामलों का
निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली
के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन
होगा।

संरक्षक

श्री वीरेन्द्र कुमार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

कार्यकारी मंडल

श्री आर. सुब्रमयम, सचिव

श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, सदस्य सचिव,
डॉ० अम्बेडकर प्रतिष्ठान एवं अपर सचिव,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

श्री विकास त्रिवेदी

निदेशक, डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

सलाहकार समिति

- प्रो० वैद्यनाथ लाभ: उपकुलपति, नव नालंदा महाविहार, बिहार
प्रो० सुनील के चौधरी: निदेशक, वैश्विक अध्ययन केन्द्र,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
प्रो० संजय द्विवेदी: महानिदेशक, आई.आई.एम.सी, नई दिल्ली
प्रो० पूनम कुमारी: भारतीय भाषा केंद्र, जे. एन. यू., नई दिल्ली
श्री हितेश शंकर: संपादक, पाञ्चजन्य, नई दिल्ली
श्री रणबीर सिंह: निर्माता, अ०ज०क० मास कम्युनिकेशन रिसर्च
सेन्टर, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
प्रो० विरेन्द्र कौंडल: जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर

मुख्य संपादक

डॉ० शिवपूजन प्रसाद पाठक

सह-आचार्य, डॉ० अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र

अंक संपादक: डॉ० सन्तोष कुमार

पी० डी० एफ०, डॉ० अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र

सम्पादकीय मंडल

- डॉ० संजीव शर्मा: सह-आचार्य, डॉ० अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र
डॉ० ज्योत्सना अरोड़ा: पुस्तकालय और प्रलेखन अधिकारी,
डॉ० अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र
डॉ० बिजेंद्र कुमार: सह-आचार्य, डॉ० भीमराव अम्बेडकर कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ० ओम प्रकाश: सहायक आचार्य, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
डॉ० प्रशांत कुमार: सहायक आचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ० अभिषेक प्रताप सिंह: सहायक प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ० नीतूमोनी काकाती: सहायक प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय



अनुक्रमणिका / Contents

समावेशी विकास नीतियों में दिव्यांग	2-8
— डॉ० पंकज कुमार सोनी	
From Viklang to Divyang: A Journey of Empowerment	9-13
- Dr. Adya Shakti Rai	
Effectiveness of Various Government's Schemes	14-20
- Akhilendra Kumar	
केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम	21-22
Higher Education Policies in India for Persons with Disabilities: Building an Inclusive Ecosystem in Higher Education Institutions	23-31
- Dr. Prithviraj Singh Chauhan	
Behavioural Management Techniques: An Interventional Approach in handling Children with Autism Spectrum Disorder	32-38
- Dr. Prashant Srivastava	
दिव्यांगजन अधिकारिता अधिनियम-2016 के अन्तर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता	39
पुर्नपाठ: सामाजिक निष्क्रियता	40-54
— डॉ० भीम राव अम्बेडकर	
Press Note on Achievements of the DAIC, MoSJE (Date: 06.06.2022)	55-57
AI For The Inclusion of Differently Abled Persons: Law and Policy Analysis	58-66
- Dr. Ashok Kumar and Ms. Mansi Shukla	
Guidelines for Submission of Manuscripts	67

संपादकीय

शारीरिक अक्षमता मनुष्य के प्रत्येक कार्यों में बाधा पहुँचाती है क्योंकि शरीर ही सभी साध्यों का साधन है। विदित है कि, सभी मनुष्यों में कुछ अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं लेकिन उसके सम्पूर्ण विकास के लिए कुछ विशेष परिस्थितयां आवश्यक हैं। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि उस परिवेश का निर्माण करे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षमता के उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सके।

भारत सरकार इस दार्शनिक आधार को भली-भांति समझती है और इसलिये वर्तमान में केन्द्रीय सरकार की नीतियां समता, समानता व समरसता से प्रेरित है। यह अवधारणा, जन-सहभागिता, प्रतिनिधित्व और जन के सम्मान पर आधारित है जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी परिलक्षित हो रही है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण और भारत रत्न के पुरस्कार हैं। वर्ष 2015 से अब तक मिले पुरस्कारों की सूची का भौगोलिक विस्तार और सामाजिक प्रतिनिधित्व जन के सम्मान को प्रदर्शित करता है। यही सोच दिव्यांगजनों से सम्बंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में भी दिखती है।

सरकार यह मानती है कि एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए दिव्यांगजन की सहभागिता आवश्यक है। वे समाज के अनिवार्य हिस्सा हैं। दिव्यांगजन की स्थिति विशेष होती है, इसलिए सरकार ने दिव्यांगता को पुर्नपरिभाषित किया है। दिव्यांगजन के लिए समानता, सम्मान और अवसर का निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016” को पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिदृश्य में दिव्यांगजनों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पुनर्वास के प्रयास को विस्तारित किया गया है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने दिव्यांगता की श्रेणी को विस्तृत किया है। पहले सात प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी होती थी, इसके स्थान पर 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। इसमें अम्ल पीड़ित और बौनेपन को भी दिव्यांग श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने अभी सांकेतिक भाषा के विकास और प्रसार को भी महत्वपूर्ण माना है। यह सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने व जीवन को गौरवशाली बनाने के लिए तत्पर दिखती है, लेकिन दिव्यांगजन के विषय में कई मील और चलना शेष है ताकि एक सहभागी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो सके।

दिव्यांगजन से सम्बंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए ‘सामाजिक न्याय सन्देश’ का यह विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा। आशा है कि आप सभी इस विमर्श का सहभागी बनेंगे।

शिव पाठक



समावेशी विकास नीतियों में दिव्यांग

— डॉ० पंकज कुमार सोनी

सार संक्षेप— वर्तमान समय में संस्थागत परिवर्तनों के साथ-साथ सैद्धांतिक विचारों को एक नए पहलू और एक नए चरित्र के साथ परिभाषित किया जाना आवश्यक है। यह प्रश्न प्रवृत्तियों और प्रतिमानों की नई दिशाओं के संदर्भ में आवश्यक परिवर्तन की स्थिति को दर्शाते हैं जो आधुनिकीकरण में भागीदारी को अनिवार्य मानते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में भारत के आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक ढांचों में बड़ा बदलाव देखा है। भारत एक उभरती हुई शक्ति होने के नाते दुनिया के प्रमुख शक्तियों के साथ विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अपने स्वयं के तर्कों पर बहस और विचार विमर्श को शुरू कर चुका है। इसी क्रम में मानवाधिकार का संवर्धन और सुरक्षा हमारी विकास नीति के आवश्यक पहलू में से एक है। भारत की विकास नीति में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं। नई चुनौतियों और खतरों के संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। दिव्यांग व्यक्ति समाज के सबसे कमजोर समूह के रूप में सामने आता है। मुख्यधारा के समाज के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के विकास और सामाजिक समावेश के बीच संबंध को समझना अति आवश्यक है। यह पत्र इसी संदर्भ में एक आकलन प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

सामाजिक वास्तविकता की खोज और विश्लेषण के लिए पारंपरिक उत्साह की तुलना में सामाजिक विज्ञान में हाल के विकास एक आदर्शवादी दृष्टिकोण दिखाते हैं। ऐसे में, दिव्यांगता सामाजिक विज्ञान पर गंभीर पुनर्विचार का प्रमुख विषय बन गया है। दिव्यांगता एक सैद्धांतिक पहली के रूप में उभरी है जिसने भेदभाव और न्याय के मुद्दों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया है। वर्तमान संदर्भ में, यह ध्यान में रखना होगा कि दिव्यांगता के मुद्दे को ज्यादातर सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया

है। दिव्यांगता की समस्या को हमेशा चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखा जाता था जिसमें सामाजिक और आर्थिक आयामों की उपेक्षा की जाती थी। दिव्यांगता अधिकारों के संघर्ष में यह माना गया कि दिव्यांगता केवल चिकित्सा की दृष्टि से समझी जाने वाली घटना नहीं है। इस घटना की प्रकृति को एक ऐसे परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत है जो समाज की मौजूदा अवधारणाओं का एक विकल्प है। यह तदनुसार सामाजिक नीति प्रतिक्रियाओं को सूचित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्गों के भीतर और उनके बीच दिव्यांगता से संबंधित संघर्ष को प्रोजेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर बहुत विश्लेषण किया गया है लेकिन बहुत कम विश्लेषण हैं, जिन्होंने मुख्य मुद्दे के रूप में दिव्यांगता पर चर्चा की है। हाल के दिनों में, दिव्यांगता पर चर्चा में एक नया उभार आया है जो पहले नहीं था। कई मुद्दों पर वैज्ञानिक और राजनीतिक चर्चा में एक महान एकीकरण पर पहले से ही चर्चा और बहस चल रही है। दिव्यांगजनो के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन दुनिया भर में बढ़ रहे थे जिसने शोधकर्ताओं को दिव्यांगता के अध्ययन और विश्लेषण और उनकी पुनर्वास नीतियों पर ध्यान देने के लिए काफी प्रभावित किया है। पिछले कुछ दशकों के दौरान, दिव्यांगता की प्रकृति और उनके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर जनमत और बहस ने अधिकांश देशों की नीतियों में भारी परिवर्तन किया है। नतीजतन, सामाजिक धारणा में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। अब, दिव्यांगता का मुद्दा विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत चिकित्सा समस्या से एक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्या में स्थानांतरित हो गया है। दिव्यांगता की घटना को अब व्यक्तिगत चिकित्सा मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसे दिव्यांगता के पारंपरिक दृष्टिकोण से पहचाना जाता है। इस प्रकार,

दिव्यांगता के संरचनात्मक चरित्र पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। दिव्यांगों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र की समझ आवश्यक है।

दिव्यांगों के संदर्भ में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संघर्ष जारी है। मानव अधिकार वास्तव में लोगों के अधिकार हैं जहां व्यक्तियों या समूहों जैसे दोनों स्तरों पर स्वयं लोगों द्वारा लगातार सतर्कता और कार्रवाई की जाती थी। दिव्यांगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे मुख्य रूप से उनके मानवाधिकारों की पहुंच हैं। मानव अधिकारों के विकास के लिए परिस्थितियों की उपलब्धता के संदर्भ में इस समस्या का पता लगाया जा सकता है जिसने उसे एक इंसान के रूप में प्रदान किया है। मानवाधिकारों तक पहुंचने का संघर्ष दिव्यांगता आंदोलन का मूल है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि दिव्यांगों को लगभग सभी समाजों और समूहों में उत्पीड़ित, हाशिए पर और कलंकित किया जाता है। दिव्यांगों की पहचान उनके सामने आने वाली शारीरिक और सामाजिक बाधाओं से की जा सकती है। उन्हें अभिनय, मिलनसार और सामुदायिक जीवन में भाग लेने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन पूरी तरह से सामाजिक परिवेश से असंबंधित इकाई नहीं है। दिव्यांगों के लिए मानवाधिकारों की उपलब्धि के लिए वैश्विक आंदोलन अधिकार-आधारित आंदोलनों पर आधारित एक हालिया घटना है।

यह पत्र दिव्यांगों के मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए संबंधित गतिविधियों का गहन विश्लेषण चाहता है। दिव्यांग समाज का सबसे कमजोर वर्ग है। दिव्यांगता के संरचनात्मक स्वरूप के कारण दिव्यांगों को सामाजिक परिवेश के संदर्भ में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस सामाजिक बहिष्कार का सामना दिव्यांगों द्वारा दैनिक आधार पर किया जाता है जिससे उनके लिए कार्य करना और सामान्य सामुदायिक जीवन में भाग लेना कठिन हो जाता है। यह अध्ययन दिव्यांगों को उनकी ताकत, क्षमताओं और क्षमताओं के अनुसार समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में तैयार करने और संलग्न करने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। यह नीति निर्माता की प्राथमिकता होनी चाहिए। नीति निर्माता उचित

आय सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को बनाए रखते हुए दिव्यांगों की स्थिति में सुधार के लिए पहल कर रहे हैं। हाल के वर्षों में अपनाई गई नीतिगत पहलों में नागरिक अधिकार सुरक्षा, आय सुरक्षा (नकद सहायता), स्वास्थ्य कवरेज, रोजगार संबंधी सहायता सेवाएं और कर नीति के लिए कानून शामिल हैं। यह अतिआवश्यक है कि ये पहल दिव्यांगों की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने और दिव्यांगता नीति के अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हैं। इन सभी प्रश्नों को कवर करने के लिए सरकार के द्वारा वैकल्पिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है।

दृष्टिकोण का विकास

यह पत्र अर्थशास्त्र की मदद से सार्वजनिक नीति और दिव्यांगता के बीच संबंध विकसित करने की कोशिश करता है। अर्थशास्त्र की किसी भी नीति में समस्या का दोहरा पक्ष है जिसका अर्थ है मांग-पक्ष और आपूर्ति पक्ष पर भी विचार करना। मानव अधिकार संवर्धन में हालिया विकास ने इस संबंध (दिव्यांगता और सार्वजनिक नीति) के मांग पक्ष को विकसित किया है।

इन कई क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से दिव्यांगता की मांग की गई है –

(1) दिव्यांगता की रोकथाम (2) मौद्रिक या प्रकार के माध्यम से जोखिम प्रबंधन और पुनर्वितरण (जब दिव्यांगता को रोका नहीं जा सकता) (3) व्यापक गरीबी और भेद्यता (4) के संदर्भ में गरीबी और दिव्यांगता का अंतर सार्वजनिक सेवाओं के वितरण जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य के संदर्भ में दिव्यांगता की बातचीत, जहां सेवा वितरण की सामान्य प्रणालियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और (5) रोजगार और दृष्टिकोण जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति की भूमिका जहां बाजार या सामाजिक संस्थान एक भूमिका निभाते हैं।

दूसरी ओर, कुछ चर है जो हमेशा समानता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है जो भेदभाव की सीमा को कम करता है। ये चर (1) न्याय तक पहुंच, (2) शिक्षा (3) स्वास्थ्य (4) कार्य और रोजगार और (5) भागीदारी हैं। ये इस मुद्दे के आपूर्ति पक्ष के रूप में विचार कर रहे हैं। दिव्यांगता में मानक साक्षर इसे पुनर्वास के उपाय के रूप में लेते हैं।



दिव्यांगता और विकास की अवधारणाएं जटिल हैं और उनकी परिभाषा और माप को स्पष्ट किए बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। विकास आमतौर पर एक निर्वाह अर्थव्यवस्था से एक आश्रित अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। परिवर्तन अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं में होता है, जिसमें उपभोग, उत्पादन, निवेश, व्यापार की संरचना, जनसांख्यिकीय रुझान और आर्थिक संस्थानों में शामिल है। जबकि विकास को आमतौर पर इसके संकीर्ण आर्थिक अर्थों में समझा जाता है, इसके मानवीय और राजनीतिक आयाम भी हैं। मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव जीवन की अन्य स्थितियों के विस्तार की प्रक्रिया है। अपने राजनीतिक अर्थ में, विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को बेहतर नागरिक अधिकार प्रदान करता है और यह निर्धारित करने के अवसर के साथ कि कौन शासन करना चाहिए। यह एंटाइटेल्मेंट और संस्थानों को संदर्भित करता है जो आमतौर पर लोकतंत्रों के साथ संबद्ध होता है।

इस व्यापक अर्थ में, विकास व्यक्तियों की क्षमताओं और स्वतंत्रता में वृद्धि को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), विकास या औद्योगिकीकरण में कैपचर किए गए विकास के पारंपरिक आर्थिक दृष्टिकोण की तुलना में विकास की यह अवधारणा कहीं अधिक कठिन है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मानव विकास सूचकांक सहित विकास के इस व्यापक दृष्टिकोण को पकड़ने के लिए कई उपाय विकसित किए गए हैं। इस प्रकार विकास एक बहुआयामी शब्द है। हम इसे आर्थिक, मानवीय और राजनीतिक आयामों के साथ एक व्यापक अवधारणा के रूप में समझते हैं जब हम दिव्यांगता की इसकी कड़ी को समझने का प्रयास करते हैं।

प्रत्येक अवधारणा को परिभाषित करने के लिए हम जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, उसके आधार पर विकास और दिव्यांगता अवधारणाएँ ओवरलैप हो सकती हैं। हालांकि, अगर विकास को एक व्यापक-आधारित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव क्षमताओं को बढ़ाता है, तो यह दिव्यांगता के साथ अच्छी तरह से अंतर हो सकता है। यह मामला है अगर हम खुद को सामाजिक मॉडल में रखते हैं जहां दिव्यांगता एक मानवाधिकार का मुद्दा है, या अगर हम

दिव्यांगता की क्षमताओं के दृष्टिकोण को अपनाते हैं जहां दिव्यांगता को क्षीणता वाले व्यक्तियों के लिए क्षमता में कमी के रूप में परिभाषित किया गया है। तब स्पष्ट रूप से, यदि अक्षम होने का मतलब है क्षमताओं से वंचित होना, दिव्यांगता को कम करना विकास के सूक्ष्म रूप में कल्पना की जा सकती है। उत्तरार्द्ध को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ मानव क्षमताओं को बढ़ाकर पूर्व पर अंकुश लगाती है। विकास और दिव्यांगता तब दो आंतरिक रूप से जुड़ी हुई अवधारणाएँ हैं। विकास और दिव्यांगता के बीच संबंध से संबंधित चार मूलभूत प्रश्न हैं: (1) विकास दिव्यांगता की व्यापकता को कैसे प्रभावित करता है? (2) विकास जनसंख्या के भीतर दिव्यांगता के वितरण को कैसे प्रभावित करता है? (3) विकास दिव्यांगता के प्रमुख कारणों को कैसे प्रभावित करता है? (4) दिव्यांगता का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है?

इन सवालों को खोजने के लिए, विश्व बैंक ने एक समिति गठित की, जो बताती है कि विकास संबंधी नीतियों में पाँच उभरती हुई प्रवृत्तियाँ हैं – (1) दिव्यांगता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सहायता का एक हिस्सा बन गया है, (2) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नीतियाँ अक्सर एमडीजी से दिव्यांगता को जोड़ती हैं (3) समीक्षा की गई नीतियों और प्रथाओं में अक्सर फ्रेम के कई दृष्टिकोण शामिल होते हैं जो विकास में दिव्यांगता को शामिल करते हैं, जिसमें मानव अधिकार, भागीदारी, समावेशी विकास शामिल हैं (4) दिव्यांगता को विशिष्ट लक्षित और मुख्यधारा समावेश एकीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से शामिल किया गया है (5) दृष्टिकोण, नीतियाँ और कार्यक्रम गतिशील हैं और समय के साथ बदल गए हैं

सीआरपीडी से निकलने वाला एक केंद्रीय विषय, और विशेष रूप से अपने दायित्वों में परिलक्षित होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के विकास सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें गरीबी में कमी और अन्य आर्थिक और सामाजिक विकास रणनीतियों के कार्यान्वयन में पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों और उनके देश के विकास कार्यक्रमों के नियोजन, डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में

उनके प्रतिनिधि संगठनों के साथ भागीदारी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दाताओं, साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एजेंसियों और कार्यक्रमों ने अपनी विकास सहायता के संदर्भ में दिव्यांगता समावेशन को संबोधित करने के लिए काम किया है।

गरीबी, अविकसितता की सबसे अधिक दिखाई देने वाली विशेषता है। आजकल इस बात पर थोड़ा विवाद है कि विकास का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। इसलिए, गरीबी और दिव्यांगता के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विचार है। यदि दिव्यांगता और विकास के बीच संबंध जटिल और अस्पष्ट है, तो दिव्यांगता और गरीबी के बीच क्या कहा जा सकता है?

गरीबी और दिव्यांगता को एक दुष्चक्र के माध्यम से जोड़ा गया है जिसे कई स्रोतों में वर्णित किया गया है। यह दो तरह का रिश्ता है – दिव्यांगता गरीबी के जोखिम को जोड़ती है और गरीबी की स्थिति दिव्यांगता के जोखिम को बढ़ाती है और गरीबी और दिव्यांगता के चक्र का परिणाम यह है कि दिव्यांग लोग आमतौर पर सबसे गरीब लोगों में से हैं।

गरीबी और दिव्यांगता के बीच संबंध दो तरीके से चलते हैं – न केवल दिव्यांगता गरीबी के जोखिम को जोड़ती है, बल्कि गरीबी की स्थिति दिव्यांगता के जोखिम को जोड़ती है। गरीब परिवारों के पास पर्याप्त भोजन, बुनियादी स्वच्छता और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है। वे कम गुणवत्ता वाले आवास में रहते हैं और अधिक खतरनाक व्यवसायों में काम करते हैं। गरीबी स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त पोषण और सुरक्षित कार्य वातावरण तक पहुंच को सीमित करके दिव्यांगता की घटनाओं और प्रसार को बढ़ाती है, जिससे बीमारी और चोट का खतरा बढ़ जाता है। खराब पोषण और खराब स्वच्छता हानि का मुख्य कारण है। इस तरह, गरीबी और दिव्यांगता दो तरह से रिश्ते से बाहर हो जाते हैं, जहां दिव्यांगता गरीबी के जोखिम को बढ़ाती है और गरीबी की स्थिति गरीबी के जोखिम को बढ़ाती है।

कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि गरीबी और दिव्यांगता का जोरदार संबंध है। गरीबी दिव्यांगता को प्रभावित कर सकती है और दिव्यांगता गरीबी को प्रभावित कर सकती है। इस तरह के रिश्तों को समझना गरीबी घटाने की रणनीतियों के डिजाइन के

लिए आवश्यक है जो निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है

इन सभी मुद्दों के मद्देनजर, कुछ अंतरराष्ट्रीय नीति समन्वय पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। नीति समन्वय तब होता है जब देश समझौते में शामिल सभी देशों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सहमत होते हैं। पिछले तीस वर्षों में दिव्यांग लोगों के लिए मानव अधिकारों की विश्वव्यापी मान्यता में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, पिछले तीन दशकों के भीतर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मानवाधिकार उपकरण को अपनाया है जो अलग-अलग-अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भी अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की रक्षा और उन्नति करता है। जैसा कि पहले कहा गया था कि ये दिव्यांग आधारित तंत्र मानव अधिकारों को बढ़ावा देते हैं साथ ही दिव्यांग लोगों को गरिमा और समानता।

इस अंतर को अंतरराष्ट्रीय बहस के साथ प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह रेखांकित करना है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता का भेदभाव भी भेदभाव के इन सवालों के आसपास घूमता है। एक तरफ, दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसरों, गरिमा और गैर-दिव्यांगों के समान सम्मान की आवश्यकता होती है, दूसरी ओर, उन्हें अंतर के उचित संशोधन की आवश्यकता होती है। समस्या के इस पहलू को अगले खंड में भारतीय विकास नीति के अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ समझा जा सकता है।

नीति निर्माताओं के लिए निहितार्थ

दिव्यांगता की घटना मानव अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे उस सामाजिक स्थिति से अलग नहीं दिया जा सकता है जहां यह उत्पन्न होता है। दिव्यांगता के बारे में धारणाएं समय-समय पर जगह-जगह और व्यक्ति-व्यक्ति में बदलती रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्यांगता की विविधता को न केवल कार्य-कारण में भिन्नता, दुर्बलता, गंभीरता, और रोग का निदान के रूप में देखा जा सकता है बल्कि इस स्थिति को पूरी आयु सीमा तक महसूस किया जा सकता है। दिव्यांगता को लिंग या सामाजिक वर्ग का विभेद के आधार पर भी नहीं देखा जा सकता है।



दिव्यांगता को एक ऐसे मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई जो जनसंख्या के महत्वपूर्ण अनुपात को प्रभावित करती है। 1980 के दशक के मध्य में, एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया कि दिव्यांगता के साथ 6 मिलियन से अधिक लोग थे। दिव्यांग लोग दुनिया में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हैं। एक समूह के रूप में, वे गैर-दिव्यांगों के लिए उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के भूखे हैं। दिव्यांग व्यक्ति कम से कम पोषित, कम से कम स्वस्थ, कम से कम शिक्षित और कम से कम रोजगार पाने वाला समुदाय है। उनके पास उपेक्षा, अलगाव, अलगाव, गरीबी, अभाव, दान और यहां तक कि दया का पत्र होने के अनुभव का एक लंबा इतिहास है।

दिव्यांग व्यक्तियों की समस्या हर देश में अलग-अलग नहीं है। यह अनुभव करना आम है कि विभिन्न देशों में दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक होने की ओर झुकाव रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जबरदस्त होने के बावजूद, सार्वजनिक व्यवहार में दिव्यांगजनों के प्रति दान और दया का ही भाव प्रमुख रहता है। दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक भावनाएं विकास और विकास के लिए ऐसे वंचितों की क्षमता को प्रभावित करती हैं। यह उत्पादकता में एक महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बनता है साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों की अव्यक्त प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यवहार में परिवर्तन ही दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में परिवर्तन लाते हैं, और इस तरह सार्वजनिक व्यवहार और उनके प्रति व्यवहार से अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाता है।

हमारी चिंता यह है कि इनमें से प्रत्येक डोमेन में समस्याएं एक आम नीति अनुसंधान प्रतिमान से प्राप्त होने वाले भ्रामक निष्कर्षों के परिणामस्वरूप हो सकती हैं। इसकी कई सकारात्मक विशेषताओं के बावजूद, भारत में दिव्यांगता के लिए नीतिगत ढांचे में सुधार की गुंजाइश है, विशेष रूप से राज्य स्तर पर जहां नीति विकास काफी हद तक अनुभवों पर आधारित रहा है। दिव्यांगों के मूलभूत मुद्दे इस हद तक हैं कि विकास के तहत विभिन्न प्रकार से उनके अधिकारों को हस्तांतरित करने में दशकों समय लग गए हैं। आज भी यह पूर्ण रूप से हस्तांतरित नहीं हो पाया है। अब, यह वह समय है जब संस्थागत तंत्र ने

अधिकारों को लागू करने और प्रदाताओं की जवाबदेही बढ़ाने के लिए जगह बनाई गई है और व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाया जा रहा है।

दिव्यांगता क्षेत्र में नीति और संस्थागत सुधार की आवश्यकताएं दोनों हैं। इस बिंदु पर, दिव्यांग लोगों के लिए परिणामों पर ध्यान देने का सुझाव होगा कि प्राथमिकता संस्थागत सुधार और सुदृढीकरण पर होनी चाहिए। दिव्यांगता क्षेत्र में अंतर्विरोधी ढांचे की समीक्षा करना और नीति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। बहरहाल, कई व्यापक नीतिगत सुधार महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है।

दिव्यांगता की लागत की तुलना जब दिव्यांगता और समानता की अलग-अलग धारणा के बीच किया जाए, तब इनके बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है। यह अधिक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह एक अच्छी तरह से स्वीकार किया गया तथ्य है कि दिव्यांगता की एक अतिरिक्त लागत है। बहुत सारे अर्थशास्त्री ने दिव्यांगता की अतिरिक्त लागत को मापने का प्रयास किया है। दिव्यांगता स्पष्ट रूप से एक प्रासंगिक उदाहरण है जहां एक पर्याप्त संसाधन विभिन्न मानव आवश्यकताओं और बंदोबस्तों की पूरी श्रृंखला का पूरा लेखा-जोखा लेता है, इसमें संसाधनों के चयन और वजन की आवश्यकताएं शामिल होंगी। यह मानना असंभव है कि हानि के साथ कई लोगों द्वारा अनुभव किए गए सभी नुकसान भेदभाव के कारण होते हैं। न्याय के एक सिद्धांत को हानि से उबरने में मदद करने के लिए लोगों को सामाजिक संसाधनों को आवंटित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अपने शारीरिक या मानसिक लक्षणों को आदर्श रूप से सामाजिक वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं। इसलिए दिव्यांगता भेदभाव की सीमा को देखना बहुत आवश्यक है।

राज्य दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। मूल रूप से, दिव्यांगता भेदभाव को तीन-आयामी दृष्टिकोण से समाप्त किया जा सकता है। इन तीन आयाम में पहला आयाम भेदभाव और उचित समायोजन पर आधारित है। दूसरा आयाम दिव्यांगता

मानक और सार्वजनिक समायोजन पर जोर देता है। जबकि तीसरा आयाम कार्ययोजना और आचरण के नियम निर्धारित करता है।

समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को खत्म करने के लिए, इन मुद्दों पर एक नए रूप को समझना आवश्यक है। 21 वीं सदी के लिए चुनौती यह है कि मानव अधिकारों के संचालन के लिए तंत्र विकसित किया जाए जिससे समानता एक सार्थक अनुभव साबित हो सके। मानव अधिकार के लिए, दिव्यांग लोग अपने समावेश के लिए सामाजिक बाधाओं को पहचानने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं।

तीन आयामों में से पहले में, राज्य एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करता है जो अन्यायपूर्ण उपचार का जवाब देने की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण का दूसरा आयाम परिचालन रूप से मानव अधिकारों का है जहां राज्य असमानताओं का जवाब देने में एक सतत भूमिका निभाते हैं और प्रणालीगत भेदभाव से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं जिन्हें भेदभाव विरोधी प्रक्रियाओं के माध्यम से बस संबोधित नहीं किया जा सकता है। तीसरा आयाम बड़े पैमाने पर समुदाय की भूमिका प्रदान करके राज्यों और दिव्यांग लोगों की साझेदारी पर आधारित है।

नीति निर्माताओं के द्वारा किये गए प्रयास

दिव्यांगता भेदभाव की सीमा नस्ल, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव जैसे अन्य प्रकार के भेदभाव से अलग है। यह समझने में आने वाली मुख्य कठिनाई है दिव्यांगता से संबंधित भेदभाव की समस्या। इस समस्या को जातिगत भेदभाव या नस्ल भेदभाव की तरह नहीं देखा जा सकता है।

इसके अलावा, समानता और भेदभाव की सीमा को कम करने के लिए कुछ कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कारक हैं (i) न्याय तक पहुंच, (ii) शिक्षा, (iii) स्वास्थ्य (iv) काम और रोजगार और (v) भागीदारी। इन्हें इस मुद्दे का आपूर्ति पक्ष भी माना जा सकता है। दिव्यांगता में मानक साहित्य इसे पुनर्वास के उपाय के रूप में लेता है।

दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने की चुनौती पूरी तरह से साकार नहीं हो पाई है। अंतरराष्ट्रीय मानकों और अनुकरणीय प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी कानून, कुछ देशों में अनुकूल नीतियों

और प्रथाओं के कार्यान्वयन के बावजूद, दिव्यांग व्यक्ति – विशेष रूप से महिलाएं, युवा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग – अशिक्षित, अप्रशिक्षित, बेरोजगार, अल्परोजगार और गरीब ही हैं।

किसी भी व्यक्ति की बुनियादी जीवन संरचना तीन मुख्य कारकों—आय, रोजगार और विशिष्ट रहने की व्यवस्था पर आधारित होती है। हालाँकि, दिव्यांगता एक अधिकार आधारित विकासात्मक आंदोलन है। इस विकासात्मक आंदोलन का गरीबी से सीधा संबंध है। यह एक जुड़वां ट्रैक संबंध है। दिव्यांगता गरीबी के जोखिम को बढ़ाती है और गरीबी भी दिव्यांगता के जोखिम को बढ़ाती है। दुनिया भर में बहुत सारे अनुभवजन्य डेटा इस संबंध के अस्तित्व को दर्शाते हैं। दिव्यांगता जीवन शैली की अतिरिक्त लागत की ओर ले जाती है और अंत में गरीबी के जाल में फंस जाती है।

भारत के मामले में दिव्यांग के अधिकार विकास को निम्नलिखित चार अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है: (1) चरण I – जिसमें पूर्व स्वतंत्रता की अवधि शामिल है और आम तौर पर एक अज्ञात डेटाबेस होता है (2) चरण II – जो तुरंत बाद की अवधि को कवर करता है मोटे तौर पर 1980 तक। इस अवधि को दिव्यांग लोगो से संबंधित मुद्दों पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय जागरूकता द्वारा चिह्नित किया गया विकास नीति में समायोजन किया गया। (3) चरण III – जिसमें 1980 से 2000 की अवधि शामिल है, को समावेशी विकास नीतियों द्वारा चिह्नित किया गया है और (4) चरण IV – में सुधार के बाद की अवधि को चालू वर्ष यानी 2000 से 2022 तक शामिल किया गया है, जो कि है दिव्यांगता से जुड़े मुद्दे पर व्यापक और गहन विश्लेषण की अवधि के रूप में माना जा सकता है।

दिव्यांग लोगों की संख्या को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि दिव्यांगता एक बहुत ही जटिल घटना है जिसका आकलन करना मुश्किल है। दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न समस्याएं विभिन्न दिव्यांगजनों में भिन्न-भिन्न हैं। मधुमेह, हृदय रोग और मानसिक विकारों जैसी स्वास्थ्य स्थितियों में भी वैश्विक वृद्धि हुई है, जो प्रकृति की समझ और दिव्यांगता की व्यापकता को भी प्रभावित करती है। किसी विशेष देश में दिव्यांगता के पैटर्न स्वास्थ्य की



स्थिति और पर्यावरण और अन्य कारकों में प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं – जैसे सड़क यातायात दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, संघर्ष, आहार और मादक द्रव्यों का सेवन। हाल के दिव्यांगता अधिकार आंदोलन में, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजना परियोजना की पुनः जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सरकार ने हाल ही में इस आंदोलन को बहुत गहराई से समझना शुरू किया था। सरकार के द्वारा किए गए प्रयास को तीन प्रकार के दृष्टिकोण में रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है— (1) पुनर्वास आधारित दृष्टिकोण, (2) समाज-कल्याण आधारित दृष्टिकोण, और (3) सशक्तिकरण आधारित दृष्टिकोण।

दिव्यांगजनों का संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति के संघर्ष की तुलना में ज्यादा जटिल है। दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुभवों की सीमित समझ के साथ दिव्यांगजनों के सम्मान, सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए, हमें इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए दिव्यांगता की एक पूर्ण अवधारणा विकसित करने की आवश्यकता है, जो समावेशी विकास के लिए एक उचित तंत्र के निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमारा देश भारत इन बारीकियों को समझने में लगा है। भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण की प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार योजनाओं और नीतियों का निर्माण किया है सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्षेत्र में कई कार्यक्रम शुरू किए। साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जैसी अन्य संस्थाएं ने भी दिव्यांग व्यक्तियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

उपसंहार

यह सामान्य अनुभव है कि विभिन्न देशों में दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक ही होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जबरदस्त प्रगति के बावजूद, अंधविश्वास, दान और करुणा के साथ एक जुनून के कारण, दिव्यांगता पर तिरस्कार या दया दिखाने का यह रवैया सार्वजनिक व्यवहार में काफी दिखाई देता है। दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक भावनाएं ऐसे वंचित लोगों की क्षमता को समझने में बाधा डालती हैं जो उनकी वृद्धि और विकास में बाधक हैं। इससे उत्पादकता में महत्वपूर्ण नुकसान होता है और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों की गुप्त प्रतिभा भी छुपी रह जाती है। इस प्रकार, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा

सकता है कि व्यवहार परिवर्तन दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में परिवर्तन लाते हैं, और इस प्रकार उनके प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देते हैं।

दिव्यांगता को अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से देखा गया है। आम तौर पर, दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों की ताकत और सीमाओं की समझ से काफी हद तक निर्धारित किया गया है। आधुनिक समय में, विधायी उपायों के कार्यान्वयन, दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियों और राज्य की बढ़ती प्रतिबद्धता ने सार्वजनिक दृष्टिकोण में कुछ प्रत्यक्ष परिवर्तनों में मदद की है। लेकिन, यह परिवर्तन दिव्यांगता के बारे में किसी की समझ के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण प्रसारित नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि दिव्यांगजनों के मुद्दों की व्यापक तरीके से व्यवहारिक समझ को विकसित किया जाए।

संदर्भ:

- विकलांगता नियमावली 2005
- लिंग, जाति, धर्म और विकलांगता के आधार पर भेदभाव
- भारत सरकार, 2006 में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार पर पुस्तिका
- मानव अधिकार शिक्षा शुरुआती के लिए, अध्याय 2—विकलांगों के अधिकार
- अपने अधिकारों को जानें: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
- विकलांगों के अधिकार: अनुराधा मोहिती, मीरा पिल्लई और प्रीति रूंगटा
- आर बर्थोड, जे लेकी, एस मैकके, (1993): द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल पीपल, पॉलिसी स्टडीज इंस्टीट्यूट, लंदन
- ए, एलवान (1999): गरीबी और विकलांगता: साहित्य का एक सर्वेक्षण, सामाजिक संरक्षण चर्चा पत्र श्रृंखला, संख्या 9932, विश्व बैंक, वाशिंगटन
- ए सेन (1983): आर्थिक असमानता पर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस
- ए सेन और जीन ड्रेज (2002): भारत: विकास और परिवर्तन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस
- एस, मित्रा (2003): विकलांगता योग्यता दृष्टिकोण, वर्किंग पेपर, रटगर्स विश्वविद्यालय
- पी के सोनी (2019): भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में विकलांग युवा लड़कियों के लिए नीति प्रतिक्रियाएँ SIS, JNU में राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत पत्र
- बाकुर, अली (1997): विकलांगता चुनौतियां बनाम प्रतिक्रियाएं, कैन, नई दिल्ली
- माइकल ओलिवर (1996): अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी: थ्योरी टू प्रैक्टिस, पालग्रेव, हैम्पशायर
- टी बुरचर्ड (2000): डायनामिक्स ऑफ बीइंग डिसेबल, जर्नल ऑफ सोशल पॉलिसी, 29: 4, 645-68
- संयुक्त राष्ट्र (2006): विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन, जेनेवा
- DFID (2000), विकलांगता, गरीबी और विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास विकलांगता विभाग, CASE रिपोर्ट 21, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

From Viklang to Divyang: A Journey of Empowerment

Dr. Adya Shakti Rai

Disability, which is a derivation of difference in ability, is a part of human variation. Discrimination and stigmatization of people with disability have continued throughout history. They are not only deprived to develop their innate capabilities in a full-fledged manner and but are also discouraged to participate meaningfully in the progress of the society. Disability has been an integral part of human race since the beginning. Even though the approach towards disability varied from place to place and culture to culture during these periods but mostly the approach was negative. It took a long time in transforming the approach towards disability from negative to positive and the path was never easy. It was comprised of several attitudinal changes in the mind- set of society, which is reflected in several models of disability.

This paper is a discourse which endeavors to ensure the empowerment of persons with special needs. Further, it also describes the journey from apathy to empathy, exploitation to empowerment, exclusion to inclusion, and viklang to 'divyang'.

Differences in the ability of the individual members of society are a naturally existing phenomenon. Disability, which is a derivation of difference in ability, is a part of human variation. Each individual is characterized with different appearances, needs, abilities, and preferences etc. Each and every individual is different from others and persons with disabilities belong to same society. Disabled people do not belong to a separate society but are an integral part of it. But at the same time, this is also true that society holds a negative approach towards the disabled. People with disability have always been discriminated and stigmatized and unfortunately, it's a reality in today's civilized world also. Since centuries, Persons with

disabilities have been experiencing economic and political marginalization particularly the disabled children who are often excluded from society and face negative attitudes and stigma attached to them. This disadvantaged, ostracized and marginalized section of the society is very much an integral part of the society and this need to be realized. Social prejudices prevail when children with learning, speech, physical, cognitive, or sensory impairments find difficult to live just like other individuals of society. They are not only deprived to develop their innate capabilities in a full-fledged manner and but are also discouraged to participate meaningfully in the progress of the society. They face discrimination in the form of systemic apathy towards them.

Various studies related to disability has shown that people with severe disabilities had to face discrimination and hardship at every walk of life which force them to live below poverty line without proper education and basic medical facilities. They have been deprived of the basic facilities which otherwise would have easily accessible. In India before 1995, the year in which PwD Act was enacted, people with special needs did not enjoy any legislative rights. History of special education clearly indicates that people with special needs have travelled a long journey from apathy to empathy, exploitation to empowerment, exclusion to inclusion, and viklang to 'divyang'. They have always suffered from the stigma of not being a productive member of the society because of lack of wisdom and understanding.

Defining disability worked as the first step towards the empowerment of the disabled person. As the Preamble to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) -2006, adopted by the United Nations, describes disability by stating that:



“Disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.” The Convention further emphasizes that “Persons with disabilities include those who have long term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.” The World Health Organization (2014) refers to disability as a complex phenomenon, reflecting the interaction between features of a person’s body and features of the society in which he or she lives.

Disability has been an integral part of human race since the beginning. Even though the approach towards disability varied from place to place and culture to culture during these periods but mostly the approach was negative. It took a long time in transforming the approach towards disability from negative to positive and the path was never easy. It required several attitudinal changes in the mind-set of society, which gets reflected in several models of disability. Over the years, various models of disability have been conceptualized which emphasize upon the evolution of disability concept. All these models have approached disability in quite different ways. Let us have a look on models of disability.

Religious Model of Disability: Religious model of disability sees disability as a punishment of some sin or bad deed committed by the disabled individual or their parent; it is an act of God to punish them as a result of their bad karma. They consider disability as punitive and calamitous. This is the oldest model of disability and pre-modern paradigm which endorse upon that God or any other external force inflicts disability to an individual or family as a punishment. It is the result of the misdeed committed by individual or his/her family. Thus this model believes that the present condition of individual is due to actions committed in previous birth.

Charity Model of Disability: It is a disability model defined and developed by abled people. The charity model of disability believes that disabled people’s life is a tragic one as they

are the victims of circumstance and therefore deserve pity and sympathy. According to the charity model, the non-disabled people are the saviors of disability who are the victims of circumstances. Non-disabled see them as a tragic victim so they need care, sympathy and charity in order to survive. But considering themselves as the recipients of charity to survive, the self-esteem of the disabled is injured.

Medical Model of Disability: This is the basic model out of which the charity model came out as an off-shoot. Based on the medical ground, it defines disability as something in the body of the disabled which can and should be cured. It primarily focuses on impairment. According to this model, disability is an intrinsic condition to the individual. Seen as a moralistic extension of the model, it considers that the medical professionals are the experts in the field of disability. The central focus of this model lies in its location of disability as an individual problem tied to the functional limitations of the bodies of people with impairments. (Swain, French, Cameron, 2003). It is illness which is the part of an individual’s own body which reduces its quality of life on one hand and adds to its disadvantage on the other. It suggests that clinical perspective is required for curing or at least managing disability. This model believes that the challenges associated with the disability are produced by the disabled person itself. It considers disability as a disabled individual centric ‘problem’ and it should not concern anyone but the affected individual. Its nature is deterministic as it says that person having disability cannot be equal to other counterparts, consequently, it reduces the opportunity for persons with disability.

The Social Model of Disability: This model gives an explanation to the myriad experiences of the disabled in the society and thus provides a tool to create a social change. Not basically designed to provide a perfect theory of disability this theory provides an explanation of the experiences of the disabled people in society. Quite a recent conceptualized model, it views persons with special needs and focuses not on disability but on the barriers created by society as the main reason of challenges and problems faced by individual with special needs. It follows

inclusive approach to ensure participation of all, including persons with special need. This model is a radical and pragmatic approach to bring an end to the exclusion of the disabled people and free them of the oppression. The significant part of this model is that it lays stress that even they are also entitled to same rights and opportunities as the non-disabled ones, and there is no need for them to change. The social model endorses barrier free society, which will help enhance the participation of the disabled people in society, and facilitate them to access work and live independently. It highlights the difficulties due to the external factors that the disabled people facing in their daily life. This model has its origin in early eighties and endorsed by World Health organization when the concept of disability was separated from impairment. According to WHO, disability is a blanket term, which has various components: impairments (a problem in body function or structure), activity limitations (a difficulty encountered by a person in executing a task or action) and participation restrictions (a problem experienced by a person in involvement in life situations). It declares that negative attitude, systematic barriers and exclusion by society contributes to pathetic condition of special need individuals. The social model perceives disability as a complex collection of conditions, many of which are created by the social environment (Langtree, 2010). It put emphasis on the concept that those who have created the problem at first, should come forward to fix it. In this case, it is the society, which has created all the barriers for the people with special needs. So now, it is the responsibility of the society to create a barrier free environment, which motivates equal participation from abled as well as disabled section of the society. It stands for the proposition that structural barriers lie at the root of the marginalization of disabled people. (Malhotra and Rowe, 2014). Social Model disability doesn't originate because of single barrier. As per this model, the barrier created by environment, society and attitude, they all create obstruction for the people with impairment from actively participating in the society.

The perspective regarding disabled or disability condition changes from religious model

to social model, their participation in every field of progress changes. Education is the key to any kind of development. It is often regarded as the key to success as well as an empowerment tool for individual as well as society. It provides vision to human beings to think for their well-being and create awareness for their rights. As the time passed by, their ways of participation and access to education also changed. Social model of disability regards learning as a fundamental human right and is committed to provide education in inclusive learning environment. If we look at the development of educational practices for the disabled, we observe that in beginning they were getting education separately. This education system travelled a journey from special schools to inclusive schools. Let us have a look on the journey of educational practices.

Present models of practices: Presently three broader models are practiced specifically for educating the children with special needs. They are as follows:

1. Special Education

The special education is provided in special schools which are generally of residential nature. It is specially designed for special category of students. It assumes that separate group of children as per their special need can only interact with other children of the same category. Special education empowers and enables the teachers, which help them in identifying and focusing on needs of the special children. Therefore, special schools are equipped with the resources that are required as per the needs of the disabled children. The main criticism of this setting is that children are isolated from the mainstream and from their homes, where they could have interacted with their loved ones as well as other abled children of their age group. It is also considered to be an expensive option.

2. Integrated Education

Integrated education came into existence to overcome the limitations and disadvantages of the special schools. It provides same education to all children, irrespective of whether they are disabled or abled. In this model, disabled and



abled children are taught together in some of the classes. In some specific cases where the disabled student is unable to cope up in the regular class or in cases where he/she needs to learn some specific skills like braille writing and reading then they are taught separately. In Integrated education, general teacher teaches persons with special needs with special teacher assistance. Main aim of this education is to help the child develop necessary skills, confidence and self-concepts that are necessary for active participation in mainstream of social life as well as work life.

3. Inclusive Education

Inclusive education means creating an effective education system which caters to the needs of all, irrespective of abilities or disabilities. It assumes the changes that education system must bring to fit the child. If a child is unable to learn, the problem is not with the child, it is the problem of the education system. Here the system should be flexible enough to be changed and modified in order to accommodate the diverse needs of all learners, including children with special needs. It should cater the needs of each individual student and should not be limited to just disability. In inclusive education, there is no provision of separate room or separate classes for children with special needs as we have in integrated education. It is the responsibility of the teachers and schools to take care of children's learning and they are accountable for this. It focuses on flexibility of curriculum, teacher training and changes in educational environment. Inclusive education caters the needs of all the children in a school irrespective of their strengths or weaknesses. It makes them an integral part of the school community.

Endeavors for empowerment of persons with special need in India:

Almost seven decades ago, many determined efforts were made towards the empowerment of persons with special needs. Article 15 states that the state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Article 41 states that the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make

effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved wants. Article 45- Directs the state to provide free and compulsory education for all the children until they attain age of 14 years. Article 46- shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Education is primary mean of empowerment of any individual. The previous article 45 is now substituted as Article 21A. The Article 21A states that "the state shall provide free and compulsory education to all children of the age 6-14 years in such manner as the state may by law determine". Thus, education is to be ensured for all without discrimination. Our constitutional commitments have been reflected through various commissions of education appointed at different points of time. The Kothari Commission (1964-1966) observes that the coveted goal of universalization of Elementary Education (UEE) depends upon the extent of success in bringing special groups of children within the educational network. After Kothari commission, National Policy for Children (1974), National Policy on Education (NPE) (1986), Behr-ul-Islam Committee (1987), Ramamurthy Committee (1991), Program of Action (POA) (1992) are constituted. Besides several commissions, some disability specific acts have been formed to provide education through inclusive schools for children with disabilities, in accordance with the provisions of the Rehabilitation Council of India Act (RCI -1992), Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act (1995), National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (1999), National Curriculum Framework (NCF-2005), Action Plan for Inclusive Education of Children and Youth with Disabilities (2005), National policies on Disabilities (2006). India participated in drafting of the U.N. Convention on the Rights of person with Disabilities (CRPD), signed it on the day it was opened for signature and was among the first seven countries to ratify the convention on 1st October 2007. A flagship

program Sarva Shiksha Abhiyan (SSA- Education for All), was launched in 2001 by Government of India which also made special provision for serving children with special needs. All these Commissions', Acts and policy documents advocate providing educational opportunities for the disabled children in common schools. With all these directives laid down by the Indian Government, it is evident that the education of children with disabilities holds a priority. In The RPWD Act, 2016, the list has been expanded from 7 to 21 conditions and replaced PwD Act 1995 to comply with the UNCRPD. It also includes cerebral palsy, dwarfism, and muscular dystrophy, acid attack victims, hard of hearing, speech and language disability, specific learning disabilities, autism spectrum disorders, chronic neurological disorders such as multiple sclerosis and Parkinson's disease, blood disorders such as hemophilia, thalassemia, and sickle cell anemia, and multiple disabilities. It enhances the horizon of disability conditions in comprehensive ways.

India adopted a new Education Policy in the year 2020. The NEP 2020 has a transformative vision and promises to bring revolutionary changes in life of persons with special need by seeking inclusive and equitable and quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. If this policy is implemented in true sense, it will surely bring a response to the diversity of India and can cater the needs of the diverse population. The biggest victory for disability rights in the NEP is the recognition of the 2016 legislation on disability i.e. The Rights of Persons with Disability Act, 2016 with a strong promise to enforce the legislation. The Act provides for free education to children between six to eighteen years with benchmark disability. It will help in their empowerment. For far too long, the problems of people with disabilities have been compounded by a disabling society that has focused upon their impairments rather than their potential. RPWD Act 2016 and NEP 2020 maintains that disability is socially constructed and shifts the focus away from physiological impairment. This marks a shift in considering

disability as a condition of the individual, to understanding disability as a condition of a society wherein people with impairments are discriminated against, segregated and denied full participative citizenship. It is a shift from 'disabled' being seen as a personal tragedy, to 'disabled' being a positive identity. And it is a shift from dependency and passivity, to the rights of disabled people to control decision making processes that shape their lives. (Swain, French , Cameron, 2003). According to Menzies and Falvey (2008) Inclusive education is now often regarded as a practical outgrowth of the social model of disability. Whereas segregated education was based on the medical model which views disability as a "within- child phenomenon . . . to be treated with special procedures, which are sometimes best implemented in separate placements, in order to remediate the deficit or impairment. It must be emphasized at the end that discrimination is now considered as a basic human rights violation of special need person. Social model of disability has provided significant background for the empowerment of disability. It is an important milestone in the journey of this marginalized section from 'viklang' to 'divyang'.

References

- Langtree, I. (2014). Definitions of The Models of Disability: Brief Synopsis: Glossary list of definitions and explanations of the Models of Disability in society today. Retrieved September 19, 2014, from <http://www.disabled-world.com>
- Malhotra, R and Rowe, M. (2014). Exploring Disability Identity and Disability Rights through
- Narratives, Finding a Voice of Their Own, Routledge
- Menzies, H. and Falvey, M.A. (2008) 'Inclusion of Students with Disabilities in General Education' in T.C. Jiménez and V.L. Graf (eds) Education for All: Critical Issues in the Education of Children and Youth with Disabilities, San Francisco, CA: Jossey-Bass,
- Swain, J., French, S., Cameron, C. (2003) CONTROVERSIAL ISSUES IN A DISABLING SOCIETY, Open University Press, United Kingdom
- World Health Organization. (2014). Disabilities. Retrieved September 18, 2014, from <http://www.who.int/topics/disabilities/en/>



Effectiveness of Various Government's Schemes

Akhilendra Kumar

Disability has become a focused attention in the recent times with the rise in political activism and voluntarism at the international and national level and also increasing debate about the development of 'alternative' service programmes, particularly, community based rehabilitation. The Ministry of Social Justice and Empowerment, GOI is the nodal Ministry for the disability sector under which a new Department has been created as Department of Disability Affairs to give focus on disability issues as well as PWDs for Effectiveness of Schemes and programmes for rehabilitation of persons with disability in a holistic approach with multi-sectoral process, involving a package of services and activities with an allocation of Rs.1171.00 crores in 2021-22.

The most important factor has been a shift in emphasis in policies towards disabled from a welfare and charity approach to that of equalization of rights and opportunities. Importantly, the role of NGO's in disability sector has been found praise worthy while emerging trends and efforts have had a direct impact on the policy makers, persons with disabilities and organizations engage in rehabilitation of disabled persons. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act was enacted in 1995, which was repealed as The Rights of Persons with Disabilities Act 2016, as India is also the signatory of United Nations Convention for Right to Persons with Disabilities (UNCRPD). The Act aims at the elimination of discrimination and the creation of an inclusion in society which provides opportunities for development of

people with disabilities to their fullest potential.

The GOI has introduced many schemes for the development and upliftment of PWDs, some major schemes are being presented here.

The National Handicapped Finance and Development Corporation has been set up to support self employment projects for disabled. Moreover, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act has been passed, which is expected to be instrumental in providing supports and protection to vulnerable sections of disabled population.

As it has been already mentioned that credit for policy shift in disability sector goes to Rehabilitation Council of India, set up in 1993 under a central legislation enacted in 1992. The main purpose of the RCI Act was to regulate and standardize the programmes of training professionals in the disability sector on the lines of professional bodies such as the Medical Council of India and the Bar Council of India. The RCI has ensured the socio-economic empowerment of disabled.

The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), GOI as a registered body was established in 1972 with the aim of providing appliances to the physically handicapped population of the country by manufacturing of Wheel Chairs and Tricycle Aids and Appliances.

About 8000 Institutions are engaged in welfare and rehabilitation. Out of these Institutions, hardly 100 institutions are run by government. About 80% institutions (NGO's)

are located in 8 states. Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Delhi.

It has been the constant endeavour of the GOI and various State governments to achieve Sustainable Development Goals to which India is a signatory and one of the major role player with a pledge to “Leave No One Behind”. United Nations SDGs as per 2030 agenda deal with various aspects related to the upliftment and Empowerment of PWDs.

Accessible India Campaign:

In furtherance of the vision, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities GOI has launched the Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan), as a nationwide flagship campaign for achieving universal accessibility for Persons with Disabilities and to create an enabling and barrier free environment, with a focus on three verticals: built environment; public transportation and information & communication technologies.

Swavalamban Health Insurance Scheme:

The Trust Fund for Empowerment of Persons with Disabilities, under the Department of Empowerment of People with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, has started “Swavalamban Health Insurance Scheme” conceived with the objective of providing affordable Health Insurance to persons with disabilities.

Unique Identity Card For Divyangjan:

Unique ID for Persons with Disabilities” project is being implemented with a view of creating a National Database for PWDs, and to issue a Unique Disability Identity Card to each person with disabilities. The project will not only

encourage transparency, efficiency and ease of delivering the government benefits to the person with disabilities, but also ensure uniformity

Assistance to PwD for Purchase/ Fitting of Aids/ Appliances (ADIP):

The main objective of the Scheme is to provide grants-in-aid to the various implementing agencies (National Institutes/ Composite Regional Centres/Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India(ALIMCO)/ District Disability Rehabilitation Centres/State Handicapped Development Corporations/other local bodies/ NGOs).

Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme:

The Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) includes projects for providing education and vocational training and rehabilitation of persons with disabilities by providing grants in aid to voluntary organizations.

Implementation of the Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act, 1995 (SIPDA):

The grants-in-aid are provided under this Scheme to State Governments and various other bodies, set up by the Central and State Governments, including Autonomous Bodies and Universities, to support activities, pursuant to implementation of the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, particularly relating to rehabilitation and provision of barrier-free access.

Scheme of National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities:

Empowerment of persons with disabilities is an inter-disciplinary process, covering various aspects namely, prevention, early detection, intervention, education, vocational training, rehabilitation and social integration etc.



Scheme of National Scholarships for Persons with Disabilities:

Under the Scheme of National Scholarships for Persons with Disabilities, the following scholarship programmes are being run by GOI:

1. National Fellowship for Students with Disabilities:
2. Pre-Matric Scholarship and Post-Matric Scholarship for Students with Disabilities:
3. National Overseas Scholarship for students with Disabilities:
4. Scholarship for Top Class Education for Students with Disabilities:

Employment To Persons With Disabilities:

The objective of the scheme is to encourage of employment of persons with disabilities in the corporate sector. The scheme of giving incentives to employers for providing employment to persons with disabilities in the private sector was launched in the year 2008-09.

The National Action Plan (NAP) For Skill Training Of Person With Disabilities:

The Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment has launched the National Action Plan for skill training of persons with disabilities, in collaboration with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship on 21st March, 2015.

Uttar Pradesh State Schemes for Persons with Disabilities

The State government has established a separate department for the development of disabled persons in the state. The Empowerment of Persons with Disabilities Department, UP was created in August, 1995 for providing holistic development of destitute and weaker sections of disabled population. There has been more than 6 times increase in the expenditure for empowerment of disabled persons in the state. Empowerment of Persons with Disabilities

Department, Government of Uttar Pradesh has shaped their policies in view of new RPD Act 2016 provisions, providing various schemes and support for social, economical vocational rehabilitation of PWDs with a positive overall impact on their upliftment and Quality of Life to achieve Sustainable Development Goals specially in Aspirational districts chosen by the govt .

The GOUP is operating various schemes and programmes for empowerment and rehabilitation of Persons with Disabilities .The schemes aim to promote physical, psychological, social, educational and economic rehabilitation and development of persons with disabilities to enhance their quality of life and also enable them to lead a life with dignity.

U.P. Govt. is the first State to implement the RPD Act, 2016 with their new rules. In order to provide the PWDs various support and facilities the GOUP framed new schemes & programmes with new increased budget Allocation. In the CENSUS 2011 there were only 07 major disabilities and according to which 41,57,514 PWDs were surveyed in UP. With the new RPD Act, 2016 the Disabilities are now increased to 21 types of which till now there is no survey of the population of the PWDs.

The GOUP first of all changed the name of the Department from Viklang Jan Vikas Vibhag to Empowerment of Person with Disabilities Department in English & Divyang Jan Sashakti karan Vibhag in Hindi since 26.04.2017 to boost the moral PWDs and aware the society about their existence.

1. Helpline Number: To increase the speedy delivery of different services to PWDs the department started a Help Line No.1800-180-1995 on 12.05.2017 so that PWDs may be able to inform the grievances and problems they are facing as well as to gather the information about their schemes. At present 500 complaints are attended daily to provide the relief and services .

2. **Increase in Budget Allocation:** The GOUP increased the budgetary allocation from Rs.660 Crores which was in 2016-17 to Rs. 1095 Crores in 2020-21. This increase is 66 % in comparison to the previous allocations which shows the commitment of GOUP to speedup the development of PWDs in their well being and saturate large number of PWDs all over the state.
3. **State Disability Pension:** The disability pension called as “Sustenance allowance” is given to people with disability and it is Fusion of state as well as Indira Gandhi National Disability Pension scheme. The monthly amount of the pension was increased from Rs 300 to Rs.500 per month from 6 June 2017. The amount is credited into the saving bank account of the applicant. The payment is done in every three months to 11,02,028 pensioners at present in comparison to 8,75,992 of 2016-17 . This way directly 2,26,036 new pensioners are benefitted with this scheme which is directly attached to their economic upliftment. An allocation of Rs.62,102.00 lakh was spent in 2020-21 for the benefit of divyangjan.
The GOUP has given the facility to apply for pension through online application due to which PWDs residing in remote areas and villages are able to apply for pension easily e-suvidha kendras near their villages.
Under the Pradhan Mantri Kalyan Package a sum of Rs. 1000/- is being awarded to disabled people apart from their monthly pension.
4. **Leprosy Pension:** The GOUP have started this new scheme in 2016-17 to give the benefits to Leprosy Cured Persons who are certified as PWDs. The amount of pension is Rs. 2500/- per month was started in 2016-17 giving to 4765 PWDs is now increased to 11,170 in 2020-21. This way 6,450 new Leprosy Cured Persons are being benefitted at present and this amount directly has a effect on their livelihood . Allocation of Rs. 39.00 crores is done in 2021-22.
5. **Bus Concession:** This is to facilitate outdoor mobility of the disabled persons. Any disabled person having 40 percent disability with any income or of any age can travel free in the buses run by the UP State Roadways Transport Corporation up to the last stoppage of that bus irrespective of the limits of out of state. GOUP has reimbursed the expenditure borne by the UP State Roadways Transport Corporation of Rs. 135.26 Crores from 2017-18 to 2020-21. Allocation of 20.00 crores is earmarked in 2021-22 .
6. **Incentive Award for Marriage between Disabled and Non-Disabled :** The primary aim of this scheme is to facilitate disabled persons to get married for leading a better and happy life in the society. The amount of incentive award is Rs.20,000/- in the case of female partner and if both the spouse being disabled amount will be given Rs. 35,000. But if only male partner is disabled then the amount is Rs.15,000/- .From 2017-18 to 2020-21, more than 3,327 couples are benefitted under this scheme to lead a happy prosperous life in the society. Allocation of Rs. 26.40 crores was done in 2020-21 .
7. **Cochlear Implant Surgery:** This new scheme was started in 2017-18 to benefit the Hearing Impaired Children up to 06 years of age for surgery with Rs. 6 Lakh per beneficiary. 88 Hearing Impaired CWDs are benefitted from 2017-18 to 2019-20 who are now can hear and speak to lead a Quality of Life.
8. **Artificial Limbs & Assistive Devices:** Under this scheme the Artificial Limbs & Assistive Devices costing Rs.10,000 is being given. A total of 1,76,424 PWDs have been benefitted to lead quality of life because their mobility has been increased to do their Job , Health,& Education. Allocation of Rs. 37.40 crores was in 2020-21.
9. **Corrective Surgery Scheme:** To perform 21 types of different surgeries GOUP has earmarked Rs. 10,000 per person since 6



July 2017. A total of 1326 PWDs are benefited with surgeries between 2017-18 to 2019-20 by which they are now leading a normal life.

10. Motorized Tricycle Scheme: The GOUP has started the new scheme in 2020 with the objective of increase their mobility specially students for going to their institutions for education but the beneficiary shall be having 80 percent or more disability and their yearly income must be below 1,80,000.
11. State Fund for PWDs: The GOUP has become the first state in India to implement the various provisions of Right to Person with Disability Act 2016. Under this new act the GOUP has established State Fund for PWDs with a allocation of Rs. 15 crores.
12. State Award: The GOUP every year on 03 December World Disability Day in provisions of RPWD Act 2016 12 types of Disabilities with 30 sub types Disabilities are notified for the State Award of Rs.25,000. 84 persons / institutions have been awarded State Award since 2017.
13. Bachpan Day Care Center: The State Govt. has established Bachpan Day Care Centers in 18 divisional headquarters to provide pre primary education to Mentally Retarded/ Hearing Impaired/ Visually Impaired CWDs in the age group of 03-07 years under one umbrella. Free uniforms, school books, bag, transportation and mid-day meal is being given to CWDs. The result of this scheme is found to be very appreciative so it has been decided by the GOUP to increase the centers in 07 districts in 2019-20.
14. Govt. Braille Press: The GOUP as established a Govt. Braille Press to produce Braille books on various subjects for the education of Visually Impaired students all over the state studying in different institutions. The GOI has also awarded National Award to this press.
15. National Awards to GOUP : The Govt. of India has recognized the various Affective

interventions and steps taken by GOUP under holistic approach to give benefits to PWDs. Seeing the Effectiveness of various schemes the GOI has awarded National Award to Department of Empowerment of PWDs,UP for implementing the various rehabilitation programmes for PWDs with good impact and feed back for district Lucknow on 03 December 2018, National Award for making Barrier Free Website www.uphwd.gov.in for the use of PWDs on 03 December 2019, National Award for district Varanasi on 03 December 2019 for implementing different rehabilitation programmes, National Award to GOUP for implementing Sugamya Bharat Abhiyan of GOI in the state of UP.

16. Awareness Programmes: The Department of Empowerment for PWDs with a objective to aware the PWDs residing in far flung areas, villages and remote areas started its advertisement jingles in different FM Radio Channels, playing Nukkad Natak and Hoardings in different places with an expenditure of Rs. 35 lakhs. This programme was a great success and gave impetus to the campaign with the result the numbers of beneficiaries increased in all the schemes which reflects the effectiveness of different schemes of the State Govt.
17. Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University: GOUP has established this university in 2008 with an estimated expenditure of more than Rs. 800 crores in a 131 acres Barrier Free Campus to impart education specially to students with disabilities for which 50 percent seats are reserved for them and 50 percent seats are for normal students in all the 09 faculties and 29 departments. The GOI Awarded National Award to University being totally Barrier Free Campus. The disabled students are being given free education, free hostel and free mess facilities. Apart from normal stream education special emphasis is on Law, Management, Engineering, Rehabilitation

courses like BPOE, BASLP, PDCD, M.Ed, B.Ed, D.Ed in Special Education respectively.

As a Rehabilitation University it has focussed on A Paralympic Stadium of international standard for disabled students, Artificial Limb and Assistive Devices Centre to impart free devices to disabled people. A college for Deaf studies with the matching grant of GOI is being established to start new courses for deaf students. An allocation of Rs.33.50 crores is done for 2021-22.

The GOUP is the only state in India which has focussed on the Education of PWDs from pre-primary to higher education totally free, in an inclusive environment. As mentioned above at pre primary level Bachpan Day Care centres, from primary to secondary level special schools upto intermediate for blind students, at high school level special schools for Hearing Impaired and Physically Impaired students are being run. Special schools for Mental Retarded students are also being run in which Pre Vocational and Vocational classes are held apart from Sheltered Homes and Vocational Training Centres for Mental Retarded Persons also.

18. Samekit Vishesh Madhyamik Vidyalaya : These special schools are one of its kind in India with an inclusive environment totally Barrier Free from class 6 to 12 standard are being established in a phased manner in 12 districts at present, in which fifty percent students will be normal students as well as fifty percent will be disabled students in every standard to impart special and normal education.

We can see how UP govt has undertaken the Education Sector as a priority for PWDs because literacy is the backbone of development, knowledge and wisdom.

On other hand the GOUP govt prioritised its focus on Health sector as well by establishing up a psychological development centre, Manovikas Kendra at BRD Medical College, Gorakhpur for rehabilitation of Japanese Encephalitis affected

children in the most backward areas in eastern belt of the state. Manovikas Kendra at Gorakhpur for the Children with Disabilities specially affected by Japanese Encephalitis offers a slew of services like IQ assesment,audiology,speech therapy, physiotherapy ,occupational therapy,vocational skills.

UP SpinalCord Injuries Centre at Bareilly, with a matching grant from GOI was set up to cater medical aid and other para medical facilities with diagnostic centre for the patients of trauma and accidents on highways. Scheme for Cochlear Implant Surgeries @ Rs. 6 lakhs for the CWDs who are hearing impaired in the age group of 1 to 5 years free of cost.

Scheme for Corrective Surgeries of 21 types of surgeries required for disabled people is being run in different districts of the state to reduce the disabilities occurred and rehab services to provide mobility and quality of life.

A State Referral Centre in Dr.Ram Manohar Lohia Hospital,Lucknow has been set up with the help of GOI to cater services for the disabled people referred from all over the state for various medical and rehabilitation serviceslike IQ assesments, Speech and Hearing assesments, Physio and Occupational therapies with medical diagnostic interventions..

The GOUP also started giving benefits to PWDs in providing jobs in all categories of services by identifying numerous posts on which PWDs can perform their duties in all the govt departments for which a special campaign for recruitment of PWDs held with nominating Specialists of the disability sector as members of the selection committees with help of Employment Department, UP.More than 3500 eligible disabled persons of different disabilities were given govt jobs under the special drive. PWDs are also being given conveyance allowance for reaching their establishments to perform the duties.

The Rural Development Department, UP is providing Indira Awas to PWDs in rural areas whereas The Urban Development Deptt, UP is



providing houses under DUDA in urban areas for rehabilitation .

The Stamp and Registration Deptt, UP is giving cocessions upto Rs. 10 lakhs in purchase of land by PWDs as a exemption in stamp duty.

The Civil And Supplies Deptt,UP is awarding shops for distribution of ration to PWDs.

All the Development Authorities and Awas Vikas Housing Board have reserved plots and houses for the PWDs on priority basis with special care to allot them on the ground floor so they may not face infrastructural barriers.

Health Deptt ,UP is providing free medical facilities all over the state and screening og disabilities at early stage with Disability Certificate to PWDs.

Education Deptt, UP Basic Education, Madhyamik and Higher Education are imparting free education to CWDs under Sarva Shiksha Abhiyan,Madhyamik Shiksha Abhiyan,and Uchha Shiksha Abhiyan.

CONCLUSION

As of now a holistic approach has been the backbone of success in all the spheres of PWDs in leading a Quality of Life. The analysis of physical and financial performance of various programmes and schemes shows that there has been remarkable progress in Empowerment of Persons with Disabilities. However, there is dearth of funds and inadequate coverage of various schemes due to large number of disabled population in 75 districts of the state.

Though the intention of the GOUP reflects its dedication and commitment towards the development of PWDs still we see a large gap

in delivery of services to saturate the number of PWDs identified by Chief Medical Officers in different districts due to the paucity of funds under various schemes. The large number of applications of Persons with Disabilities for various services shall be timely processed and forwarded to the concerned authorities for availing benefits under various educational and social development schemes for their better Inclusion and Quality of Life achieving the Sustainable Development Goals. .

REFERENCES

- The Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016
- Annual Report of Empowerment of Persons with Disabilities Department,Govt of UP .
- Website www.uphwd.gov.in
- United Nations Convention for Right to Persons with Disabilities (UNCRPD)
- United Nations SDGs
- Department of Disability Affairs

ABBREVIATIONS

- PWD: Person with Disability
- CWD: Children with Disability
- GOI: Govt of India
- GOUP: Govt of UP
- SDG: Sustainable Development Goals
- BPOE: Bachelor in Prosthetic and Orthotic Engineering
- BASLP: Bachelor In Audiology Speech Language Pathology
- PDCD: Pre Degree Certificate Course for Deaf Students
- M.Ed: Masters in Education
- B.Ed: Bachelor in Education
- D.Ed: Diploma in Education

केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम के माध्यम से पुनर्वासित करने का प्रयास किया जा रहा है इनसे संबंधित निम्नलिखित योजनाएं हैं:

क्र.स.	योजना	उद्देश्य / लाभार्थी	संपर्क संस्थान
1	दिव्यांगों के लिए सहायक फिटिंग के द्वारा सहायता (एडिप संसोधनोपरांत) 01/04/2014 – 31/03/2020)	उपकरण – सहायक उपकरणों के द्वारा दिव्यांगों को मानसिक स्वच्छंदता, गुणात्मकपूर्वक, कार्य-निपुणता के साथ कार्य सफलता के साथ बाधा-रहित जीवकोपार्जन कर सके।	अर्टिफिशियल लिंब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को)
2	मोटोराइज्ड, ट्राई –साइकिल (एडिप योजना)	क्वाड्रीप्लॉजिक, मस्क्युलर डिस्ट्रोफी स्ट्रोक प्रमस्तिक धात, पक्षाघात, बहु दिव्यांग एवं आधा शरीर दिव्यांग।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
3	एडिप योजना योजना के अंतर्गत (क) दृष्टि दिव्यांग (ख) श्रवण बाधित	– डाइस प्रूफ प्लेस बुक प्लेयर एवं अन्य टॉकिंग डेविस, नोटबुक, लैपटॉप, डिजिटल-मैग्निफाएर – सहायक यंत्र / उपकरण फिटमेंट	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
4	वित्तीय सहायता बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगजनों हेतु	– डेजीफ प्लेयर, नोटबुक लैपटॉप, डिजिटल मैग्निफाएर, टी. एल. एम. टी किट (शिक्षण एवं पाठ्य सामग्री) – एलिम्को मॉडल संवेदन किट रु बौद्धिक एवं विकासात्मक रूप से दिव्यांगजनों के लिए।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
5	कुष्ठ प्रभावितजनों के लिए सहायक उपकरण, वित्तीय सहायता	– आधुनिक सहायता उपकरण – वित्तीय सहायता (पेंशन)	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
6	सहायक उपकरण / अनुमोदित सहायक यंत्र	– अस्थि दिव्यांगजनो हेतु अनुमोदित सहायक यंत्रो / उपकरणों की खरीद / फिटिंग वित्तीय हेतु सहायता योजना	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
7	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सहायता	– राष्ट्रीय दिव्यांग (14/04/2018) – अन्य गतिविधियों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान – पेंटिंग, हस्तशिल्प, शौर्य कार्यशाला द्वारा।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
8	दिव्यांग व्यक्तियों (सामान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण अधिकार अधिनियम 1945 (सिपडा)	– वित्तीय सहायता, अवरोध मुक्त पुनर्वास, प्रावधान, कौशल विकास कार्यक्रम, सर्वव्यापी सुलभता।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली



क्र.स.	योजना	उद्देश्य / लाभार्थी	संपर्क संस्थान
9	दिव्यांगजनों के अधिकारों के कार्यालयन के लिए योजना	— बाधा मुक्त, वातावरण शोषित स्थान, सार्व. जानिक कार्यालयों, सार्वजानिक बाधा, मनोरंजन क्षेत्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि ।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
10	केंद्रीय क्षेत्रक योजना (ब्रेल प्रेस स्थापना / आधुनिकीकरण) दिव्यांगजन अधिनियम कार्यक्रम के लिए योजना (सिपडा)	— नयी ब्रेल प्रेस की स्थापना, आधुनिकीकरण गैर आवर्ती अनुदान, संघ शासित प्रदेश में छोटे स्तर से ब्रेल प्रेस की स्थापना ।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
11	सुगम्य भारत अभियान :- राष्ट्र व्यापी अभियान (03/12/2015)	— सुलभ भवनों के अनुसार की वृद्धि करवाना — परिवाहन की सुलभता — हवाई जहाज वायुयानों में वृद्धि — रेल एवं रेलवे स्टेशनो पर सुलभता — सुचना एवं संचार, एको-सिस्टम अभिगम्यता — संकेत दु-भाषियो / भाषाइयो को बढ़ाना — निर्मित वातावरण (आई.सी.टी.पारिस्थ. तिकी)	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
12	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू. डी. आई. डी. कार्ड / स्वालम्बन कार्ड)	— राष्ट्रीय डेटाबेस, दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आई. डी. पारदर्शिता, क्षमता सर. कारी योजनाओं का लाभ सामान्य रूप से मिले, अंतिम दिव्यांग तक लाभ, सप्रसंग प्रत्यक्ष प्रणाली की स्थापना ।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
13	क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटर. रनेशनल सेंटर स्थापित । (डी. ई. पी. डब्ल्यू. डी. के अंतर्गत) (राष्ट्रीय संस्थानों)	राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरनेशनल सेंटर (डी. ई. पी. डब्ल्यू. डी.) की स्थापना, अतिरिक्त प्रसांगिक मामलों एवं वित्तीय सहायता प्रदान जाँच, पहचान, सेवायें, परामर्श ।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
14	कौशल प्रशिक्षण दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	दिव्यांगजन विकास की तलाश में, रोजगार योग्य कौशल, यू.ए.सी.आर.पी.डी, अधिकारिता, प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रमाणन इकाई, नौकरी सृजन ।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
15	जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना (अवेयरनेस जेनरेशन एंड पब्लिसिटी स्कीम योजना-2014)	सहायता के लिए स्वीकार्य घटक, दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन कॉउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन, योजना से सम्बंधित सहायता, अनुदान वित्तीय सहायता ।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली
16	प्रौद्योगिकी, उत्पादों एवं मुद्दों पर अनुसंधान नामक योजना (अनुसंधान और विकास) जनवरी-2015	दिव्यांगता दर में कमी, प्रमुख सहायक उपकरणों को अनुप्रयोग को बढ़ावा देना ।	दिव्यांगजन विभाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली

Higher Education Policies in India for Persons with Disabilities: Building an Inclusive Ecosystem in Higher Education Institutions

Dr. Prithviraj Singh Chauhan

The rights of person with disability to pursue higher education have been adversely marred due to the lack of sound policies and legal provisions in acts and policies. Acts and policies are much focused on the school education only and the problem faced by PWD in higher education has not been addressed in these acts. The present study attempts to provide insights on the gaps between the available policies for the persons with disabilities and their impact in promotion of higher education. Study critically analyses the available policies in higher education for the disabled followed by suggestions for their improvement. Inclusive ecosystem can be built by providing adequate financial support for infrastructure augmentation, bringing awareness through higher educational institutions, by making provisions for study of disability issues as a part of general curriculum of higher education. Providing training to the teachers before they join services and establishing the centre of disability studies in every universities are some major suggestions to improve could the participation of PWD in higher education.

Introduction:

The concept of disability has been constructed in opposition of ability wherein the abilities of some individuals to perform day to day activities in a way, considered normal are adversely affected due to some biological or medical conditions. Disability of a person makes him/her unsuitable to accommodate in the system, developed to serve the normal people. Due to

different behavioural practices and requirements a Person with Disability (PWD) could not access the environment. Disability is a dynamic concept which cannot be delimited to the individual's body only as suitable conditions are primary requisite for an individual to grow with any kind of bodily difference. "Disability is any condition of the body or mind (impairment) that makes it more difficult for the person with the condition to do certain activities (activity limitation) and interact with the world around them..." (Centre for Disease Control, 2020). United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) has included every kind of impairment under the domain of disability. Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. (UNCRPD, 2006). India being the signatory of CRPD has prepared The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 in line of U N convention and defines person with disability as " a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others;" (RPWD Act. 2016, p. 03). As per census of 2011, 26.8 million people of India is living with some or other kind of disability which constitute 2.21% of total population and this number could be higher as the reported number is based on the standard definition of disabilities as per PWD Act 1995.



Participation of the disabled in economy is negligible due to the lack of education and training. Education is the master key to bring them in the main stream of society but the situation is really dismal for disabled community, as per census of 2011 only “5% are graduates and above.” (Persons with Disabilities Statistical, 2021 p. 33). Number is significantly low to its relative population. India has made considerable progress in the upliftment of PWD by adopting suitable policies and infrastructure but the onus of providing the infrastructure and support primarily lies on the governments only. Participation of community and other sectors are still negligible due to the lack of sensitivity and awareness. Due to the lack of awareness and community support, enrolment of disabled population in institutes of higher education is very low. The small number of enrolment in higher education highlights the need of examination of available public policies in reference to their contribution in building inclusive ecosystem for disabled in higher education.

Study Area:

Present work focuses on the public policy of the Government of India issued time to time for the welfare and management of the life of the disabled. Study is limited to the acts, rules and provisions constructed to facilitate higher education of disabled population in India. Study critically examines the available policies of higher education for the disabled and identifies the gaps between policies in force and their outcomes to identify the cracks need to be filled for building inclusive atmosphere to improve the enrolment ratio of disabled in higher education.

Methodology and Material:

Qualitative analysis method has been used to examine the policies for higher education of Government of India. The method is used to critically assess the impact of the acts, and policies provisions, being administered to provide higher education to person with disability. Since proposed research work deals with higher education, so regulations, rules, guidelines and

policies issued through regulatory bodies of higher education like U.G.C., A.I.C.T.E. and NCTE etc. are also studied along with acts, policies of Government of India.

Primary objective of the work is to identify the grey areas, need to be addressed through policy change and adoption of suitable measures for building an inclusive system of higher education for person with disability. Public policy documents available in public domain have been used as a source of information for the study.

Policy Provisions for Higher Education for Person with Disability:

- I. The Constitution of India treats persons with disability at par with other citizens, and without any prejudice, guarantees them all the rights available under. Article 15 of constitution prohibits the state not to discriminate against any citizen on the basis of grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them and Article 15 (2) specifically mentions that no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition can be denied access to public places. Article 45 has provision of providing free and compulsory education to all children including children with disability up to the age of fourteen years. (The Constitution of India, 2020)
- II. National Policy on Education 1986 has detailed plan for inclusion of disabled children in the main stream of school education and provisions to open special school, train teachers and provide adequate funds to empower them but the reach of all the provisions does not go beyond the school education (National Policy, 1998). However the need has been felt to provide vocational training to disabled students so Programme on Action Report for National Policy on Education 1986 proposed that “Centres for vocational training of the handicapped will be set up in institutions like special institutes of relevant/useful Technology, District Vocational Training

Centers, ITIs and Polytechnics to equip this section of the society with appropriate employable skills” (Programme of Action 1992, p. 40). Report recommends grant of sufficient fund for facilitation of technical education for disabled.

- III. Rehabilitation Council of India Act, 1992 as amended in 2000, empowers Rehabilitation Council of India to act as a regulatory and supervisory body to formalize services, provided to persons with disability. RCI controls entire ecosystem available to provide services for person with disability. Its function involves recognizing programmes offered by institutions of higher education, preparing professionals/service providers for PWD, development of resource material for education of disabled students, promotion inclusion of disabled in all policies and facilitating training of disabled by providing necessary support. RCI takes necessary steps to facilitate education and inclusion of disabled in main stream of society. RCI has done commendable service in development of human resource to provide service for persons with disability along with development of resources and study materials in accessible formats. RCI also provides financial assistance to different stake holders for promotion of disability issues. (RCI Act, 1992)
- IV. Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, Under article 26 (a) obligate appropriate government to ensure that every child with a disability has access to free education in an appropriate environment till he attains the age of eighteen years. Article 27 (d) contains provisions about imparting education through open schools or open universities. Under Articles 30, 30(b) and 30(f) appropriate governments were directed to prepare comprehensive plan for education by removing architectural barriers from schools, colleges or other institutions, imparting vocational and professional training and suitable modification in the

examination system to eliminate purely mathematical questions for the benefit of blind students and students with low vision. (PWD Act, 1995). The act does not have much to say about the transactional aspect of higher education and only focuses on removing the architectural barriers along with examination reform for blind students.

- V. The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 was enacted to empower the persons with disabilities and insure their inclusion in community and society. Its thrust areas are to deal with problems of persons with disability who do not have family support and making a policy for providing guardianship and facilitation of the realization of right of person with disability.
- VI. National Policy for Persons with Disabilities 2006, in its policy statement it states ‘The National Policy recognizes that Persons with Disabilities are valuable human resource for the country and seeks to create an environment that provides them equal opportunities, protection of their rights and full participation in society’ (NPPD, 2006). Government identifies education for person with disabilities as an area of intervention in the policy and affirmed that ‘It will be ensured that every child with disability has access to appropriate pre-school, primary and secondary level education by 2020, (NPPD, 2006). Large scale reforms ranging from development of inclusive and accessible infrastructure, change in curriculum, pedagogical reforms to social awareness campaign and counseling of stake holders to bring the disabled student in periphery of schools were envisioned, but the focus of NPPD 2006 is limited to school education and it only provisions that ‘Persons with disabilities will be provided access to the Universities, technical institutions and other institutions of higher learning to pursue higher and professional courses (NPPD, 2006)



VII. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 u/s 16 obligates that 'appropriate Government and the local authorities shall endeavor that all educational institutions funded or recognised by them provide inclusive education to the children with disabilities....' In order to accommodate children with disability reasonable accommodation to individual's requirement will be provided to maximise academic and social development consistent with the goal of full inclusion. Premises of such institutions will made accessible and facilitate education in appropriate language and medium to deaf and blind students. Transportation facility and monitoring will be responsibility of state to monitor participation, progress in terms of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability. U/s 17 of act, it is provisioned that training would be provided to teachers and staff to support PWD at all levels of school education and books and assistive devices for free of cost to the students with benchmark disabilities up to the age of eighteen years will be provide (RPWD Act, 2016).

VIII. University Grant Commission in order to support universities for building necessary infrastructure for inclusive education for empowerment of persons with disability, started two schemes of financial assistance i.e. Teacher Preparation in Special Education (TEPSE) and Higher Education for Persons with Special Needs (Differently-abled Persons) (HEPSN). Teacher Preparation in Special Education (TEPSE) scheme launched to start B.Ed. and M.Ed. degree courses with specialization in one of the disability areas to train teachers in order to teach children with disability while Higher Education for Persons with Special Needs (HEPSN) Scheme has three major components:

- I. Establishment of Enabling Units for differently-abled persons.
- II. Providing Access to Differently-abled persons.

III. Providing Special Equipment to augment Educational Services for Differently-abled Persons.

Enabling unit for differently abled persons conceived to act as a supporting unit to assist students in their need during their course of study and securing employment after study. The unit will also sensitize other stake holders about the need of differently abled students. Components II & III have provisions for financial assistance to institutions of higher education for building barrier free infrastructure and ensuring availability of assistive devices for students (UGC Guidelines 2012). UGC has extended facility of cassettes recording for blind students of universities, vide its order no No.F.15-3/80 (CP) dt.23.04.1980 and mandated 3% reservation of seats in admission for person with disability vide its order no No.F.6-1/2002 (CPP II) Vol. II dt. 21.10.2005/1.11.2005. Five percent relaxation of marks at Master Level has been provided to PWD for appearing in N.E.T./J.R.F exams vide its order No.F.6-1/2002 (CPP-II) dt. 5.06.2002. Relaxation up to five years in upper age limit has been provided in admission to various courses, vide its order no. No.F.6-1/2002 (CPP II) Vol. III dt.02.08.2006. U.G.C. has directed universities vide its order no. F.6-1/2006 (CPP-II) dt.29/30.9.2008 to establish Department of Disabilities Studies in universities. Order no. F. No.6-21201 3(SCT) dt. 14.01.2019 of UGC directs universities to uniformly follow guidelines for exam issued by Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, New Delhi for easy access to the examination system to ease the burden of disabled students.

IX. AICTE has issued direction to institutions to follow, implement guidelines issued by the Government of India to build barrier free environment in institutions. It has collaborated with various organizations to develop manuals like Design Manual for a

Barrier Free Environment in Universities/ Colleges for All India Council for Technical Education (AICTE) on the different areas of intervention for person with disabilities. AICTE provides SAKSHAM scholarship for especially abled students to pursue higher education and organizes awareness programs to sensitize the stake holders to build inclusive atmosphere in institutions. Supernumerary seats (25 Nos.) are sanctioned by the Council, for the Institutions falling under the Centrally Supported Scheme Upgrading existing Polytechnics to integrate Persons with Disability (PwD) to bring disabled students in the mainstream of Technical and Vocational Education (AICTE, Approval Process Handbook 2020-21 p.107). Council has included the components of architectural design as an elective course named as Barrier-Free Architecture (AICTE, Model 2019, p.131) that addresses the issues of disability and accessibility. Providing barrier free built environment for disabled and elderly persons has been made essential requirement for approval of institution.

Identifying Gaps in Policy for Higher Education for Person with Disability:

After the thorough analysis of the policies, guidelines and provisions for higher education of government and the associated regulatory bodies, gaps have been found in three major areas viz. 1. Rights and legal obligation 2. Accessible Infrastructure policies and 3. Design for curricular design and material.

- I. Rights and legal obligations- Right to Education is a fundamental right and it empowers every child including child with disability to ask the state to fulfill its duties of providing education but it is limited to school education only. During the study it has been observed that legal rights and provision did not mature beyond school education. Acts and policies have sections for higher education but such sections are not framed in a powerful way and leave onus of interpretation of them on stake

holders. RCI act primarily focuses on the training and education of service providers. Its authority is limited to recognizing programmes dealing in special education. It cannot mandate any institutions to start programmes for PWD students. PWD Act 1995 obligates appropriate government to provide free education to disabled students till the age of 18 years and it also suggested to build accessible infrastructure in university and other institutions. NPPD has targeted to provide education up to secondary level till 2020 and RPWD Act 2016 obligates governments to provide accessible atmosphere and inclusive education to children with disability. It does not emphasize on the higher education for persons with disability. UGC has started two schemes under the plan for institutions; to provide financial assistance and to build infrastructure for inclusive education but these schemes are not binding in nature. They are voluntary schemes and due to lack of interest and obligatory provision in law. These schemes have failed to make any impact on education system. Only few institutions availed these schemes. UGC has given reservation and relaxation to disabled students and issued guidelines to reform of the examination system but it failed to make any substantial change in situation. In a survey conducted by National Centre for Promotion of Employment of Disabled People it is found that "About 0.56% seats in higher education go to disabled candidates though there's reservation to the extent of 3% in public institutions" (Disabled Get, Times of India, 2015). AICTE has done its part by providing additional seats and scholarships. It is clearly perceptible that there are no sanctioned rights available for higher education for PWD. Most of the acts are silent on higher education. In absence of any sound legal framework, how a PWD can demand their rights from institutions of higher education.

- II. Policies for Accessible Infrastructure- Provisions for development of accessible



infrastructure exist in all the policy documents and acts. RPWD Act 2016 obligates to provide reasonable accommodation for PWD. The term reasonable is ambiguous and open for multiple interpretations. It is observed that there is no dearth of provision for building infrastructure for inclusion of disable students in higher education but at the ground level these provisions are not implemented due to the lack of state apathy and in the absence of a robust policy. These acts and provision are not very emphatic to get these problems addressed. Wherever such infrastructure is available but that is not in good working condition.

- III. Policy for Curriculum Design and Material – As for as curriculum for specialised programmes recognized by RCI is concerned there is no need of intervention. RCI is taking good care of such curriculum. After examination of acts, policies and guidelines it is found that disabilities issues are yet to find a place in general curriculum of different disciplines. There is no policy in place to prescribe disability components for all programmes and students. Neither UGC nor AICTE has included disabilities studies component in their model curriculum of different disciplines. AICTE has only one elective paper in B.Arch. and UGC does not even have such component. In absence of curriculum related to problems of persons with disabilities, common students cannot be made aware about their problems. A common citizen does not study anything about the disability as a part of higher education. Since RCI designs curriculum with specific need to train teachers and professional and its prime focus is training, not awareness. Policy to include disability study components in general curriculum of all discipline is the need of hour. Policy to provide material in accessible format is in place but it does not fix the responsibility of stake holders and therefore failed to lead to meaningful outcomes.

Suggestions for Building Inclusive Ecosystem in Higher Education Institutions:

Recognizing that disability is an evolving concept ((UNCRPD, 2006).), requires careful policy planning to remove attitudinal and environmental barriers for inclusion of PWD. Person with disability belongs to Socio-Economically Disadvantaged Groups must be given special rights to improve their participation in higher education. Following measures have been devised after careful analyses of available policies.

- I. Sound Legal Frame Work- Formulate separate act for higher education for person with disabilities to govern entire education system. The proposed act should have detailed coverage of components of higher education only. Acts in force are not very emphatic to address the issue. Ambiguous nature of acts leave space to evade responsibilities. Detailed rules and regulation with appropriate clause for punishment need to be administered. Mixing of issue of higher education under the garb of inclusive education of other Socio-Economically Disadvantaged Groups make disabled doubly marginalized as the problems of PWDs are not similar to other marginal groups. Special attention need to be given to the problem of disabled in higher education.
- II. Curriculum- Only teaching disability studies to the teacher trainee and other service provider is not sufficient to bring PWD in main stream of societies. Disabilities studies should not be limited to specific discipline only as India has a very large number of population of PWD and the number of students opting for disabilities studies is very low, as per the AISHE survey 2018-19 there are 290 students enrolled in disabilities studies programmes offered at the P.G., M.Phil and Ph.D level in India (AISHE, 2019, T-13). Disabilities issues should be an integral part of general curriculum of all disciplines irrespective of specialization to make generations aware about their problems faced by PWD then only the target of inclusion of PWD could be achieved. Specialised training is not

required for every student but teaching theoretical components of disabilities will bring awareness among them. Awareness is the key of empowerment and this goal can be achieved by inclusion of components of disability studies in general curriculum of all discipline. RCI should facilitate curriculum planning related to disabilities issues for general and professional education through its expert committees. The component of disability in curriculum should be not elective or optional; it should be binding to the universities.

III. Funding- Funding is another crucial issue in inclusion of PWD in higher education. Most of the government supported institutions do not have adequate funds to facilitate infrastructural requirement of PWD. Adequate funding should be made available to institutions. Such funds should not be wasted by doing customary facilitation like preparing ramps and lifts only. Every institution should take action as per the requirement of PWD specific area, for this district level data of disabled population should be used to identify marker of facilitation.

IV. University Level Resource Centre- Though U.G.C has already issued guidelines to establish enabling unit in universities under XII plan but little has been done by universities. Even U.G.C. has not done much in this field and involved in a customary facilitation of inclusive education. Annual report 2018-19 of U.G.C. mention that "An amount of Rs. 0.88 lakh has been released to Five Centers during 2018-19"(UGC Annual Report 2018-19,p. 281) to establish Equal Opportunity Cells in Universities. Such meager amount is not going to make any difference in the system. The said report of 2018-19 does not mention number of cells established in universities. One can easily imagine the priority of U.G.C. Resource centre in each university should be established with adequate fund and technology and the reach of the centre should not be limited to that university

campus only. All the affiliated institutions should collaborate with centre in case of affiliating university. Assistive device and resources should be shared between the institutions as per the need of students. It will reduce the burden of opening centers in each college and it can minimize wastage of resources.

V. Compulsory Disability Cell- U.G.C. vide its order no. No.F.6-1/2018 dated 11.1.2019 in compliance of Supreme Court judgment in WP (C) No. 292 of 2006 dated 15/12/2017 has already issued instruction to establish Internal committee of teachers, staff, students and parents in institutions of higher education to look after day to day activity requirement and explore possibilities of improvement in future. It is a welcoming step but proper monitoring of formation and functioning of the committees should be a regular exercise to promote inclusive education. Formation of such committee/cell should be compulsory for every institution. Audit of the work done by such committees/cell should be done by disability commissioner.

VI. Students Volunteers Programme- Students volunteer programmes should be a part of institutional frame work. A volunteer group should be prepared and trained in the beginning of the session to work along with disability cell/internal committee. National Service Scheme of institutions should be given responsibility of conducting the area specific survey and database of such survey should be maintained.

VII. Collaboration with Schools and Data Sharing- District educational administration should collect the data of disabled students from school and this data should be shared with every institutions of higher education of that area. Institutes should use this data to target schools to conduct awareness programmes to promote students to pursue higher education and understanding area specific problems related to students with disabilities. Universities should collaborate



with schools for collection of the data and providing necessary training to teaching and non teaching staff of schools.

VII. Training to Newly Appointed Faculty - U.G.C has mandated 'Induction Programme' for newly recruited teachers in higher education. Disability issues should be included in training module of newly recruited faculty members. Refresher programmes need to be conducted from time to time for the in-service teachers as well to sensitize them and make their approach more disabled friendly.

VIII. Awareness Programmes- Bringing awareness is a very important factor for emancipation of PWD. Report of Tata Institute of Social Sciences on Inclusion & Accessibility for Students With Disability in Higher Education has highlights the need of "Working at University level through sensitization and training at various levels for various stakeholders especially peers, teachers and staff in order to better accommodate the needs of students with disability during Field Work or internship, Research, issues of Library accessibility, Accommodation, Job Placement, Scholarship & funding schemes etc." (TISS Inclusion & Accessibility Report, 2015, p.4) Awareness activity in institutions will lead to inclusion of disabled students. Institute of higher education can also play a substantial role in spreading awareness among mass. Disability Cell of such institutions should be entrusted the responsibility to educate mass in their areas about the rights and need of the disabled to build public consensus for better inclusion.

IX. Accommodation- Mobility is another major issue for disabled students. Institutions should focus on providing disabled friendly accommodation in campus to avoid unnecessary trouble of travelling. PWD students will feel secure in the vicinity of campus.

X. Use of ICT- There is a good advancement in assistive technology. Use of ICT can empower disabled students in a better

way but such technology has not found way in higher education due to the lack of awareness and resources. Affordability of assistive technology is still a bigger challenge for PWDs. Governments and NGOs should come forward to make such technology available to disabled students.

XI. Social Audit of Disabled Friendly Infrastructure- All the acts have adequate provision for providing accessible infrastructure for disabled but this issue is not limited to educational institutions only. A PWD needs disabled friendly infrastructure at every public place to reach at the door step of institution. Despite of obligations by the acts, a little has been done due to some other reasons. Lack of sense of accountability to the issue is another major reason to overlook their demand. There should be social audit system of disabled friendly infrastructure of institutions. N.G.Os, disability activists, disabled persons with different kind of disability and educationists should be part of the social audit committees. Committees should be formed at district level. Audit from this committee should be made compulsory to provide funding and recognition of institutions.

Conclusion:

India has made considerable progress in higher education but participation of PWDs is still very low in higher education. Most of the acts, and policy enacted for the betterment of the disabled have a mute response on higher education and the focus of such acts and policies remains on school education only. Provisions for higher education are limited to special education infrastructure only. First and foremost need is to have a subtle legal frame work to ensure their inclusion in higher education. NEP2020 has proposed multifaceted strategy for inclusion of Socio-Economically Disadvantaged Groups and disability is one of such groups. NEP 2020 has also envisioned to see issues of inclusive education in conjunction of school education. Government's plan to establish University of Disability Studies and Rehabilitation Sciences

in Assam is welcoming step and such university should be opened all over India. Until a sound policy, focused on the persons with disabilities in the higher education is formulated and administered properly and unless the general population is sensitized about the needs and demands of PWD, true inclusion of disabled in higher education is not possible and the rights guaranteed in constitution can not materialized without their inclusion.

References

- All India Council for Technical Education.(2019). Model Curriculum for Bachelor of Architecture (B.Arch) 2019. Retrieved from https://www.aicte-india.org/sites/default/files/B.%20Arch%202019_compressed.pdf
- All India Council for Technical Education. (2021). Approval Process Handbook 2021-2022. Retrieved from [https://aicte-india.org/sites/default/files/approval/Approval%20Process%20Handbook_2021-22%20\(Revised\).pdf](https://aicte-india.org/sites/default/files/approval/Approval%20Process%20Handbook_2021-22%20(Revised).pdf)
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Disability and Health Overview. Retrieved from <https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html>
- Disabled get only 0.56% of seats in higher education. (2015) Time of India Education, 5 Apr 2015. Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/disabled-get-only-0-56-of-seats-in-higher-education/articleshow/46810639.cms>
- Government of India Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education. (2019). All India Survey on Higher Education (AISHE) 2018-2019. Retrieved from https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/AISHE%20Final%20Report%202018-19.pdf
- Government of India Ministry Of Law and Justice Legislative Department. (2020). The Constitution Of India. Retrieved from https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI_1.pdf
- Government of India Ministry of Law, Justice and Company Affairs. (1992). The Rehabilitation Council of India Act, 1992. Retrieved from <http://www.rehabcouncil.nic.in/writereaddata/rciact.pdf>
- Government of India Ministry Of Law, Justice And Company Affairs. (1999). The National Trust For The Welfare Of Persons With Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation And Multiple Disabilities Act, 1999. Retrieved from <https://thenationaltrust.gov.in/upload/uploadfiles/files/National%20Trust%20Act%20-%20English.pdf>
- Government of India Ministry of Social Justice and Empowerment. (2006). National Policy for Persons with Disabilities. Retrieved from <http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/National%20Policy.pdf>
- Government of India Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2021). Persons with Disabilities (Divyangjan) in India - A Statistical Profile : 2021. Retrieved from http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Persons_Disabilities_31mar21.pdf
- Government of India, Department of Education, Ministry of Human Resource Development. (1998). National Policy on Education 1986. Retrieved from https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92.pdf
- Government of India, Ministry of Human Resource Development.(1992). National Policy on Education 1986 Programme on Action (1992). Retrieved from https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- Government of India, Ministry Of Law, Justice And Company Affairs. (1995). P W D Act, 1995 The Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection Of Rights And Full Participation) Act, 1995. Retrieved from <https://www.niepmid.tn.nic.in/documents/PWD%20ACT.pdf>
- Ministry of Law and Social Justice. (2016). The Rights Of Persons With Disabilities Act, 2016. Retrieved from https://www.niepmid.tn.nic.in/documents/RPWD_ACT_2016.pdf
- National Policy on Education 1986 Programme on Action (1992). Retrieved from https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- The Tata Institute of Social Sciences TISS (2015). Inclusion & Accessibility for Students with Disability in Higher Education Report. Retrieved from https://www.tiss.edu/uploads/files/iaccess_report.pdf
- United Nations. (2006). United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved from https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf
- University Grant Commission. (2012) Guidelines for Persons with Disabilities Scheme in Universities XII Plan (2012-2017). Retrieved from https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1604485_person-with-disabilities-Uni.pdf
- University Grant Commission. (2019). Annual Report 2018-2019. Retrieved from https://www.ugc.ac.in/pdfnews/3060779_UGC-ANNUAL-REPORT--ENGLISH--2018-19.pdf



Behavioural Management Techniques: An Interventional Approach in handling Children with Autism Spectrum Disorder

Dr. Prashant Srivastava

Psychediatric Social Worker, Department of Psychiatry, Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal, Haryana

Background: Autism Spectrum Disorder (ASD) is considered to be a complicated condition wherein problem in communication and behavior, not only affect the individual but also the family and the community at large. Children with Autism Spectrum Disorder have a wide range of needs and most exhibit behavioural problems. Around 7-15% of children with ASD have severely challenging behavioural problems. The nature and severity of these behavioural problems vary with the degree of autism spectrum disorder. In children with autism spectrum disorder, the social environment in which they live and interact also shapes their behaviour. Having a child with ASD is stressful for families and the child's behavioural problems can create additional stress and frustration for parents and caretakers. Management of behavioural problems in children with autism spectrum disorder is a great concern. **Aims and Objective:** This study was aimed to know the behavioural management application provided to children with Autism Spectrum Disorder. **Method:** 10 Children's were included, who were diagnosed with autism spectrum disorder and samples were selected based on Purposive Sampling technique. Some behavioural domains were selected using self- rated behaviour (0 to 10) for children with autism spectrum disorder

to quantify the study subjects' behavioural problems before and after application of behavioural management techniques (pre and post-intervention, respectively) and data was analysed using SPSS-20 version. **Result and Outcome:** Behavioural management techniques were effective in reducing the aggressiveness, impulsivity, poor understanding, poor interaction pattern and poor attachment of children with autism spectrum disorder.

Introduction:

Autism is a life-long developmental disability, which can affect interaction pattern, social skills, and behaviour. Its form and intensity can vary from person to person, but people with autism share some complexity in making sense. First illustrated by Leo Kanner in 1943, it was not until 1980 that autism was formally familiar as a disorder of development distinct from childhood schizophrenia (American Psychiatric Association 1994). People with characteristics similar to classic, Kanner-type autism have been recognized who do not fulfil the same particular criteria for autism. To recognise this, a broader range of pervasive developmental disorders including Asperger's Syndrome, Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified (PDD NOS)/Atypical Autism are now measured to be part of the autistic spectrum (although classification is contentious). This is together known as Autism Spectrum Disorder, or ASD.

Autism involves the inability to express communicative functions and engage in typical social behaviour (Paul, 2001). Core features of ASD are apparent in three of the following behavioural areas: 1. social communication, 2. language 3. restrictive concerns and repetitive behaviour. These three areas are known to as the “triad of impairment”. Onset of atypical or delayed functioning in at least one of these areas is expected before the age of three years. Related features of ASD sometimes apparent include aggressive or violent behaviour to self and others, Poor attention, concentration and sleep concerns, unusual responses to sensory stimuli and savant skills and interests. The triad of core features forms the basis for diagnostic criteria used by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (American Psychiatric Association, 2000) and the International Classification of Diseases (ICD-10) (World Health Organization, 1992) to classify ASD.

The rates of behaviour concerns among young disabled children, and especially children with autism spectrum disorder are three to four times greater than among Non-ASD children (Baker et al., 2002; Baker et al., 2003; Volkmar and Dykens, 2002). These behaviour problems classically continue to persist into later childhood and adolescence (Emerson, 2003) and, as the child increases in size, potency and speed, become more rigorous. This puts the child at increased risk of injury and also means they become more and harder for parents and schools to manage. Tough behaviour is the main reason why children are placed in 38 or 52 week placements in residential schools (Abbott et al., 2000), and is also a key issue for families being unable to access short breaks (or respite care), and/or the child being unable to access educational, therapeutic and/or community or social actions (Kahng and DeLeon, 2008). High levels of unmet desires in skills to manage their child’s behaviour are reported by parents,

and intensity of the child’s behaviour problem has been found to be associated with levels of parental stress (for example, Baker et al., 2003; Quine and Pahl, 1989).

Tongee, al., (2006), concluded that parent psycho-education and behaviour training program for parents of young children with autism provides key improvements in parental mental health and modification, justifying its addition to early behaviour intervention programs at least for parents with mental health problems. The multidisciplinary team approach has brought out major improvement in children with autism and the improvements are in the areas of relating to people, listening and visual reaction, and there are reduction in body use, object use, and activity intensity (Sridevi and Rangaswamy, 2013).

Methodology:

This study was aimed to examine the application of behavioural management provided to children with Autism Spectrum Disorder. 10 Children’s were included, who were diagnosed with Autism Spectrum Disorder and samples were selected based on Purposive Sampling technique. Some behavioural domains (Aggressiveness, Impulsivity, Poor Understanding, Poor Interaction Pattern and Poor Attachment) were selected using self-rated behaviour (0 to 10) for children with autism spectrum disorder to quantify the study subjects’ behavioural problems before and after application of behavioural management techniques (pre and post-intervention, respectively) for 6 weeks and data was analysed using SPSS20 version. Informed consent from the parents was also taken.

Reason for taking for intervention:

To reduce the aggressive behaviour and impulsivity as well as to enhance the understanding, interaction pattern and attachment of child with Autism Spectrum Disorder.



Specific areas to be focused:

- Establish a firm therapeutic alliance with the parents.
- Educate the parents regarding the manifestations of behaviours of child with autism.
- To decrease aggressive behaviour and impulsivity.
- To improve understanding, interaction pattern and attachment

Types and Techniques of Intervention:

Psycho education: The parents offered psycho education to make the aware about the nature of illness, course, treatment, prognosis, and to clear any misconceptions about the illness. This was done so that the parents got a better position to deal with the illness as they had no hope of getting better. Directions to reduce repeated medical consultations and investigations also provided.

Supportive Psychotherapy: Supportive psychotherapy was aimed at validating the distress the parents is undergoing. The parents are given reassurance, support, and his ability to cope with distress is reinforced.

Behaviour Modification: The behaviour modification was carried out for 6 weeks. The session was continued for 2 hours to decrease aggressive behaviour and impulsivity and to improve eye contact, attention and concentration, understanding, interaction pattern and attachment with different materials. The target behaviors and reinforcers were identified to continue the therapy program for the betterment of the child. As well as some social skills program for autistic children included the learning how to act and react in social situations. Basic skills such as developing sense of self, waiting for turn, replying to questions, and explaining rules are addressed.

This also includes Communication Skills Management by getting attention can be termed under communication skill and interaction pattern as well as social skills. This is one of the pre-requisite of communication skills i.e. we need to gain the other person's attention before we communicate. As child with ASD are unable to follow this while teaching communication skills. This will follow with the child with an aim to gain the other persons attention before communicating. Many exercises were planned and implemented to develop this behaviour in the child such as Picture exchange communication system.

Therapeutic Process:

Session 1: The initial sessions involved the pre-assessment of the child behaviours as per parents. Some behavioural domains like Aggressiveness, Impulsivity, Poor Understanding, Poor Interaction Pattern and Poor Attachment were self-rated (0 to 10) for children with autism spectrum disorder by parents. It also involved psycho-education which was provided to the parents with the purpose of increasing awareness about the illness. This helped them in understanding how his symptoms began. Firstly therapist listen them with care and reassurance and empathy was given to them. Supportive psychotherapy was also given to their parents as they were very anxious and worried. Supportive measures such as reassurance and persuasions were used and were asked to support the child esteem.

Session 2: In this session parents were advised for aggressive behaviour and impulsivity of child and how to reduce all these behaviours. Some distraction techniques were taught to parents. The therapist advised parents to make the child engage in some different activities. Don't let the child free. As well as to reduce the fulfilling the needs of child and to reduce over-involvement. Therapist also guided how to use the reinforcements (positive and negative) for reducing the maladaptive behaviours of child.

Session 3: Parents were reviewed about second session which was conducted. In this session poor understanding was targeted. Therapist advised regarding some park based activity and guided parents to increase the activity of child in daily routine like engaging the child in house hold activities, and also to reduce the day sleeping of child. Some sitting activity also introduced to parents like table-top play activity, attention improving exercises and some play activity games as well as giving more opportunities for daily needs and demands.

Session 4: Parents were reviewed. This session concludes the interventions focused on improving interaction pattern of child. Many exercises were introduced and implemented to develop this behaviour in the child. Picture exchange communication system in which the communication partner avoids eye contact at one stage. When the child approaches the person with his picture card and taps the person to gain his / her attention, the communication partner looks at the child and then responds to the request. Frequent repetition of similar strategy helped the child to understand the importance of gaining other's attention. As well as therapist also teaches the parents to increase the maximum vocalization of child for demands and to reduce the fulling the demands of child by parents on only indications. Using of flash cards for effective interaction by child was also teaches to parents by therapist.

Session 5: Parents were reviewed about fourth which was conducted. In this session poor attachment was targeted. In this session therapist guided parents to enhance social behaviour and competence in children with ASDs should be targeted with respect to the child's age, developmental level, and peer group.

This session intervention includes focus on teaching parents how to engage their child and encourage back-and-forth play and improving eye contact. This session may also focus on playing with peers, understanding emotions, and learning the basics of turn-taking and initiating and responding to social interactions. In this session therapist focused on specific social-behavioural skills (e.g., conversations, greetings, initiating game play, joint attention) and affective understanding (e.g., recognizing emotions in self and others). For improving eye contact therapist trained the parents to use some techniques such as: Placing the child in a darkroom and moving candle in front of him with a distance from one side to another side. Further, whenever the child pulls parents for his/her demand they were asked to pull back their hand and when child looks at them then after they fulfil child's demand and parent followed this method, through which the child learned that he need to look at the other person before his need is met and parents were also asked to hold the child's head and engage him by talking along with the expressions.

Session 6: Parents were reviewed. In this session they were also educated about follow-up and medical adherence. During this session the parents gave feedbacks and unclarified concepts regarding disorder and its intervention strategies and therapist does corrections and clarifies the all concepts. After the session therapist explained parents about the importance of regular practice of interventions guided in all sessions and also advised the parents to practice it on daily basis with child. At the end again as post-intervention, Self-rating (0-10) was done by parents to know the effectiveness of behavioural management techniques in children with autism spectrum disorder.

Results:

Table 1: Statistical Mean Age of the samples

Variables	Mean	Standard Deviation
Age (in years)	3.90	0.73

Table 2: Statistical analysis of the socio demographic variables of the sample

Variables		Frequency	Percentage (%)
Sex	Male	6	60
	Female	4	40
Family Type	Nuclear	7	70
	Joint	3	30
Socio-Economic Status	Low	3	30
	Middle	6	60
	High	1	10
Religion	Hindu	6	60
	Muslim	4	40

Table 3: Comparison of the change of scores in various domains of behaviours in the pre and post behavioural management intervention phases:

Variables	Mean $\pm$ SD		T	P	Imp
	Pre ^{M1}	Post ^{M2}			
Aggressiveness	8.30 $\pm$ 1.06	6.00 $\pm$ 1.56	3.851	0.001***	M1>M2
Impulsivity	8.00 $\pm$ 0.81	6.00 $\pm$ 1.24	4.243	0.000***	M1>M2
Poor Understanding	8.40 $\pm$ 1.07	5.80 $\pm$ 0.78	6.166	0.000***	M1>M2
Poor Interaction Pattern	8.40 $\pm$ 0.96	6.20 $\pm$ 0.78	5.578	0.000***	M1>M2
Poor Attachment	8.70 $\pm$ 0.82	5.80 $\pm$ 1.03	6.943	0.000***	M1>M2

*** Significant at 0.001

Discussion:

This study aimed to examine the application of behavioural management provided to children with Autism Spectrum Disorder. The results indicate that there is a significant difference in the means of the domains of Aggressiveness, Impulsivity, Poor Understanding, Poor Interaction Pattern and Poor Attachment, in the pre and post intervention phase. Stress was also reduced among parents after the intervention phases. Kaale et. al. (2012) found that behavioural management are the most preferable treatment approaches for children with ASD. These types of behaviour treatment

programs typically target behaviours and development more broadly, instead of focusing on a specific behaviour of interest (Kasari et. al., 2012). Positive outcomes were seen with these management in terms of cognition and language have led to the suggestion that beginning intensive therapy at an earlier age may lead to greater improvements (Ingersoll, 2010; Kasari et. al., 2012, Lawton & Kasari, 2012; Kasari, 2006). Children with a multiple problems, impairments and risk factors, including those with autism spectrum disorder, benefit from early, intensive management, with trained providers, using inclusive, individualized, and ecologically relevant management approaches (Ramey &

Ramey, 1998). Lord (1995) found that over the past few years, children with ASD are being diagnosed at two years of age. Treatments for autism spectrum disorder include behavioural intervention, developmental intervention, and cognitive-behavioural intervention; and these have unique intervention strategies and also have some overlap within these interventions (Corsello, 2005).

Conclusion and Outcome:

This study is carried out at New Delhi was an effort to study the application of behavioural management techniques on children with autism spectrum disorder. For this purpose, 10 children between the age ranges of three to twelve years were taken for the study and six sessions of 45 minutes each were conducted for duration of 6 weeks with a pre and post assessment. Results showed that:

- Behavioural management techniques were effective in reducing the Aggressiveness, Impulsivity of children with autism spectrum disorder.
- It also helped to increase the understanding, interaction pattern and understanding of children with autism spectrum disorder
- Changes in the parent child interactions post the effective training of parents in session was also observed.

To conclude behavioural management techniques is effective in bringing about changes in the behavioural issues in children with autism, but an ongoing evaluation and treatment process is essential to maintain and generalize the target behaviours attained.

Limitation:

The study was done over a small sample size; hence it lacks the efficiency to generalize the outcome of behaviour. A control group

could have been used to compare the efficacy of the intervention programme used. A formal assessment of the antecedents and consequences affecting the target behaviour was not performed which would have helped in better identifying the cause of the maladaptive or deficit behaviours. Long term follow up assessment was not done which could have given a better idea of the maintenance of effects of the intervention.

Future Directions:

Follow up studies are needed in the Indian context to identify whether the results obtained are maintained over a long period of time. More controlled studies in which sample size is large are needed. Comparative studies involving other behavioural interventions will add in the understanding of the efficacy of behavioural management. Other behavioural dimensions recognised in the present study can be targeted using ABC analysis to identify the efficacy of behavioural management in reducing problem behaviours.

References:

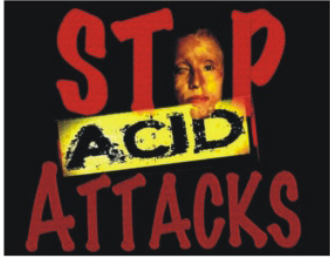
- Abbott, D., Morris, J. and Ward, L. (2000). Disabled Children and Residential Schools: A survey of local authority policy and practice, Bristol: Norah Fry Research Centre, University of Bristol.
- American Psychiatric Association (APA). (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR (4th edition, text revision). Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Baker, B.L., Blacher, J., Crnic, K. and Edlbrock, D. (2002). Behaviour problems and parenting stress in families of 3 year old children with and without developmental delays. American Journal on Mental Retardation, 107, 433-44.
- Baker, B.L., McIntyre, L., Blacher, J., Crnic, K., Edelbrock, C. and Low, C. (2003). Pre-school children with and without developmental delay: behaviour problems and parenting stress over time. Journal of Intellectual Disability Research, 47, 217-30.



- Corsello, C.M. (2005). Early Intervention in Autism. *Infants & Young Children*, 18 (2), 74–85.
- Emerson, E. (2003). Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability. *Journal of Intellectual Disability Research*, 47, 51-58.
- Ingersoll, B. (2010). Brief report: Pilot randomized controlled trial of reciprocal imitation training for teaching elicited and spontaneous imitation to children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40, 1154–1160
- Kaale, A., Smith, L., Sponheim, E. (2012). A randomized controlled trial of preschool based joint attention intervention for children with autism. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 53, 97–105.
- Kahng, S. and DeLeon, I. (2008). Behavior management, in P.J. Pasquale (ed.), *Neurodevelopmental Disabilities in Infancy and Childhood. Volume I: Neurodevelopmental Diagnosis and Treatment*, Baltimore: P.H. Brookes.
- Kasari, C., Freeman, S. and Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: A randomized controlled intervention study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47, 611–620.
- Kasari, C., Rotheram-Fuller, E. and Locke, J. (2012). Making the connection: randomized controlled trial of social skills at school for children with autism spectrum disorders. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 53, 431–439.
- Lawton, K. and Kasari, C. (2012). Brief report: Longitudinal improvements in the quality of joint attention in preschool children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42, 307–312.
- Lord, C. (1995). Follow-up of two-year-olds referred for possible autism. *Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines*, 36(8), 1365–1382
- Quine, L. and Pahl, J. (1989). *Stress and Coping in Families Caring for a Child with Severe Mental Handicap: A longitudinal study*, Kent: Institute of Social and Applied Psychology and Centre for Health Services Studies, University of Kent.
- Ramey, C.T. and Ramey, S.L. (1998). Early intervention and early experience. *American Psychologist*, 53, 109–120.
- Sridevi, G. and Rangaswamy, K. (2013). Efficacy of Multidisciplinary Approach in the Treatment of Children with Autism. *Indian Journal Developmental Disabilities*, 1(1), 44-49.
- Volkmar, F. and Dykens, E. (2002). Mental retardation, in M. Rutter and E. Taylor (eds), *Child and Adolescent Psychiatry*, 4th edition, Oxford: Blackwell.
- World Health Organization. (1992). *International classification of diseases: Diagnostic criteria for research* (10th edition). Geneva, Switzerland.

दिव्यांगजन अधिकारिता अधिनियम-2016 के अन्तर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता

1. “एसिड हमले के पीड़ितों”



2. दृष्टि बाधित



3. सुनने में अक्षम



4. वाणी और भाषाई निशक्तता



5. बौद्धिक अक्षमता



6. विशिष्ट लर्निंग निशक्तता



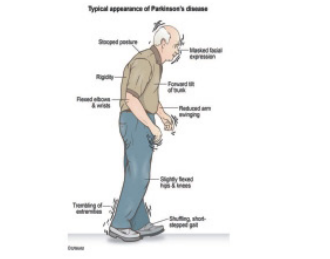
7. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर



8. मानसिक व्यवहार “मानसिक बीमारी”



9. पार्किन्सन की “बीमारी”



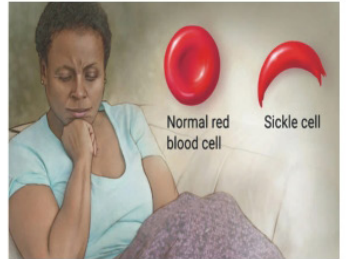
10. रक्त विकार। “हिमोफीलिया”



11. “थैलेसीमिया”



12. सिकल सेल रोग



13. विविध निशक्तता



14. बौनापन



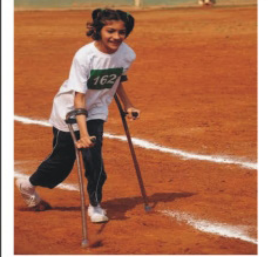
15. मांसपेशीय दुर्बिकार



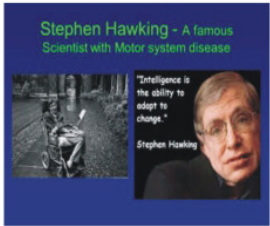
16. मस्तिष्क पक्षाघात



17. चलने में निशक्तता



18. क्रोनिक् न्यूरोलॉजिकल समस्याएं



19. कुछ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति



20. हाथों या पैरों में संवेदनशून्यता



21. प्रकट विकृति और आंशिक पक्षाघात



22. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाली कोई अन्य श्रेणी



पुर्नपाठ सामाजिक निष्क्रियता

डॉ० भीम राव अम्बेडकर

हिं दू समाज के दोषों को व्यक्त करने वाली सामाजिक बुराईया सर्वविदित हैं। मिस मेयो द्वारा प्रकाशित 'मदर इंडिया' में इन बुराईयों का विस्तार से विवेचन किया गया है। परंतु 'मदर इंडिया' ने जहां इन बुराईयों को उजागर करने का सोद्देश्य कार्य किया है और इनके प्रवर्तकों को विश्व न्याय मंच के सामने अपने पापों का उत्तर देने के लिए आहूत किया है, उससे दुर्भाग्यवश विश्व में यह धारणा भी बनी है कि जबकि हिंदू इन सामाजिक बुराईयों की कीचड़ में फंसकर पतनमुख हो रहे हैं, वहां भारतीय मुसलमान उनसे मुक्त हैं और हिंदुओं की तुलना में अधिक प्रगतिशील हैं। ऐसी

धारणा का बनना उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक ही है जो भारत में मुस्लिम समाज को बहुत पास से जानते हैं। कोई भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या कोई ऐसी सामाजिक बुराई है जो हिंदुओं में तो है, लेकिन मुसलमानों में नहीं पायी जाती? बाल-विवाह को ही लें। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (आल इंडिया वूमेंस कान्फ्रेंस) द्वारा गठित बाल-विवाह विरोधी समिति ने एक समाचार बुलेटिन प्रकाशित किया है, जिसमें देश के विभिन्न समुदायों में प्रचलित बाल-विवाह की स्थिति का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। 1931 की जनगणना रिपोर्ट से जो आंकड़े लिए गए हैं, वे यहां प्रस्तुत हैं:

तालिका : 0-15 के आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं में विवाहित महिलाएं

वर्ष	हिंदू	मुस्लिम	जैन	सिख	ईसाई
1881	208	153	189	170	33
1891	193	143	172	143	37
1901	186	131	164	101	38
1911	184	123	130	88	39
1921	170	111	117	72	32
1931	199	186	125	141	172

बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय क्या बाल-विवाह की दृष्टि से मुसलमानों की स्थिति हिंदुओं से बेहतर मानी जा सकती है?

महिलाओं की स्थिति को लीजिए। मुसलमान इस बात पर जोर देते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को मिले कानूनी अधिकार अन्य महिलाओं, उदाहरणार्थ हिंदू महिलाओं को प्राप्त अधिकारों की तुलना में अधिक आजादी सुनिश्चित करते हैं और वे कतिपय पाश्चात्य देशों की महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों की तुलना में भी अधिक हैं। यह दावा मुस्लिम कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर किया जाता है।

सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि मुस्लिम कानून में विवाह के लिए कोई आयु-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और लड़की के इस अधिकार को मान्यता दी गई है कि वह किसी भी समय विवाह कर सकती है। फिर, उस स्थिति के अलावा जबकि विवाह पिता अथवा पितामह ने कराया है, बाल्यावस्था में अन्य विवाहित मुस्लिम लड़की योवनावस्था प्राप्त कर लेने पर अपने विवाह का परित्याग कर सकती है।

दूसरे यह विश्वास किया जाता है कि मुसलमानों में विवाह एक अनुबंध है। अनुबंध होने के कारण पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। मुस्लिम कानून

ने पत्नी को भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया है। यदि वह उसका उपयोग करे तो तलाक के मामले में पुरुष की बराबरी कर सकती है। यह दावा किया जाता है कि मुस्लिम कानून के तहत, विवाह के समय अथवा कतिपय मामलों में उसके बाद भी, पत्नी ऐसा अनुबंध कर सकती है जिसके द्वारा वह कतिपय परिस्थितियों के तहत तलाक हासिल कर सकती है।

तीसरे, मुस्लिम कानून में यह व्यवस्था है कि पत्नी अपने को समर्पित करने के एवज में धन अथवा संपत्ति पति से मांग सकती है, जिसे उसके 'मेहर' के तौर पर जाना जाता है। मेहर (एक प्रकार का दहेज) का निर्धारण विवाह के बाद भी किया जा सकता है, और यदि कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है तो भी पत्नी समचित मेहर की हकदार है। मेहर की राशि को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें एक को फौरी कहा जाता है जो मांग करने पर तुरंत देय होती है, और दूसरी है 'मुद्ती' जो मृत्यु अथवा तलाक से शादी के टूटने पर देय होती है। मेहर के लिए पत्नी का दावा पति की संपत्ति पर एक प्रकार का ऋण माना जाता है। उसका अपने मेहर पर पूर्ण अधिकार होता है, जिसका मकसद उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। वह अपनी इच्छानुसार उक्त मेहर का परित्याग कर सकती है अथवा उसकी आय को विनियोजित भी कर सकती है।

कानून के ये तमाम प्रावधान महिला के पक्ष में होने पर भी मुस्लिम महिला विश्व भर में सर्वाधिक असहाय अवस्था में है। मिस्र के एक मुस्लिम नेता के शब्दों "इस्लाम ने महिला पर हीनता की मोहर लगा दी है तथा सामाजिक प्रथाओं को धर्म की स्वीकृति देकर उसे आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास के सभी अवसरों से वंचित कर दिया है। किसी भी मुस्लिम लड़की को अपने विवाह को अमान्य करने का साहस नहीं है, यद्यपि इस आधार पर उसे छूट हो सकती है कि वह नाबालिक थी और यह विवाह उसके माता-पिता ने नहीं अन्य लोगों ने कराया था। कोई भी मुस्लिम पत्नी यह उचित नहीं समझेगी कि उसके निकाह के अनुबंध में यह धारा भी शामिल की जाए कि उसे तलाक लेने का अधिकार है। ऐसे में उसका प्रारब्ध यही होगा कि एक बार का निकाह, हमेशा के लिए निकाह। वैवाहिक अनुबंध कैसा भी क्लेशप्रद क्यों न हो, विवाह के बंधन से वह बच नहीं सकती, विवाह को अमान्य नहीं कर सकती, जबकि वहीं पति

को बिना कोई कारण दर्शाए ऐसा करने की हमेशा छूट है। 'तलाक' शब्द का उच्चारण करने और उसके तीन सप्ताह तक आत्मसंयम का निर्वाह करने के बाद पति को अलग किया जा सकता है। पति की मर्जी की राह में एकमात्र रूकावट मेहर की अदायगी का दायित्व है। यदि मेहर का परित्याग किया जा चुका है या उसका भुगतान किया जा चुका है, तो तलाक का हक उसकी मन की मौज का ही मामला है। तलाक के मामले में ऐसी उदारता से सुरक्षा की वह अनुभूति नष्ट हो जाती है जो एक महिला के पूर्णतः मुक्त और सुखद जीवन की परमावश्यक आधारशिला है। मुस्लिम महिला के जीवन की यह असुरक्षा उस समय और अधिक बढ़ जाती है, जब उसके पति को बहु विवाह करने और रखैल रखने का कानूनन अधिकार प्राप्त हो जाता है। मुस्लिम कानून मुसलमानों को चार महिलाओं से एक समय पर विवाह करने की अनुमति देता है। इसे इसलिए कोई असामान्य बात नहीं कहा जाता कि यह व्यवस्था उस हिंदू कानून की तुलना में अधिक प्रगतिशील है जिसमें किसी हिंदू पर इस मामले में कोई रोक नहीं है कि वह कितनी ही पत्नियां रख सकता है। परंतु इस तथ्य को विस्मृत कर दिया जाता है कि चार कानूनी पत्नियों के अलावा मुस्लिम कानून एक मुसलमान को अपनी महिला गुलामों से भी सहवास करने की अनुमति देता है। महिला गुलामों की संख्या के बारे में उस कानून में कुछ भी नहीं बताया गया है। उसे यह भी अधिकार है कि वह बिना किसी रूकावट अथवा कृतज्ञता के उन गुलामों को अपने साथ रख सकता है। उस पर यह बंधन भी नहीं है कि वह उनसे विवाह करे।

बहु विवाह करने तथा रखैल रखने की प्रथा विशेष रूप से मुस्लिम महिला के लिए जिस तरह दुखदायी है, उसका तथा उसके कारण जो अनेक बुराइयां जन्मती हैं उनका समुचित रूप से वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल पाते। यह सच है कि बहु विवाह और रखैल रखने की स्वीकृति के बावजूद किसी को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि मुसलमानों में आम तौर पर ऐसा होता है। फिर भी यह तथ्य तो बना ही रहता है कि ये ऐसे विशेषाधिकार हैं जिनका आसानी से दुरुपयोग करते हुए कोई भी मुसलमान अपनी पत्नी के जीवन में दुखों और कष्टों का विष घोल सकता है। श्री जॉन जे.पूल. जो इस्लाम के शत्रु नहीं हैं, का कथन है: 'तलाक के मामले में इस



छूट का कुछ मुसलमान बहुत अधिक लाभ उठाते हैं। स्टोवार्ट ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए अपनी पुस्तक 'इस्लाम एंड इट्स फाउंडर' में कहा है — कुछ मुसलमानों ने लगातार अपनी बीबियां बदलते रहना अपनी आदत बना ली है। हमने ऐसे नौजवानों के बारे में पढ़ा है जिनकी बीस और तीस पत्नियां हैं। हर तीसरे-चौथे महीने वे एक नई बीबी ले आते हैं, और इस प्रकार ऐसा होता है कि एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक महिलाओं को हस्तांतरित करने का निरंतर एक सिलसिला चलता रहता है। उन महिलाओं को कभी एक को पति मानना पड़ता है, तो कभी दूसरे घर का द्वार देखना पड़ता है, अथवा बेसहारा या निराश्रित स्थिति को झेलते हुए तलाक दे दिए जाने का परिणाम भुगतती रहती हैं। जीवनयापन के लिए ऐसे में वह कुछ दूसरे अधिक तुच्छ और निम्न साधनों का सहारा लेती हैं। इस तरह कानून का अक्षरशः पालन करते हुए और संभवतः एक, अथवा निश्चित रूप से चार, से अधिक पत्नियां न रखते हुए भी घृणित चरित्र वाले लोग तलाक का सहारा लेकर अपने जीवन-काल में चाहे जितनी पत्नियां रख सकते हैं।

एक दूसरे तरीके से भी एक मुसलमान चार से अधिक पत्नियां रख सकता है, और फिर भी कानून के अंतर्गत रह सकता है। यह तरीका रखैलों के साथ रहने का है, जिनकी कुरान ने खुलकर इजाजत दी है। कुरान की जिस सूरा में चार पत्नियां रखने की अनुमति है, ये शब्द भी हैं — जिन दासियों को तुमने प्राप्त किया है। फिर 70वीं 'सूरा' में यह बताया गया है कि दासियों के साथ रहना कोई पाप नहीं है। वे शब्द ये हैं — वे गुलाम जिन पर उनके दाहिने हाथ का अधिकार उनके दोष का कारण नहीं होंगे। अतीत के समान ही आजकल भी बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवारों में गुलाम (दासियां) पाई जाती हैं। जैसा कि मुइर ने अपनी पुस्तक 'लाइफ ऑफ महोमत' में कहा है — 'जब तक दासियों के साथ रहने की यह असीम अनुमति उन्हें प्राप्त रहेगी, तब तक यह आशा नहीं की जा सकती कि मुस्लिम देशों में गुलाम रखने की प्रथा पर रोक का कोई हार्दिक प्रयास होगा। इस तरह गुलामी के मामले में कुरान मानवता की शत्रु है, और महिलाएं सामान्यतः सर्वाधिक उत्पीड़ित हैं।' जाति प्रथा को लीजिए। इस्लाम मातृ-भाव की बात कहता है। हर व्यक्ति यही अनुमान लगाता है कि इस्लाम दास प्रथा और जाति प्रथा से मुक्त होगा। गुलामी के बारे

में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। अब कानूनन यह समाप्त हो चुकी है। परंतु जब यह विद्यमान थी, तो ज्यादातर समर्थन उसे इस्लाम और इस्लामी देशों से ही मिलता था। कुरान में पैगंबर ने गुलामों के साथ उचित और मानवीय व्यवहार किए जाने का सदुपदेश दिया है वह प्रशंसनीय है, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन के समर्थन में हो। जैसा कि सर डब्ल्यू. मूडर ने स्पष्ट कहा है:

गुलाम या दास प्रथा समाप्त हो जाने में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जब इस प्रथा के बंधन ढीले करने का अवसर था तब मुसलमानों ने उसको मजबूती से पकड़ लिया। किसी मुसलमान पर यह दायित्व नहीं है कि वह अपने गुलामों को मुक्त कर दे। परंतु गुलामी भले विदा हो गई हो, जाति तो मुसलमानों में कायम है। उदारहण के लिए बंगाल के मुसलमानों की स्थिति को लिया जा सकता है। 1901 के लिए बंगाल प्रांत के जनगणना अधीक्षक ने बंगाल के मुसलमानों के बारे में यह रोचक तथ्य दर्ज किए हैं:

'मुसलमानों का चार वर्गों — शेख, सैयद, मुगल और पठान — में परंपरागत विभाजन इस प्रांत (बंगाल) में प्रायः लागू नहीं है। मुसलमान दो मुख्य सामाजिक विभाग मानते हैं — 1 अशरफ अथवा शरफ और 2. अजलफ। अशरफ से तात्पर्य है 'कुलीन' और इसमें विदेशियों के वंशज तथा ऊंची जाति के धर्मांतरित हिंदू शामिल हैं। शेष अन्य मुसलमान जिनमें व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मांतरित शामिल हैं उन्हें अजलफ अर्थात् नीचा, अथवा निकृष्ट व्यक्ति माना

1. स्टडीज इन मोहमडनिज्म, पृ. 34-35 2. तथैव, अध्याय XIII 3. दि कुरान, इट्स कम्पोजीशन एंड टीचिंग, पृ. 58 जाता है। उन्हें कमीना अथवा इतर कमीन या रासिल, जो रिजाल का भ्रष्ट रूप है, बेकार कहा जाता है। कुछ स्थानों पर एक तीसरा वर्ग 'अरजल' भी है, जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीच समझे जाते हैं। उनके साथ कोई भी अन्य मुसलमान मिलेगा—जुलेगा न हीं और न उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता

इन वर्गों में भी हिंदुओं में प्रचलित जैसी सामाजिक वरीयता और जातियां हैं। 1. 'अशरफ' अथवा उच्च वर्ग के मुसलमान (i) सैयद (ii) शेख (iii) पठान (iv) मुगल (v) मलिक (vi) मिर्जा 2. 'अजलफ' अथवा निम्न वर्ग के मुसलमान 6) खेती करने वाले शेख और अन्य वे लोग जो मूलतः हिंदू थे, जनगणना-अधीक्षक

ने मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था के एक और पक्ष का भी उल्लेख किया है। वह है 'पंचायत प्रणाली' का प्रचलन। वह बताते हैं:

"पंचायत का प्राधिकार सामाजिक तथा व्यापार संबंधी मामलों तक व्याप्त है और अन्य समुदायों के लोगों से विवाह एक ऐसा अपराध है, जिस पर शासी निकाय कार्रवाई करता है। परिणामतः ये वर्ग भी हिंदू जातियों के समान ही प्रायः कठोर संगोती हैं, अंतर-विवाह पर रोक ऊंची जातियों से लेकर नीची जातियों तक लागू है। उदाहरणतः कोई धूमा अपनी ही जाति अर्थात् धूमा में ही विवाह कर सकता है। यदि इस नियम की अवहेलना की जाती है तो ऐसा करने वाले को पेश किया जाता है। एक जाति का कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी दूसरी जाति में प्रवेश नहीं ले पाता और उसे अपनी उसी जाति का नाम कायम रखना पड़ता है, जिसमें उसने जन्म लिया है। यदि वह अपना विशिष्ट पेशा त्यागकर जीवनयापन के लिए कोई अन्य साधन भी अपना लेता है, तब भी उसे उसी समुदाय का माना जाता है, जिसमें कि उसने जन्म लिया था। हजारों जुलाहे कसाई का धंधा अपना चुके हैं, किंतु वे अब भी जुलाहे ही कहे जाते हैं।

इसी तरह के तथ्य अन्य भारतीय प्रांतों के बारे में भी वहां की जनगणना रिपोर्टों से वे लोग एकत्रित कर सकते हैं, जो उनका उल्लेख करना चाहते हों। परंतु बंगाल के तथ्य ही यह दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि मुसलमानों में जाति प्रथा ही नहीं, छूआछूत भी प्रचलित है। इस तरह से यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है कि भारत में मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों से अछूता नहीं है। वस्तुतः मुसलमानों में हिंदुओं की तमाम सामाजिक बुराइयां तो हैं ही, कुछ और बुराइयां भी हैं। मसलन एक है मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य पर्दा प्रथा।

पर्दा प्रथा के परिणामस्वरूप, मुस्लिम महिलाओं का अलगाव सुनिश्चित है। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में न आए। उनका निवास मकान के पिछले भाग में होता है। सभी महिलाओं को चाहे वे जवान हों या वृद्धा, एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कोई भी पुरुष नौकर उनकी उपस्थिति में काम नहीं कर सकता। महिला को अपने पुत्रों, भाइयों, पिता, चाचा और पति अथवा किसी ऐसे ही नजदीकी रिश्तेदार को देखने

की अनुमति है, वही विश्वासपात्र होने पर घर में प्रवेश पा सकता है। वह इबादत के लिए मस्जिद में भी नहीं जा सकती और जब कभी उसे बाहर जाना होता किंतु किसी बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित नहीं हैं और जिन्हें अशरफ समुदाय, अर्थात् पिराली और ठकराई आदि में प्रवेश नहीं मिला है। (ii) दर्जी, जुलाहा, फकीर और रंगरेज। (iii) बाढ़ी भटियारा, चिक, चूड़ीहार, दाई, धावा, धुनिया, गड्डी, कलाल, कसाई, कुला, कुंजरी, लहेरी, माहीफरोश, मल्लाह, नालिया, निकारी। अब्दाल, बाको, बेडिया, भाट, चंबा, डफाली, धोबी, हज्जाम, मुचो, नगारची, नट, पनवाड़िया, मदारिया, तुन्तिया। 'अरजल' अथवा निकृष्ट वर्ग भानार, हलालखोदर, हिजड़ा, कसबी, लालबेगी, मोगता, मेहतर है तो बुर्का ओढ़ना पड़ता है। ऐसी पृथक्ता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह पाता। वे प्रायः खून की कमी, क्षयरोग, पायरिया और कतिपय अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनके शरीर में भी सुघटता नहीं रहती, उनकी कमर झुकती जाती है, हड्डियां निकल आती हैं, हाथ और पांव में खम पड़ जाता है, वे कुरूप हो जाती हैं। पसलियों, जोड़ों और प्रायः सभी हड्डियों में दर्द रहता है। उनके हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला भी प्रायः पाया जाता है। इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप, प्रसूतिकाल में उनकी मृत्यु हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास नहीं होता। स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उनमें अनैतिकता की प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से पूर्णतः अलग-थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में उलझा रहता है। फलस्वरूप वे अपनी सोच में संकीर्ण हो जाती हैं और उनका दृष्टिकोण भी संकुचित हो जाता है।

वे अन्य जातियों की बहनों से पिछड़ जाती हैं। वे किसी बाह्य गतिविधि में भाग नहीं ले पाती और उनमें एक प्रकार की दासता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि घर की चारदीवारी के बाहर वे अत्रा किसी बात में रुचि न लें। पर्देवाली महिलाएं प्रायः डरपोक, निस्सहार शमीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। भारत के मुसलमानों में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते



हुए कोई भी आसानी से यह समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है।'

पर्दे का शारीरिक और बौद्धिक प्रभाव भौतिक प्रभाव के मुकाबले काफी कम पड़ता है। वस्तुतः पर्दा प्रथा दो मूल पुरुष और महिला दोनों में ही यौन संबंधी इच्छा को लेकर गहन संदेह में निहित है और इसका उद्देश्य स्त्री-पुरुष दोनों को अलग रखकर रोकना ही है। परंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति के बजाए पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर-परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता है। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा-कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चों अथवा वृद्धों के अलावा, पुरुष अन्य महिलाओं से हिल-मिल नहीं सकता, अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता। महिलाओं से पुरुषों की यह पृथकता निश्चित रूप से पुरुष के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। यह कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संपर्क को काट दे, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के लिए देखिए श्याम कुमार नेहरू द्वारा संपादित 'अवर काज।'

यौनाचार के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक एवं अन्य दूषित आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।

पर्दा प्रथा की बुराई का प्रभाव केवल मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित नहीं है। यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सार्वजनिक जीवन में अभिशाप बनी सामाजिक पृथकता के लिए भी जिम्मेदार है। यह तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है कि इस पृथकता के लिए मुसलमानों की पर्दा-प्रथा के बजाए हिंदुओं की असामाजिक प्रवृत्तियां भी जिम्मेदार हैं, परंतु हिंदू जब यह कहते हैं तो सही ही कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक संपर्क की स्थापना संभव नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे संपर्क से तात्पर्य एक ओर की महिलाओं और दूसरी ओर के पुरुषों के बीच संबंध होना ही होगा।'

ऐसा नहीं कि पर्दा और ऐसी ही अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं हैं। परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, जबकि हिंदुओं में ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदुओं की

अपेक्षा मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं और उसे सामाजिक आवश्यकताओं और धार्मिक अंकुशों के बीच अनिवार्य संघर्ष को झेलकर ही समाप्त किया जा सकता है। मुसलमानों में पर्दा प्रथा, अपने मूल के अलावा, एक वास्तविक समस्या है, जबकि हिंदुओं में नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी प्रयास किया हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता।

इस तरह भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक जीवन में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक जीवन में भी एक प्रकार की गतिहीनता है। मुसलमानों को राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उनकी मजहब में ही अधिक रुचि है। किसी सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के समक्ष उसके मुस्लिम क्षेत्र से जो शर्तें रखी जाती हैं, उनसे यह बात आसानी से स्पष्ट हो जाती है। मुस्लिम मतदाता प्रत्याशी के कार्यक्रम पर दृष्टिपात करने की भी परवाह नहीं करते। यह वर्ग प्रत्याशी से मात्र यही चाहता है कि वह मस्जिद के पुराने बल्बों के स्थान पर अपने खर्चे से नए बल्ब लगवा दें, क्योंकि पुराने बल्ब टिमटिमाने लगे हैं। पुराने कालीन की जगह नया कालीन बिछा दें और मस्जिद की मरम्मत करा दें। कुछ स्थानों पर मुस्लिम यह बात दिलचस्प है कि इस तर्क का उपयोग यूरोपियन अपने बचाव में करते हैं, जिन पर भारतीय यह आरोप लगाते हैं कि वे उन्हें अपने क्लबों में प्रवेश नहीं करने देते। वे कहते हैं कि "हम अपनी महिलाओं को क्लबों में लाते हैं। यदि आप अपनी महिलाओं को क्लबों में लायें, तो आप आ सकते हैं, परन्तु उस स्थिति में हम अपनी महिलाओं को आपके साथ की अनुमति नहीं दे सकते, जब आप अपनी महिलाओं को ऐसा नहीं करने देते। जब आप इस बात के लिए तैयार हो, तभी आप हमारे क्लबों में प्रवेश पाने को कह सकते हैं।"

मतदाता इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रत्याशी एक शानदार दावत देने को तैयार हो जाता है, और कुछ इस पर कि वह ऊंचा दांव लगाकर वोट खरीदने को रजामंद हो जाता है। मुसलमानों के लिए चुनाव पैसे का मामला ही है। उन्हें इस बात में रुचि नहीं होती कि यह सामान्य सुधार के सामाजिक कार्यक्रम का साधन बन सकता है। मुस्लिम राजनीति विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष श्रेणी के जीवन, अर्थात् धनी और निर्धन, पूंजी और श्रम, भूमिपति और पट्टेदार, पुजारी और जन-सामान्य, तर्क और अंधविश्वास के बीच अंतर जैसी बातों पर ध्यान नहीं देती। मुस्लिम

राजनीति अनिवार्यतः मुस्लाओं की राजनीति है और वह मात्र एक अंतर को ही मान्यता देती है – हिंदू और मुसलमानों के बीच मौजूद अंतर। जीवन के किसी भी धर्मनिरपेक्ष तत्व का मुस्लिम समुदाय की राजनीति में कोई स्थान नहीं है, और वे मुस्लिम राजनीतिक जमात के केवल एक ही निर्देशक सिद्धांत के सामने नतमस्तक होते हैं, जिसे मजहब कहा जाता है।

मुसलमानों में इन बुराइयों का होना दुःखद है। किंतु उससे भी अधिक दुःखद तथ्य यह है कि भारत के मुसलमानों में समाज-सुधार का ऐसा कोई संगठित आंदोलन नहीं उभरा जो इन बुराइयों का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर सके। हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। परंतु संतोषजनक बात यह है कि उनमें से अनेक इनकी विद्यमानता के प्रति सजग हैं और उनमें से कुछ उन बुराइयों के उन्मूलन हेतु सक्रिय तौर पर आंदोलन भी चला रहे हैं। दूसरी ओर, मुसलमान यह महसूस ही नहीं करते कि ये बुराइयां हैं। परिणामतः वे उनके निवारण हेतु सक्रियता भी नहीं दर्शाते। इसके विपरीत, अपनी मौजूदा प्रथाओं में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि मुसलमानों ने केंद्रीय असेंबली में 1930 में पेश किए गए बाल विवाह विरोधी विधेयक का भी विरोध किया था, जिसमें लड़की की विवाह-योग्य आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष करने का प्रावधान था। मुसलमानों ने इस विधेयक का विरोध इस आधार पर किया कि ऐसा किया जाना मुस्लिम धर्मग्रंथ द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध होगा। उन्होंने इस विधेयक का हर चरण पर विरोध ही नहीं किया, बल्कि जब यह कानून बन गया तो उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा अभियान भी छेड़ा। सौभाग्य से उक्त अधिनियम के विरुद्ध मुसलमानों द्वारा छेड़ा गया वह अभियान फेल नहीं हो पाया, और उन्हीं दिनों कांग्रेस द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में समा गया। परंतु उस अभियान से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि मुसलमान समाज सुधार के कितने प्रबल विरोधी हैं।

प्रश्न किया जा सकता है कि मुसलमान समाज-सुधार के विरोधी क्यों हैं?

इसका सामान्य उत्तर यह है कि विश्व भर के मुसलमान ही प्रगतिशील नहीं हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है। उनकी सक्रियता के प्रथम स्फुरण के बाद – जिसका स्वरूप निस्संदेह विशाल था और उससे बड़े साम्राज्यों की नींव रखी गई – मुसलमान सहसा ही

सुषुप्तावस्था की स्थिति में जा पड़े। ऐसा लगता है कि उस तंद्रा अवस्था से वे कभी नहीं जगे। इस स्थिति के अध्येताओं ने उनकी इस तंद्रा का कारण यह बताया है कि सभी मुसलमानों में यह धारणा मूलबद्ध रही है कि इस्लाम एक विश्व-धर्म है, जो प्रत्येक काल और परिस्थिति में सभी लोगों के लिए उपयुक्त है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि मुसलमान ने अपने मजहब के प्रति आस्थावान रहते हुए प्रगति नहीं की, वह तेजी से आगे बढ़ रही इस आधुनिक दुनिया में भी जड़वत् रहा है। इस्लाम की एक विशेषता यह रही है कि वह जिन जातियों को दास बनाता है, उनकी स्वभावगत बर्बरता को भी अविचल कर देता है। यह सोच में स्थिर है, निश्चित है और अभेद्य है। यह अपरिवर्तनीय है, और राजनीतिक सामाजिक अथवा आर्थिक परिवर्तनों की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती।

यह सिखाए जाने के कारण कि इस्लाम के बाहर कोई सुरक्षा नहीं है, उसके कानून के बाहर कोई सच्चाई नहीं है और उसके आध्यात्मिक संदेह से हटकर कोई भी सुख नहीं है, मुसलमान अपनी स्वयं की स्थिति के अलावा और कुछ सोच पाने में असमर्थ हो गए हैं, इस्लामी विचार के अलावा और कोई विचार उन्हें सुहाता ही नहीं है। मुसलमान को यह पक्का विश्वास है कि वह पूर्णता के असाधारण स्तर पर पहुंच चुका है, कि वही पूर्ण सत्य का अधिकारी है, वही पूर्ण विद्वान है और यह सत्य ऐसा नहीं है जो किसी पुनरावलोकन का मोहताज हो, अपितु यह पूर्ण सत्य है।

मुसलमानों के मजहबी कानून का उन विविधतापूर्ण मनुष्यों पर जिनसे यह दुनिया बनी है, ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके चिंतन, अनुभूति, विचारों और निर्णय में एकरूपता का प्रादुर्भाव हुआ। यह तर्क दिया जाता है कि यह एकरूपता उन पर शामक प्रभाव डालती है और यह मुसलमानों को केवल हस्तांतरित नहीं की जाती है, बल्कि असहनशीलता की भावना से उन पर थोपी जाती है, जो इतनी कठोर और हिंसात्मक प्रवृत्ति के रूप में मुस्लिम जगत के बाहर अन्यत्र कहीं भी नहीं पाई जाती और जो इस्लाम धर्म की शिक्षा के विरुद्ध विवेकशील विचारधारा को दबाने में संलग्न है। जैसा कि रेनन ने कहा है:

“इस्लाम में गहन आध्यात्मिक और ऐच्छिक एकता है। इसमें मतांधता का आधिपत्य है। यह



एक भरकम कड़ी है जो मानवता ने कभी धारण नहीं की थी.....इस्लाम का मजहब के रूप में अपना सौंदर्य भी है.परंतु मानवीय तर्क की कसौटी पर इस्लाम हानिकारक ही सिद्ध हुआ है। वे मस्तिष्क जिन्हें इसने बाहरी प्रकाश के लिए बंद कर दिया था, निस्संदेह अपनी स्वयं की आंतरिक सीमाओं में बंद थे, परंतु इसने स्वतंत्र चिंतन का दमन किया है। मैं यह तो नहीं कहता कि इसने अन्य धर्मों की तुलना में अधिक सख्ती से यह किया, परंतु अधिक सफलता से तो अवश्य ही किया। जिन देशों को इसने जीता, उन्हें मानव की तर्कवादी संस्कृति के लिए एक बंद क्षेत्र बना दिया। जो तथ्य मुसलमान में निश्चय ही विशिष्ट है, वह है विज्ञान से उसकी घृणा, उसकी यह सोच कि अनुसंधान उपयोगी नहीं है, तुच्छ तथा लगभग कुफ्र है – प्राकृतिक विज्ञान इसलिए अनुपयोगी है कि उसमें खुदा से प्रतिद्वंद्विता की कोशिश होती है। ऐतिहासिक विज्ञान इसलिए कि उसमें इस्लाम से पूर्व काल का वर्णन होता है जिससे प्राचीन विधर्म

पुनर्जीवित हो सकता हैं.....' रेनन ने उपसंहार स्वरूप कहा है:

इस्लाम विज्ञान को शत्रुवत् मानता है, इसलिए वह स्थिर रह गया और स्थिरता बनी रहना खतरनाक है। इस्लाम स्वयं ही अपने दुर्भाग्य का कारण बना है। विज्ञान की हत्या कर उसने अपनी ही हत्या कर ली है और इस आत्महत्या के लिए संसार भर में उसकी भर्त्सना होती

यह उत्तर यद्यपि स्पष्ट है, किंतु सही उत्तर नहीं हो सकता। यदि यही सही होता तो फिर भारत के बाहर सभी मुस्लिम देशों में जो हलचल और अंतःक्षोभ उभर रहा है, निरख-परख की भावना, परिवर्तन की भावना और सधार की आकांक्षा जीवन के हर क्षेत्र में परिलक्षित हो रही है, उसकी सफाई हम क्या देंगे? वस्तुतः तुर्की में जो सामाजिक सुधार हुए हैं, वे बेहद क्रांतिकारी स्वरूप वाले रहे हैं। यदि इन देशों के मुसलमानों की राह में इस्लाम बाधक नहीं बना है तो फिर भारत के मुसलमानों की राह में बाधक क्यों बनेगा? भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक जड़ता का कोई विशेष कारण तो होना ही चाहिए।

वह विशेष कारण क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत के नेशनेलिटी एंड अदर एसेज।

मुसलमानों में परिवर्तन की भावना के हास का कारण उस विशिष्ट स्थिति में खोजना होगा, जो उसे भारत में प्राप्त है। वह एक ऐसे सामाजिक परिवेश में रह रहा है जो मुख्यतः हिंदू है। यह हिंदू वातावरण सदैव चुपचाप, किंतु सुनिश्चित रूप से उस पर अपना प्रभाव डाल रहा है और उस पर हावी हो रहा है। शनैः शनैः स्वयं पर पड़ने वाले इस प्रभाव से बचाव के लिए वह हर उस चीज को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो इस्लामी है और यह जांचने-परखने की भी चिंता नहीं करता कि यह मुस्लिम समाज के लिए लाभदायक है या हानिकारक। दूसरी बात यह है कि भारत में मुसलमान एक ऐसे राजनीतिक वातावरण में रह रहे हैं जो मुख्य रूप से हिंदू प्रभुत्व वाला है। वह ऐसा महसूस करता है कि उसका दमन होगा और राजनीतिक दबाव मुसलमानों को दलित वर्ग बना देगा। यही वह चेतना है जिसे जगाकर वह स्वयं को हिंदू वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक सोच में विलीन होने से बचता है और जो मेरे विचार में भारतीय मुसलमान को अपने अन्य देशों के सहधर्मियों की तुलना में सामाजिक सुधार के मामले में अधिक पिछड़ा बनाए हुए है। उनकी ताकत सीटों और पदों के लिए सतत संघर्ष में ही लगी रही है, जिसके कारण समाज-सुधार से संबंधित सवालों पर सोचने-विचारने का उनके पास समय ही नहीं बच पाता। और यदि कुछ समय मिलता भी है तो वह सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ जाता है, वे इस डर से संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए एकजुट होकर अपनी सामाजिक-धार्मिक एकता को हर कीमत पर अक्षुण्ण रखना चाहते हैं कि हिन्दू और हिन्दुत्व उन पर हावी न हो जायें। भारत के मुस्लिम समुदाय में राजनीतिक गतिरोध के बारे में भी यही स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। मुस्लिम राजनीतिज्ञ जीवन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को अपनी राजनीति का आधार नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए इसका अर्थ हिंदुओं के विरुद्ध अपने संघर्ष में अपने समुदाय को कमजोर करना ही है। गरीब मुसलमान धनियों से इन्साफ पाने के लिए गरीब हिंदुओं के साथ नहीं मिलेंगे। मुस्लिम जोतदार जमींदारों के अन्याय को रोकने के लिए अपनी ही श्रेणी के हिंदुओं के साथ एकजुट नहीं होंगे। पूंजीवाद के खिलाफ श्रमिक के संघर्ष में मुस्लिम श्रमिक हिंदू श्रमिकों के साथ शामिल नहीं होंगे। क्यों? उत्तर बड़ा सरल है। गरीब

मुसलमान यह सोचता है कि यदि वह धनी के खिलाफ गरीबों के संघर्ष में शामिल होता है तो उसे एक धनी मुसलमान से भी टकराना पड़ेगा। मुस्लिम जोतदार यह महसूस करते हैं कि यदि वे जमींदारों के खिलाफ अभियान में योगदान करते हैं तो उन्हें एक मुस्लिम जमींदार के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ सकता है। मुसलमान मजदूर यह सोचता है कि यदि वह पूंजीपति के खिलाफ श्रमिक के संघर्ष में सहभागी बना तो वह मुस्लिम मिल-मालिक की भावनाओं को आघात पहुंचाएगा। वह इस बारे में सजग है कि किसी धनी मुस्लिम, मुस्लिम जमींदार अथवा मुस्लिम मिल-मालिक को आघात पहुंचाना मुस्लिम समुदाय को हानि पहुंचाना है और ऐसा करने का तात्पर्य हिंदू समुदाय के विरुद्ध मुसलमानों के संघर्ष को कमजोर करना ही होगा।

भारतीय रियासतों में राजनीतिक सुधारों के प्रति मुस्लिम नेताओं का रुख यह दर्शाता है कि मुस्लिम राजनीति किस तरह विकृत हो गई है। मुसलमानों और उनके नेताओं ने कश्मीर के हिंदू राज्य में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के लिए प्रचंड आंदोलन चलाया था। वे ही मुसलमान और वे ही नेता अन्य मुस्लिम रियासतों में प्रतिनिधि सरकारों की व्यवस्था लागू किए जाने के घोर विरोधी हैं। इस विचित्र रवैये का कारण बड़ा सीधा सा है। हर मामले में मुसलमानों के लिए निर्णायक प्रश्न यही है कि उसका हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रतिनिधि सरकार से मुसलमानों को सहायता मिली हो तो वे उसकी मांग करेंगे और उसके लिए संघर्ष भी करेंगे। कश्मीर रियासत में शासक हिंदू है, किंतु प्रजाजनों में बहुसंख्यक मुसलमान हैं। मुसलमानों ने कश्मीर में प्रतिनिधि सरकार के लिए संघर्ष इसलिए किया क्योंकि कश्मीर में प्रतिनिधि सरकार से तात्पर्य है हिंदू राज्य से मुस्लिम अवाम के लिए सत्ता का हस्तांतरण। अन्य मुस्लिम रियासतों में शासक मुसलमान, परंतु अधिसंख्यक प्रजाजन हिंदू हैं। ऐसी रियासतों में प्रतिनिधि सरकार का तात्पर्य होगा मुसलमान शासक से सत्ता का हिंदू प्रजा को हस्तांतरण और इसी कारण एक मामले में मुसलमान प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरे में विरोध। मुसलमानों की सोच में लोकतंत्र प्रमुखता नहीं है। उनकी सोच को प्रभावित करने वाला तत्व यह है कि लोकतंत्र प्रमुख नहीं है। उनकी सोच को प्रभावित करने वाला तत्व यह है

कि लोकतंत्र, जिसका मतलब बहुमत का शासन है, हिंदुओं के विरुद्ध संघर्ष में मुसलमानों पर क्या असर डालेगा। क्या उससे वे मजबूत होंगे अथवा कमजोर? यदि लोकतंत्र से वे कमजोर पड़ते हैं तो वे लोकतंत्र नहीं चाहेंगे। वे किसी मुस्लिम रियासत में हिंदू प्रजा पर मुस्लिम शासक की पकड़ कमजोर करने के बजाए अपने निकम्मे राज्य को वरीयता देंगे।

मुस्लिम संप्रदाय में राजनीतिक और सामाजिक गतिरोध का केवल एक ही कारण बताया जा सकता है। मुसलमान सोचते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को सतत संघर्षरत रहना चाहिए। हिंदू मुसलमानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और मुसलमान अपनी शासक होने की ऐतिहासिक हैसियत बनाए रखने का। इस संघर्ष में शक्तिशाली ही विजयी होगा, और अपना शक्तिशाली होना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हर ऐसी चीज का दमन करना अथवा उसे बड़े-खाते डाल देना होगा जो उनकी एकजुटता में दरार डालती

यदि अन्य देशों में मुसलमानों ने अपने समाज को सुधारने का काम शुरू किया है और भारत के मुसलमान ऐसा करने से इंकार करते हैं तो उसका कारण यह है कि अन्य देशों में मुसलमानों का प्रतिद्वंद्वी समुदायों से कोई सांप्रदायिक और राजनीतिक संघर्ष नहीं है, जबकि भारत के मुसलमानों की इससे स्थिति भिन्न ऐसा नहीं है कि रुढ़िवादिता की यह अंध भावना, जो सामाजिक ढांचे को संवारने की आवश्यकता को ही नकारती है, केवल मुसलमानों पर ही हावी है। हिंदुओं पर भी इसका प्रभाव हुआ है। एक समय हिंदुओं ने यह स्वीकार किया था कि सामाजिक क्षमता के बिना अन्य किसी क्षेत्र में स्थाई प्रगति संभव नहीं है, और हिंदू समाज अपनी कुरीतियों के कारण उत्पन्न भ्रांति के वशीभूत कुशलता की स्थिति नहीं पा सका है, अतएव इन कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सतत प्रयास अपेक्षित है। इस तथ्य की मान्यता के फलस्वरूप राष्ट्रीय सोशल कांफ्रेंस का भी गठन हुआ था। कांग्रेस का काम जहां देश के राजनीतिक संगठन में कमजोर पहलुओं को स्पष्ट करना था, वहीं सोशल कांफ्रेंस का काम हिंदू समाज के सामाजिक संगठन के दुर्बल तत्वों का निवारण करना था। कुछ समय तक कांग्रेस और कांफ्रेंस ने एक ही संगठन के दो अंगों की तरह काम किया और उनके अधिवेशन भी एक ही पंडाल में संपन्न होते थे। परंतु शीघ्र ही ये दोनों संगठन दो



दल बन गए। एक राजनीतिक सुधार दल और दूसरा सामाजिक सुधार दल के रूप में उभरा और दोनों के बीच भीषण विवाद छिड़ गया। राजनीतिक सुधार दल ने राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन दिया और सामाजिक सुधार दल ने सोशल कांफ्रेंस का साथ दिया। दोनों संगठन दो विरोधी शिविर बन गए। विवाद का मुद्दा यह था कि क्या समाज-सुधार राजनीतिक सुधार से पहले अपेक्षित है? एक दशक तक इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बना रहा और इस लड़ाई में कोई भी पक्ष विजेता की स्थिति में नहीं आ सका। परंतु यह स्पष्ट हो गया कि सोशल कांफ्रेंस का भाग्य तेजी से उतार पर आ गया है। जिन भद्रजन ने सोशल कांफ्रेंस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि शिक्षित हिंदुओं का बहुमत राजनीतिक प्रगति का पक्षधर है और समाज-सुधार के प्रति उपेक्षा भाव अपनाए हुए है और जब कि कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और जो लोग इसमें शामिल नहीं होते पर उससे सहानुभूति रखते हैं, उनकी संख्या और भी अधिक है, सोशल कांफ्रेंस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। यह उपेक्षा-भाव और समर्थकों की घटती हुई संख्या की स्थिति बनने के बाद शीघ्र ही उसे स्वर्गीय तिलक जैसे राजनीतिज्ञों की सक्रिय विरोध-भावना भी झेलनी पड़ी। कालांतर में राजनीतिक सुधार के पक्षधरों का दल विजयी हुआ और सोशल कांफ्रेंस का अंत हो गया तथा वह विस्मृत हो गई। इसके साथ ही साथ हिंदू समाज से समाज-सुधार की भावना भी विलुप्त हो गई। श्री गांधी के नेतृत्व में हिंदू समाज पागलखाना भले ही नहीं बना, किंतु राजनीति के पीछे तो वह सुनिश्चित रूप से पागल हो ही गया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वराज की पुकार ने समाज-सुधार का ही स्थान प्राप्त कर लिया, जो कभी हिंदुओं के दिमाग में था। राजनीतिक कोलाहल के धूम-धड़ाके में हिंदुओं को यह भी ध्यान नहीं रहा कि ऐसी कोई बुराई भी उनमें है जिसे दूर किया जाना है। जो लोग इस बारे में सजग हैं, वे यह नहीं मानते कि समाज-सुधार भी राजनीतिक सुधार की तरह ही महत्वपूर्ण है और जब उन्हें उसका महत्व स्वीकार करने पर बाध्य किया जाता है तो वे यह तर्क देते हैं कि जब तक पहले राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कर ली जाए, तब तक कोई सामाजिक सुधार नहीं हो पाएगा। वे राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के

लिए इतने अधिक आतुर थे कि समाज-सुधार के पक्ष में प्रचार करने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके विचार में ऐसा करने के लिए राजनीतिक प्रचार से ही समय और शक्ति की कटौती करनी होगी। श्री गांधी के एक प्रवक्ता ने राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण को स्पष्टतया और समुचित तौर पर व्यक्त किया, जब उसने श्री गांधी को यह लिखा:

क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि राजनीतिक सत्ता अर्जित किए बिना कोई भी बड़ा सुधार हो पाना असंभव है? वर्तमान आर्थिक ढांचे को सुधारना होगा? राजनीतिक पुनर्निर्माण के बिना किसी तरह का पुनर्निर्माण संभव नहीं है और मुझे डर है कि परिष्कृत और गैर-परिष्कृत चावल, संतुलित आहार और इस तरह की अन्य बातें प्रलाप मात्र ही हैं।

रानाडे के नेतृत्व में संचालित सोशल रिफॉर्म पार्टी का अंत हो गया और उसने कांग्रेस के लिए मैदान छोड़ दिया। हिंदुओं में एक अन्य दल उभरा, जो कांग्रेस का ही प्रतिद्वंद्वी है। यह हिंदू महासभा है। इसके नाम से तो कोई भी यही आशा करेगा कि इस संगठन का उद्देश्य हिंदू समाज का सुधार करना है। परंतु ऐसा नहीं है। कांग्रेस से इसकी प्रतिद्वंद्विता का समाज सुधार बनाम राजनीतिक सुधार के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस से इसके विवाद का मूल कांग्रेस की मुस्लिम समर्थक नीति में निहित है। इसका गठन मुस्लिम

1. अधिक ब्यौरे के लिए जाति-उन्मूलन (एनिहिलिशन ऑफ कास्ट) विषय पर मेरी लघु पुस्तिका देखिए। 2. हरिजन, 11 जनवरी, 1936

अतिक्रमण के विरुद्ध हिंदू अधिकारों के रक्षार्थ हुआ था और इस नाते इसकी दृष्टि हमेशा राजनीतिक आंदोलनों, गतिविधियों, सीटों और पदों पर लगी रहती है। सामाजिक सुधार के लिए इसके पास कोई समय नहीं है। हिंदुओं का एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए उत्सुक संगठन होने के नाते यह संस्था नहीं चाहती कि उसके तत्वों में कोई मत वैभिन्न्य हो, जबकि समाज-सुधार का काम अपने हाथ में लेने से यह हो सकता है। हिंदू जनता को संगठित करने के लिए हिंदू महासभा सभी सामाजिक बुराइयों के यथावत् बने रहने की पीड़ा झेलने को भी तैयार है। हिंदुओं की एकता हेतु यह 1935 के अधिनियम में परिकल्पित संघीय व्यवस्था का स्वागत करने को तैयार है, भले ही उसमें अनेक खामियां और असमानताएं हों। उसी

उद्देश्य से हिंदू महासभा भारतीय रियासतों को भी उनके प्रशासन को यथावत् रखते हुए सहने को तैयार है। इसके अध्यक्ष का यह युद्ध-घोष रहा है कि हिंदू रियासतों को मत छोड़ो। हिंदू महासभा का यह रवैया मुसलमानों के रवैए से भी अधिक विचित्र है। हिंदू रियासतों में प्रतिनिधि सरकारें हिंदुओं को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगी। तो फिर हिंदू महासभा के अध्यक्ष इसका विरोध क्यों करते हैं? संभवतः इसलिए कि इससे मुसलमानों का लाभ होगा, जो वह सहन नहीं कर सकते।

केंद्रीय विधान सभा में 1939 के मुस्लिम विवाह-अधिनियम को समाप्त करने के बारे में हुई बहस से बेहतर उदाहरण इस बारे में कोई और नहीं हो सकता कि हिंदू और मुसलमान अपने-अपने शक्ति संतुलन के अनुरक्षण की चिंता में कितनी दूरी तक जा सकते हैं।

1939 से पूर्व कानून यह था कि मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाहित पुरुष अथवा महिला के स्वधर्म-त्याग से विवाह उस स्थिति में भंग हो जाता था, जबकि कोई विवाहित मुस्लिम महिला अपना धर्म बदल लेती थी। ऐसे में वह अपने नए धर्म के अनुयायी किसी भी पुरुष से विवाह करने को स्वतंत्र हो जाती थी। साठ वर्ष तक भारत की सभी अदालतों में इस कानून का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया।

1939 के अधिनियम VIII द्वारा इस कानून को रद्द कर दिया गया था, जिसकी धारा 4 इस प्रकार है:

किसी विवाहित मुस्लिम महिला द्वारा इस्लाम धर्म के परित्याग से जबरदस्त खान बनाम उसकी पत्नी के मामले में 1870 में उत्तर-पश्चिम प्रांत के हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय सबसे पहला निर्णय था। अथवा उसके इस्लाम धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण से स्वतः ही उसका विवाह-विच्छेद नहीं होगा।

बशर्ते कि ऐसे धर्म परित्याग अथवा धर्मांतरण के बाद महिला धारा 2 में उल्लिखित किसी भी आधार पर अपने विवाह-विच्छेद के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की हकदार होगी, बशर्ते यह भी कि इस धारा के उपबंध उस महिला के मामले में लागू नहीं होंगे, जिसने अपना धर्म त्यागकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया था और बाद में फिर अपने पूर्व धर्म को अपना लिया है। इस अधिनियम के अनुसार, किसी विवाहित मुस्लिम महिला द्वारा कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेने

मात्र से ही उसका विवाह भंग नहीं होगा। जो कुछ उसे प्राप्त होता है, वह तलाक लेने का अधिकार ही है। यह देखकर परेशानी ही होती है कि धारा 2 में न तो धर्मांतरण को और न ही स्वधर्म त्याग को तलाक का आधार माना गया है। इस कानून का परिणाम यह है कि विवाहित मुस्लिम महिला को अपने आत्मबोध की आजादी नहीं है और हमेशा के लिए अपने उस पति से बंधी रहती है, जिसकी धार्मिक आस्था उसके लिए पूर्णतः घृणास्पद है। इस परिवर्तन के समर्थन में जो आधार पेश किए गए उन पर भी ध्यान देना अभीष्ट होगा। इस विधेयक को पेश करने वाले काजी काजमी एम.एल.ए. ने परिवर्तन के पक्ष में एक नितांत विलक्षण तर्क पेश किया। विधेयक को पेश करने के संदर्भ में अपने भाषण में उन्होंने कहा "स्वधर्मत्याग को किसी भी अन्य धर्म के समान इस्लाम ने एक घोर अपराध माना है, जो प्रायः राज्य के विरुद्ध अपराध जैसा ही है। यह प्रावधान रखना इस्लाम धर्म के लिए कोई गौरव की बात नहीं है। यदि हम किसी भी राष्ट्र के पुराने अधिनियमों को देखें तो पाएंगे कि ऐसे ही प्रावधान अन्य संहिताओं में भी उपलब्ध हैं। पुरुष के लिए अधिक कठोर दंड, अर्थात् मृत्युदंड, जबकि महिलाओं के लिए मात्र कारावास की व्यवस्था थी। यह मुख्य प्रावधान इसलिए था कि क्योंकि यह पाप है, अपराध है, इसके लिए दंड दिया जाना चाहिए। इसलिए महिला को पत्नी का अधिकार गंवाना पड़ता था। मात्र यही नहीं, अपितु समाज में अपने सभी स्तरों से उसे वंचित होना पड़ता था। उसे अपनी संपत्ति और नागरिक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता था। परंतु हमने यह पाया है कि 1850 में ही एक अधिनियम पारित किया गया था, जो 'जातीय अयोग्यता निवारण अधिनियम 1850 का अधिनियम-21' के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम द्वारा वह प्रावधान रद्द कर दिया गया जिससे कि महिला द्वारा स्वधर्म त्याग करने पर उसे अपने नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। अब उसे अपने नागरिक अधिकारों या अपनी संपत्ति की जब्तगी, अथवा उत्तराधिकार अथवा इसी तरह के किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सवाल केवल यह है कि विधान से उसे यह सहायता मिली, फिर उसे विचार की स्वतंत्रता मिली। उसे यह स्वतंत्रता मिली कि वह अपनी पसंद के किसी धर्म को ग्रहण कर सकती है और जब्तगी की वह धारा हटा दी गई है, जिससे। उसे कष्ट उठाना पड़ता



था और धर्म-परिवर्तन करने पर अवरोध उत्पन्न होता था। सवाल यह है कि इसके बाद उस महिला के पत्नित्व के अधिकार पर हम कहां तक अंकुश लगा सकते हैं। समाज में उसकी पत्नी-स्थिति महत्वपूर्ण है। वह किसी परिवार का अंग होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके अन्य रिश्ते व संबंध भी होते हैं। यदि उसका मन-मस्तिष्क उदार व स्वतंत्र है, तो हो सकता है कि वह उसी पुराने धर्म में बने रहना पसंद न करे। यदि वह अपना धर्म बदलती है तो हम अपने आधुनिक विचारों के अनुरूप उस पर और दंड क्यों थोपें कि वह अपने पति की पत्नी नहीं रहेगी। मेरा यह विनम्र मत है कि अब जब हम विचार-स्वातंत्र्य और धर्म-स्वातंत्र्य के पक्षधर बनते हैं और जब हम विभिन्न समुदायों के बीच अंतर्विवाह की वकालत करते हैं तो हमारे लिए ऐसे प्रावधान का समर्थन करना अनुचित होगा कि आस्था या धर्म बदलने मात्र से वह अपने पति की पत्नी होने के अधिकार से भी वंचित हो जाए। अतएव आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से इस विपरीत सुझाव का समर्थन नहीं कर सकते कि धर्मत्याग से उसे अपने पति की पत्नी होने के अधिकार से वंचित होना पड़े। परंतु यह तो तर्क का एक भाग ही रहा।

“पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 की धारा 32 के अनुसार, कोई भी विवाहित महिला इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है कि उसका पति पारसी नहीं रहा....

इससे दो बातें स्पष्ट हैं। पहली यह कि विवाह-विच्छेद का यह आधार किसी धार्मिक विचार अथवा धार्मिक भावना पर आधारित नहीं है, क्योंकि यदि धर्मांतरण के बाद पुरुष अथवा महिला दोनों में से किसी को भी विवाह भंग करने के लिए अभियोग का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि वादी को ही यह शिकायत है कि दूसरे पक्ष ने धर्मांतरण कर लिया है, उसे विवाह भंग करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य समुदायों के बारे में, हम नेटिव कनवर्ट्स मैरिज डिस्सोल्यूशन एक्ट-1886 अधिनियम XXI से विवाह संबंधों पर धर्मांतरण के प्रभाव का जायजा ले सकते हैं। यह भारत के सभी समुदायों पर लागू होता है और यह कानून इस तथ्य को मान्यता देता है कि किसी भारतीय के मात्र ईसाई हो जाने से ही विवाह नहीं टूट जाएगा, बल्कि उसे न्यायालय में जाना होगा, जहां वह

यह कह सके कि दूसरे पक्ष को जिसने धर्मांतरण नहीं किया है, उसके प्रति वैवाहिक दायित्वों को निभाना चाहिए। तब उन्हें एक वर्ष का समय दिया जाता है और न्यायाधीश उन्हें निर्देश देता है कि कुछ अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वे एक-दूसरे से बातचीत करेंगे, ताकि उनमें वैवाहिक संबंध फिर से बहाल हो सके, और यदि वे सहमत नहीं होते तो अपवित्रीकरण के आधार पर विवाह भंग हो जाता है। विवाह निस्संदेह टूट जाता है, परंतु आस्था या धर्म बदल लेने मात्र के आधार पर नहीं। अतएव भारत में प्रत्येक समुदाय ने इस मान्य सिद्धांत के अपनाया है कि दूसरा धर्म ग्रहण कर लेने मात्र से ही विवाह-विच्छेद को नहीं माना जा सकता।’ असंबली के एक अन्य मुस्लिम सदस्य और विधेयक के पक्षधर सैयद गुलाम बिख नैरांग ने तो और भी अधिक खुलकर तथा बिना किसी लाग-लपेट के अपनी बात रखी। विधेयक के सिद्धांत के समर्थन में उन्होंने कहा।

बहुत लंबे समय से ब्रिटिश भारत में अदालतों ने बेहिचक और बिना किसी शर्त के यह निर्णय दिया है कि समस्त परिस्थितियों में स्वधर्म-त्याग में स्वतः और तत्काल, और बिना किसी न्यायिक कार्यवाही या न्यायालय के निर्णय अथवा किसी अन्य धार्मिक औपचारिकता की बाधा के बिना ही, वैवाहिक स्थिति समाप्त हो जाती है। न्यायालय यही रुख अपनाते रहे हैं। प्रायः इस मुद्दे पर हनफी न्यायविदों के तीन विशिष्ट दृष्टिकोण रहे हैं। इनमें से एक दृष्टिकोण को, जिसे बोखारा न्यायविदों का मत बताया जाता है, स्वीकार कर लिया गया था, उसे पूर्ण रूप में नहीं, बल्कि मेरी राय में उसे तोड़-मरोड़ और काट-छांटकर अपनाया गया है। बोखारा मत के बारे में श्री काजमी और कुछ अन्य वक्ता पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। बुखारा न्यायविदों का कहना है कि विवाह धर्म बदल लेने से टूट जाता है। वास्तव में मैं और अधिक ठोस शब्दों में इसे स्पष्ट कर रहा हूँ — मैं अधिकृत रूप से यह कह सकता हूँ कि बुखारा मत के अनुसार विवाह भंग नहीं होता, बल्कि विवाह संबंध निलंबित होता है। विवाह निलंबित हो जाता है, किंतु पत्नी को तब तक हिरासत अथवा किसी की देखरेख में नजरबंद रखा जाता है जब तक कि वह पश्चाताप नहीं कर लेती और पुनः इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर लेती, और फिर उसे पति से निकाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका निकाह केवल निलंबित हुआ

था, समाप्त अथवा रद्द नहीं। दूसरे मत के अनुसार, धर्मांतरण कर लेने पर मुस्लिम महिला अपने पति की पत्नी नहीं रहती, बल्कि उसकी बंधक स्त्री हो जाती है। एक धारणा जो इसी दृष्टिकोण की परिणति है, यह है कि यह आवश्यक नहीं कि वह अपने पूर्व पति की बंधक स्त्री रहे, अपितु वह समग्र मुस्लिम समुदाय की बंधक स्त्री हो जाती है और कोई भी व्यक्ति उसे एक बंधक स्त्री के तौर पर नौकर रख सकता है। तीसरा मत समरकंद और बलख के उलेमा का है, जिसके अनुसार ऐसे धर्मांतरण से वैवाहिक बंधन प्रभावित नहीं होता और महिला अपने पति की पत्नी बनी रहती है। ये तीन मत हैं। प्रथम मत के एक अंश बुखारा मत को अदालतों ने मान्यता दी और एक के बाद एक निर्णय इसी अंश पर आधारित रहे। "इस सभा को यह भली भांति विदित है कि यह एकमात्र दृष्टांत नहीं है, जहाँ विधान के द्वारा, न्यायिक भूल का परिमार्जन करने की चेष्टा की गयी है। बल्कि दूसरे अनेक मामले भी हैं; जहाँ न्यायिक भूलें हुई हैं अथवा जहाँ न्यायिक अभिमत विवादास्पद रहा है अथवा विधि में ही अस्पष्टता या अनिश्चयता रही है। न्यायिक अभिमतों में सन्निहित भूलों का विधान द्वारा परिमार्जन निरंतर किया जाता रहा है। परन्तु इस विशिष्ट मामले में तो भूल दर भूल ही नहीं हुई, भूलों की त्रासदी हुई है। निश्चय ही, यह अनुभव किया जाना चाहिए कि विधेयक के लिए मेरे प्रस्ताव का कदापि यह उत्तर नहीं हो सकता है कि चूंकि उच्च न्यायालयों ने मेरे विपरीत निर्णय दिए हैं, इसलिए इस सभा में उपस्थित होकर इनके संदर्भ में विधेयक बनाने का मेरा

आग्रह अनधिकार चेष्टा होगी। संशोधन की गूढ़ता को ध्यान में रखते हुए, उसके पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्क बहुत ही तथ्यहीन थे। श्री काजमी यह नहीं समझ सके कि यदि पारसी ईसाई और मुस्लिमों के तलाक से सम्बन्धित विधियों में भिन्नताएं हैं, तब उस स्थिति में धर्मांतरण के प्रामाणिक साबित हो जाने पर, चूंकि मुस्लिम कानून पहले का है, औचित्यपूर्ण बात तो यह होती कि मुस्लिम कानून को पीछे धकेलने की बजाय पारसी और ईसाईयों के कानून को ही उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाया जाता। श्री नैरंग को यह पूछना चाहिए था कि मुस्लिम विधिवेत्ताओं की विविध विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में क्या यह अधिक न्यायसंगत नहीं होगा कि उस अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण

को ही स्वीकार किया जाय, जो मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करता है तथा उस असभ्य दृष्टिकोण को अस्वीकार किया जाय जो उन्हें गुलाम बनाता है। जो भी हो, कानूनी तों का परिवर्तन के वास्तविक उद्देश्यों से कुछ लेना देना नहीं था। वास्तविक उद्देश्य तो किसी महिला का दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना था ताकि जल्दबाजी में किसी दूसरे धर्म के धर्मावलम्बी उसे नए समुदाय में सम्मिलित कर उसका विवाह न कर दें और वह अपने मूल समुदाय में वापस न हो सके। मुस्लिम महिलाओं के हिन्दू धर्म में धर्मांतरण और हिन्दू महिलाओं के मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण का सामाजिक तथा राजनैतिक परिणाम बड़ा भयावह हुआ करता है। इसका कुछ प्रभाव दोनों समुदायों के संख्यात्मक संतुलन पर पड़ता है। महिलाओं का अपहरण कर यह असंतुलन उत्पन्न किया जाता रहा है। इसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ राष्ट्रीयता की स्वाभाविक अंकुरण और संरक्षण स्थली होती हैं। महिलाओं का धर्मांतरण और तदनुसार उनका विवाह करा देना, मुस्लिमों के द्वारा हिन्दुओं, और हिन्दुओं के द्वारा मुस्लिमों के प्रति सही में विध्वंसकारी कृत्य माना गया है, जिसका उद्देश्य उनके संख्यात्मक अनुपात में परिवर्तन करना रहा है। महिलाओं के अपहरण की यह घृणित प्रथा पशुओं की चोरी की घटनाओं की तरह ही सामान्य हो गयी थी और उसका स्पष्ट प्रभाव सामुदायिक संतुलन पर पड़ रहा था। अतः इसको रोकने के लिए प्रयास किया जाना अपेक्षित था। इस विधेयक के पीछे वास्तविक कारण यही था, जो इस विधेयक की धारा 4 के दो प्रावधानों को देखने से स्पष्ट हो जाता है। परंतुक (1) में हिन्दू, मुसलमानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं कि मुस्लिम महिला का हिन्दू धर्म में धर्मांतरण के बावजूद उसके मुस्लिम पति से उसका सम्बन्ध विच्छेद नहीं होगा। परंतुक (2) के अनुसार मुस्लिम हिन्दुओं को यह सुविधा प्रदान करते हैं कि यदि वे विवाहित हिन्दू महिला का धर्मांतरण करें तथा उस महिला का एक मुसलमान से विवाह कर दिया जाये तो, अगर मुस्लिम धर्म को वह महिला त्याग देती है, उस स्थिति में उसका मुस्लिम पति से सम्पन्न हुआ विवाह भी विघटित समझा जाएगा, तथा वह, हिन्दू समुदाय में पुनः राष्ट्रवाद के बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।



इस विषय पर ऐसे ऑन नेशनैलिटी में रेनन के विचार देखिए। इस प्रकार कानूनी परिवर्तन के पीछे संपूर्ण मंशा संख्यात्मक अनुपात को संतुलित रखने की ही है, और मात्र इसी उद्देश्य के लिए महिलाओं के अधिकार की बलि चढ़ा दी गयी। इस बुराई के दो और पहलू हैं, जिन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

एक पहलू यह है कि एक के द्वारा किए जा रहे सामाजिक सुधारों को दूसरे के द्वारा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा सामाजिक सुधार यदि दूसरे समुदाय की प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि करता है तब यह तत्काल सामुदायिक विद्वेष का कारण बन जाता है।

स्वामी श्रद्धानन्द एक बड़ी विचित्र घटना का उल्लेख करते हैं। यह घटना उपर्युक्त मानसिकता का सटीक चित्रण करती है। 26 अप्रैल 1926 के लिबरेटर में अपने संस्मरण में उन्होंने इस घटना के सम्बन्ध में यह लिखा है:

श्री रानाडे इस सामाजिक सभा को, जिसे 'नेशनल' कहा गया, मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वहां मौजूद थे। यह सभा अपने प्रारम्भ से ही सभी क्षेत्रों में हिन्दुओं की एक सभा थी। इस राष्ट्रीय सामाजिक सभा में बरेली के मुफ्ती साहेब एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि थे। सभा का आरम्भ एक हिन्दू प्रतिनिधि तथा मेरे उस प्रस्ताव से हुआ जिसका सम्बन्ध बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह से था। सनातनी पण्डितों ने मेरे इस प्रस्ताव का विरोध किया। तब मुफ्ती ने सम्बोधित करने हेतु आज्ञा मांगी। इस पर स्व. बैजनाथ ने यह कहा कि प्रस्ताव का सम्बन्ध चूंकि केवल हिन्दुओं से है, उनके बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस पर मुफ्ती आग-बबूला हो गए।

“सभापति के लिए बचाव को कोई रास्ता नहीं था, अतः मुफ्ती साहेब को अपनी बात रखने का अवसर दे दिया गया। मुफ्ती साहेब का तर्क था कि चूंकि हिन्दू शास्त्र पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए इस पर बल दिया जाना धर्मसम्मत बात नहीं है। दोबारा, जब धर्मान्तरित ईसाइयों और मुसलमानों का हिन्दू धर्म में पुनः मांतरण के विषय पर संकल्प आया तब मुफ्ती साहेब ने तर्क प्रस्तुत कर दिया कि जब किसी व्यक्ति ने हिन्दू धर्म का परित्याग कर दिया है तब उसकी पुनर्वापसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक दूसरा उदाहरण अछूतों की समस्याओं

के प्रति मुसलमानों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। मुसलमान हमेशा से ही दलित समुदायों को तृष्णा से देखते आए हैं तथा यह हिन्दू और मुसलमानों के बीच ईर्ष्या का कारण बना रहता है क्योंकि हिन्दुओं को यह आशंका होती है कि दलित समुदायों को अपने में समाहित कर मुसलमान कहीं अधिक शक्तिशाली न बन जाएं। 1909 में मुसलमानों ने एक दृढ़ कदम उठाया। उन्होंने दलित समुदायों को मतदाता सूचियों में बतौर हिन्दू नामांकित किए जाने पर आपत्ति उठायी। वर्ष 1923 में श्री मोहम्मद अली ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से अपने भाषण में 1909 ई. में मुसलमानों के प्रस्थापित दृष्टिकोण से अधिक आगे बढ़कर नयी प्रतिस्थापनाएं की। उन्होंने कहा अलामस और पीपल के दरख्तों और बाजे-गाजे वाले जुलूसों के सम्बन्ध में बचकाना विवाद हुआ करते हैं, किंतु एक प्रश्न जरूर है कि यदि साम्प्रदायिक गतिविधियों को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझा नहीं लिया जाता है तो उससे सहज ही गैर-दोस्ताना व्यवहार की जमीन तैयार हो जाती है। यदि हिन्दू दलितों को तेजी से समाहित नहीं कर लेते तब यह उन समुदायों के धर्मांतरण का प्रश्न बन जाएगा। ईसाई उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, और इस सम्बन्ध में प्रश्न कोई नहीं उठाता है। किन्तु किसी मुस्लिम सामाजिक संगठन को इस कार्य के लिए जैसे ही गठित किया जाएगा, हिन्दू समाचारपत्रों में हो-हल्ला शुरू हो सकता है। एक अत्यन्त ही धनाढ्य तथा प्रभावशाली सज्जन ने, जो दलितों के धर्मांतरण के लिए व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण करने वाली संस्था का गठन कर सकते हैं, मुझे बताया है कि अग्रणी हिन्दुओं के साथ सहमति हो सकती है कि देश को अलग-अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाय जिनमें धर्मांतरण का कार्य मुसलमान और हिन्दू अलग-अलग कर सकें। प्रत्येक सम्प्रदाय वर्षवार, अथवा इससे अधिक अवधि के भीतर, कितने लोगों का धर्मांतरण कर सकता है या अपने भीतर समाहित कर सकता है, इसकी तफसील तैयार करे। इन तफसीलों का यह आधार होगा कि प्रत्येक संप्रदाय कितने कार्यकर्ता और कितना धन लगा सकता है और पूर्व वर्ष के इनके वास्तविक आंकड़ों के आधार पर इनकी जांच की जा सकती है। इस विधि से दोनों ही सम्प्रदाय अपने में समाहित करने या धर्मांतरण करने का कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, या अन्य सुधारवादी कार्य भी वे कर सकेंगे, और उनके बीच टकराव की कोई सम्भावना

नहीं रहेगी। मैं इस सझाव को फिलहाल ईमानदारी और स्पष्टता के साथ रख सकता हूँ, परन्तु मेरे हिन्दू भाई इस सुझाव के प्रति कैसा रुख अपनाएँगे, यह मैं नहीं कह सकता। मैं अपनी ओर से जो कुछ भी कर रहा हूँ वह यह कि बड़ौदा स्टेट में तथा मध्य प्रान्त के गोंड लोगों के बीच काली पूजा का हमने जो रूप देखा है, वह हम सभी के लिए अपमानजनक है। यदि हिन्दू लोग दलित समुदायों को अपने में समाहित नहीं कर लेते हैं, तब दूसरे उन्हें अपने धर्म में धर्मांतरित कर लेंगे और यही किया भी जाना चाहिए और इसी परिस्थिति में कट्टरवादी हिन्दू भी उन्हें अछूत मानना छोड़ेंगे। धर्मांतरण एक शक्तिशाली रासायनिक प्रक्रिया की तरह उनका कार्याकल्प करता हुआ प्रतीत होता है। पर क्या यह धर्मांतरण का प्रोत्साहन नहीं है? इसका अन्य पहलू वे तैयारियाँ हैं, जो हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के विरुद्ध जोर-शोर से कर रहे हैं। यह दो राष्ट्रों के बीच सामाजिक युद्धास्त्रों की होड़ की तरह है। यदि हिंदुओं के पास काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है, तो मुसलमानों के पास भी एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय होना ही चाहिए। हिन्दू यदि शुद्धि आन्दोलन आरम्भ करते हैं, तो मुसलमान निश्चय ही 'तबलीग' आन्दोलन छोड़ेंगे। हिन्दू यदि संगठन बनाते हैं तो इसके जवाब में मुस्लिम तनजीमश् स्थापित करते हैं। अगर हिन्दुओं का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, तब मुसलमानों का भी मुस्लिम खाकसार है। सामाजिक युद्धास्त्रों तथा सज्जाओं की होड़ को जिस दृढ़ता और जिन आशंकाओं से संचालित किया जा रहा है, वह राष्ट्रों के बीच संघर्ष का लक्षण है। प्रतीत होता है कि दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे की तैयारियों की समीक्षा करते रहते हैं और युद्ध जैसी तैयारियाँ कर रहे हैं। मुसलमान समझते हैं कि हिन्दू उन्हें अधीनस्थ बना रहे हैं और हिन्दू अनुभव करते हैं कि मुसलमान उन पर पुनर्विजय करना चाह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही युद्ध की तैयारी में संलग्न हैं और एक दूसरे की तैयारियों पर नजर रखते हैं।

इस प्रकार की स्थिति अनिष्टकारी होगी। यह एक दुश्चक्र है। मुसलमान हिन्दुओं के सशक्त होने पर अपने लिए खतरा महसूस करते हैं। खतरे से निपटने के लिए वे अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। फिर उनकी स्थिति से संतुलन प्राप्त करने के लिए यही सब हिन्दू करते हैं। जैसे-जैसे ये तैयारियाँ बढ़ती हैं, उनमें संदिग्धता, षड्यंत्र और गोपनीयता भी बढ़ती

जाती है। शांतिपूर्वक सुलझाव की सम्भावनाएँ शुरू में ही नष्ट हो जाती हैं, और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति इससे भयाक्रांत रहता है तथा इसके लिए तैयारी भी करता रहता है, दोनों सम्प्रदायों के बीच युद्ध अवश्यम्भावी प्रतीत होता है। इस तरह जिन परिस्थितियों में हिन्दू और मुसलमान अपने को पाते हैं, सिवाय इसके कि एक दूसरे की चुनौती से निबटने की तैयारियाँ वे करते रहें, और कर ही क्या सकते हैं? यह संघर्ष अस्तित्व बनाए रखने के लिए है, और मुख्य मुद्दा भी यही है, न कि अस्तित्व का स्तर तथा गुणवत्ता।

निश्चय ही इस चर्चा से दो तथ्य उभरते हैं। एक तो यह है कि, हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को खतरे की दृष्टि से देखते हैं और दूसरा यह कि खतरों का सामना करने के क्रम में, सामाजिक कुरीतियों को, जिनसे कि वे पीड़ित हैं, दूर करने के उद्देश्य को ही उन्होंने टाल दिया है। क्या यह वांछनीय स्थिति है? यदि यह वांछनीय नहीं है, तब इसे कैसे खत्म किया जाए?

यह कोई नहीं कह सकता कि सामाजिक सुधारों से सम्बन्धित समस्याओं को दरकिनार कर देना औचित्यपूर्ण बात होगी। स्वस्थ राजनीतिक संरचना की यह अपेक्षा होती है कि सामाजिक कुरीतियों का उत्पीड़न और अन्याय का प्रतीक बन जाने के पहले ही, उन्मूलन कर दिया जाये क्योंकि कहीं भी आर्थिक और सामाजिक कुरीतियाँ ही पतन अथवा क्रांति की जनक होती हैं। यह विवाद का विषय हो सकता है कि पहले राजनीतिक पुनःनिर्माण हो या पहले सामाजिक पुनर्निर्माण हो। किन्तु इस तथ्य पर मतांतर नहीं हो सकता कि राजनीतिक सत्ता का उपयोग, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के निमित्त किया जाना चाहिए। राजनीतिक सत्ता के लिए किया जा रहा पूरा संघर्ष बेमानी और व्यर्थ ही होगा यदि इस संघर्ष के सम्बन्ध में यह अनुभूति न हो कि राजनीतिक सत्ता के अभाव में ही सामाजिक कुरीतियों के कारण हमारे समाज में घुन लग गया है और वह नष्ट होता जा रहा है। किन्तु मान लीजिए कि हिन्दू और मुसलमान किसी प्रकार राजनीतिक सत्ता के स्वामी बन जाते हैं तो इससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे इस सत्ता का उपयोग सामाजिक पुनः निर्माण के लिए करेंगे ही? इस सम्बन्ध में कोई आशा नहीं की जा सकती। जब तक मुसलमान और हिन्दू एक दूसरे के लिए खतरा ही बनते रहेंगे, उनका परा ध्यान खतरों का सामना करने



में ही बंटा रहेगा। मुसलमानों के खिलाफ हिन्दुओं का और हिन्दुओं के खिलाफ मुसलमानों का संगठित होते रहना जब तक कायम है, तब तक निश्चित रूप से सामाजिक पुनःनिर्माण की बात दबी रहेगी। न तो हिन्दू और न ही मुसलमान आर्थिक और सामाजिक कुरीतियों के बहते हुए नासूर की ओर अपना ध्यान फेरेंगे जिसकी कि तत्काल आवश्यकता है क्योंकि उनकी समझ में सामाजिक पुनः निर्माण का कदम, निश्चित रूप से मतभेद और विभाजन पैदा कर देगा जब कि एक दूसरे के सम्प्रदाय के खतरों का सामना करने के लिए उन्हें अपनी एकता ही मजबूत करना चाहिए। यह निर्विवाद है कि जब तक एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को खतरा मानता रहेगा, तब तक कोई सामाजिक प्रगति नहीं की जा सकेगी और दोनों के ही विचारों और कार्यकलापों पर रूढ़िवादिता का बोलबाला रहेगा।

कब ये खतरे समाप्त होंगे? जब तक हिन्दू और मुसलमान एक ही संविधान के अंतर्गत एक ही देश में रहते रहेंगे, यह खतरा कायम रहेगा क्योंकि दोनों सम्प्रदायों पर एक संविधान लागू होने में यह आशंका है कि अपने आरम्भ के काल में स्थापित संतुलन के समाप्त होने पर — जो अवश्यंभावी है — मुसलमान और हिन्दू एक दूसरे को फिर अपने लिए खतरा समझने लगेंगे। यदि यही होना है तो स्पष्ट उपचार पाकिस्तान ही है। खतरों के मुख्य कारक को यह समाप्त कर देता है। पाकिस्तान का निर्माण हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही एक दूसरे की गुलामी और अनधिकृत आक्रमण की आशंका से मुक्त कर देता है। इससे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए अलग-अलग संविधान का प्रावधान हो जाता है, जिससे दैनिक जीवन में संतुलन कायम रखने के लिए चल रहे लगातार संघर्ष का आधार ही समाप्त हो जाता है। सामाजिक महत्व के अत्यावश्यक विषयों को, जिन्हें इस समय वे बक्से

में बंद कर देने को बाध्य हैं, लेकर अब उन्हें अपनी जनता के जीवन में सुधार लाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आखिर स्वराज्य के लिए यह जो संघर्ष चलाया जा रहा है, उसका लक्ष्य भी तो यही सुधार है। किसी ऐसी व्यवस्था की अनुपस्थिति में हिन्दू और मुसलमान ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया करते रहेंगे, मानों वे दो अलग-अलग राष्ट्र हैं। दोनों आशंकित रहेंगे कि दूसरा उन पर विजय तो प्राप्त नहीं कर लेता। सामाजिक पुनः निर्माण के बजाय हमेशा आक्रमण की तैयारियों को तरजीह दी जाती रहेगी तथा इस प्रकार सामाजिक यथास्थिति बनी रहेगी। किसी को इस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बहुत ही स्वाभाविक बात है। जैसा कि जार्ज बर्नार्ड शॉ ने इंगित किया है।

“एक विजित राष्ट्र कैंसर-ग्रस्त मनुष्य की तरह होता है वह अन्य किसी विषय पर नहीं सोच सकता है। एक स्वस्थ राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता के विषय में उसी प्रकार अचेत रहता है जिस प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य अपनी हड्डियों के विषय में। परन्तु यदि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता को आप भंग कर देते हैं, तब उसकी चिंता इसे पुनः स्थापित करने की होगी। वह तब किसी सुधारक की बात पर ध्यान नहीं देगा, किसी दार्शनिक की बात नहीं सुनेगा, किसी धर्मोपदेशक की बात नहीं मानेगा, जब तक कि उसकी राष्ट्रीयता की मांग स्वीकृत नहीं हो जाती। वह एकता स्थापित करने और मुक्ति प्राप्त करने के कार्यों के अतिरिक्त सभी अत्यावश्यक कार्यों की अवहेलना करेगा। जब तक हिंदुओं से अपने को अलग रखने की मांग करने वाले मुसलमानों का पृथक राष्ट्र के रूप में एकीकरण नहीं हो जाता, और अपने ऊपर दूसरे के आधिपत्य हो जाने की आशंका से दोनों को ही मुक्ति नहीं मिल जाती, सामाजिक निष्क्रियता की इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता। इस बात में संदेह की गुंजाइश नहीं है।

**Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment**

****Azadi ka Amrit Mahotsav****

आठ साल बेमिसाल

Press Note on

Achievements of the Department

Date: 06.06.2022

On the occasion of celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav to Commemorate 75 years of the independence and glorious journey of achieving the vision of Aatmanirbhar Bharat, Honorable Minister of Social Justice and Empowerment Ministry, had briefed about the achievements of the Department of Social Justice and Empowerment on 06th June, 2022 at 11:00 am in the press conference held at Dr. Ambedkar International Centre (DAIC).

Honorable Minister informed that the Department is endeavoring to achieve the vision of building an inclusive society by empowering socially, educationally and economically marginalized sections like Scheduled castes, Other Backward Classes, Senior Citizens, Victims of the Alcoholism and Substance Abuse, Transgender Persons, Beggars, De-notified and Nomadic Tribes (DNTs), Economically Backward Classes (EBCs) and Economically Weaker Section (EWS). This Department has been implementing various schemes for upliftment of members of the afore said target groups.

Following are the achievements of the Department from financially year 2014-15 to 2021-22:-

1) Various schemes for educational upliftment of Scheduled Castes (SCs), Other Backward Classes (OBCs), Denotified and Nomadic Tribes (DNTs) have been implementing. An

amount of Rs. 36164 Crore has been spent since the financial year 2014-15 and over 11 Crore students have been benefited by the following schemes:-

- Pre-Matric Scholarship to SC Students and Others: 224.70 lakh beneficiaries and expenditure approx. Rs. 3280.07 crore.
- Post Matric Scholarship to the SC Students: 434.29 lakh beneficiaries and expenditure approx. Rs. 24968.55 crore.
- A component of Pradhan Mantri – Anusuchitjati Abhyuday Yojana (PM-AJAY): Babu Jagjivan Ram Chhtrawas Yojana: Rs. 342.5 crore sanctioned for construction of 173 hostels, which benefitted about 15800 beneficiaries.
- Higher Education For Young Achievers (SHREYAS):
 - Free Coaching Schemes for SC and OBC Students (FBS) – approx. 19347 beneficiaries and expenditure approx. Rs. 91.37 Crore since 2014-15.
 - Top class scholarship scheme for SCs (TCs) – approx. 17817 beneficiaries and expenditure approx. Rs. 313.48 crore since 2014-15.
 - National Overseas Scholarship Scheme for SC etc. students (NOS) – 534



beneficiaries and expenditure approx. Rs. 152.23 crore since 2014-15.

- National Fellowship Schemes for SCs (NFSc) – 18036 beneficiaries and expenditure approx. Rs. 1511.65 crore 2014-15.
- Schemes for Residential Education in high Schools in Targeted Areas (SRESHTA): Total Rs. 247 Crore spent benefitting total 1,55,715 SC students:-
- PM Young Achievers Scholarship Award Scheme For Vibrant India for OBCs and others (PM – YASAVI) having following five sub-schemes:-
- Pre-Matric Achievers for OBC, EBS and DNT students – 563.9 Lakh beneficiaries and expenditure approx. Rs. 1195.33 crore.
- Post-Matric Scholarship for OBC, EBC and DNT students-302.05 lakhs beneficiaries and expenditure approx. Rs. 8186.56 crore.
- Top Class Education for OBC, EBC and DNT Students-New initiative has been taken.
- Construction of Hostel for OBC Boys and Girls- Expenditure approx. Rs. 260.70 crore for construction of Hostels having 16870 seats.

2) This Department is implementing schemes for social upliftment Scheduled Castes (SCs), Senior Citizens, Victims of Alcoholism and substance Abuse, Transgender Persons, Beggars etc. Department has been approx. Rs. 10304 Crore on Social Defence front and over 42 lakh persons have been benefited during last 08 years.

- Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)
- National Action Plan for senior Citizens

(NAPSrC) – Total Beneficiaries since 2014 are 271365 and expenditure approx. Rs. 334 Crore.

- Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) – 8,30,739 assistive devices amounting to Rs. 182.06 Crore have been distributed to 2,40,490 persons in 236 camps.
- Livelihood & Skilling Initiatives for Senior Citizens –
- (i) Scheme for Elderly Self Help group have been started in 2021-22.
- (ii) Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity (SACRED) Portal was launched on 01.10.2021.
- Silver Economy (SAGE portal) : 09 Start ups have been selected in the financial year 2021-22.
- Scheme for prevention of Alcoholism and Substance Abuse :
- National Action plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) – Total Beneficiaries since 2014 are 11,35,292 and expenditure of Rs. approx. 839.09 Crore.
- Nasha Mukta Bharat Abhiyaan (NMBA) – Presently, About 357 IRCAs, 78 ODICs, 55 CPLIs and 35 ATFs are spread all over the country. Through the various activities undertaken on-ground 2.46+ Crore people reached so far including 1.17 Crore youth & 30 lakh women.
- Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE):
- Central Sector Scheme for Comprehensive Rehabilitation for Welfare of Transgender Persons.
- Central Sector Scheme for Comprehensive Rehabilitation of persons engaged in the act of Begging.

- Rs. 1,75,03,200 has been spent in SMILE in 2021-22.
 - 3) Being the nodal ministry for prevention of atrocities, The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) {PoA} Act, 1989 enacted with a view to, inter-alia, preventing atrocities against members of SCs and STs; has been made more deterrent and effective by inserting clause 18(A) in the Act and modifying its rules in the year 2018 to set up egalitarian society across the country.
 - Total number of Atrocity victims provided relief: 435382 with amount: Rs. 3073.77 Crore.
 - Inter-Caste marriage initiatives: 164325 couples benefitted.
 - 4) Ministry has enacted “The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019” to provided protection of rights to transgender persons and for their welfare.
 - 5) By taking historic decision, 10% reservation has been provided for the Economically Weaker Sections by inserting 15(6) and 16(6) articles in the constitution of India through its Amendment in the year 2019.
 - 6) This Department has been implementing various skill developments and loaning schemes through its Corporation for making marginalized sections of the society economically empowered and Atamnirbhar also. Over 20 lakh persons from the marginalized sections from SCs, OBCs, DNTs, EBSs and Safai karamcharis have been benefited by spending amount of Rs. 8286 Crore since the financial year 2014-15.
 - 7) In the Honour of Dr. B R Ambedkar, We were fortunate to build Panchtirth at five Places:-
 - Ambedkar’s birthplace in Mhow.
 - The place in London where he stayed while studying the UK.
 - DeekshaBhoomi in Nagpur, where he took education.
 - Mahaparinirvan Sthal in Delhi and
 - Chaitya Bhoomi in Mumbai.
 - 8) Dr. Ambedkar International Centre (DAIC) has also been built up at Janpath in Delhi to reduce Socio-economic inequalities by conducting rigorous and authoritative research.
 - 9) This Department has set up a National Helpline for prevention of atrocities on members of SCs/STs, Toll free No. “14566”. National helpline for Sr. Citizens has also been provided on toll free no. “14567”.
 - 10) All the schemes and projects have been started executing through e- files only by adopting 100% Go-green. This Department has strengthened e-governance and ensured 100% transparency by implementing IT enabled system for making end-to-end activities online. ‘e-Anudaan’ portal has been developed and made operational where all the proposals from NGOs/Trusts/Societies etc. are received and processed online.
- Department through various programs and schemes will always be striving to build an inclusive society wherein adequate support is provided to members of target groups for their development and making them economically and socially self-reliant across the country.



AI For The Inclusion of Differently Abled Persons: Law and Policy Analysis

Dr. Ashok Kumar

Ms. Mansi Shukla

“For most people, technology makes things easier. For people with disabilities, technology makes things possible.”

~ Mary Pat Radabaugh

According to the World Bank more than one billion people in the world struggles with some form of disability. The marginalization of this population is not just an important human rights issue but it also impacts the economic standing of a country. The exclusion of this population from social, educational and economic opportunities not only takes away their right to a dignified life but is also responsible for a greater stress on country's welfare funds. No country can achieve true equality until the disabled population of that country is empowered. The social theory of disability says that it is not the disability of a person but of the society which is unable to provide the person with necessary means. A ray of hope in this scenario is seen through modern day technologies which are capable of breaking the traditional barriers for persons with disabilities. With these technologies, assistive devices that can help PWD to have better access to information and other things, which enable them to communicate better, are changing the paradigm of technology-enabled development for PWD. One such technology can be AI. AI is a spectrum of technologies through which smart machines that can not only replicate human behaviors but can also extend human capabilities like sensing, comprehending, learning, etc, can be made. This would empower people to unleash

their potential by achieving much more than they could on their own. Through this paper the authors try to develop a multi-dimensional model framework to empower the differently abled population of India through AI. The model is named as LEST (Law & Policy, Employment, Social (daily life), Technology) and shall focus on the development of law and policy for the welfare and protection of differently abled people along with creating an inclusive social life and work environment by innovative designs powered by AI and at the same time keeping a check over the technology to remove all kinds of biasness. The paper also seeks to emphasis why is the differently abled population, the most vulnerable group of population in India along with the rights of PWD and the obligations of government to safeguard their interest and the failure of the government in doing so. The Study Area of the paper is law and policy.

1. Introduction

A truly balanced society is the one which is inclusive of its entire population. Most societies today fail to accommodate the differently abled people which simply means a large population being disintegrated from the normal social life resulting in major human rights violations and also underused human resource which

*School of Law and Governance, Central University of south Bihar, NH-120, Gaya Panchanpur Road, Post. Fatehpur, Gaya – 824236 (Bihar), India | E-mail- ashokkumar@cusb.ac.in

**Research Scholar, Faculty of Legal Studies, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh

has so much potential to contribute to nation building. This disability of the society not only takes away the right to dignified life from differently abled people but also pushes them to become economically, socially and politically marginalized. It is true that the disability of a person is not entirely of his own, the societal and environmental factors contribute to a great extent. The International Classification of Functioning, Disability and Health [hereinafter ICF (Fig 1)], is a model developed by WHO's which is used globally to measure health as well as disability at both personal and public levels. The disability of an individual, according to this model is a multi facet relation between the health situation of that person and societal/ environmental factors. Going by this model a way to accommodate the differently abled population would be to, First to empower our healthcare services with the most advanced healthcare and assistive technology and second to empower our society to be more inclusive of the people with disability. The use of Artificial Intelligence can be a big turning point to the current scenario to make the society more inclusive for PWD, the LEST model aims on the same.

2. Study Area:

The Study Area of the paper is law and policy i.e, how the law and policy should evolve and adapt to the use of artificial intelligence in assistive technology to empower persons with disability.

No specific geographical area was targeted for the purpose of this research.

3. Methodology:

The approach adopted for this paper is doctrinal. The literature review of various secondary data available is done. The data is collected from different research papers, journals, books, articles published, etc.

4. Differently Abled Population of India : Their vulnerability, Their Rights and obligation of government towards them

The very first obstacle in combating disability is to define disability and determine what shall be its measure. In its literal sense disability can mean an impairment of mind or body that limits the capabilities of the person suffering from it. The UNCRPD, 2006 has defined disability by taking into consideration the societal and physical model of disability. The Convention in its Preamble (para (e)) states that “*disability is an evolving concept which results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.*” On a similar line the Section 2(s) of The R.P.D. Act, 2016 defines “*person with disability*” to mean “*a person with long term physical, mental,*

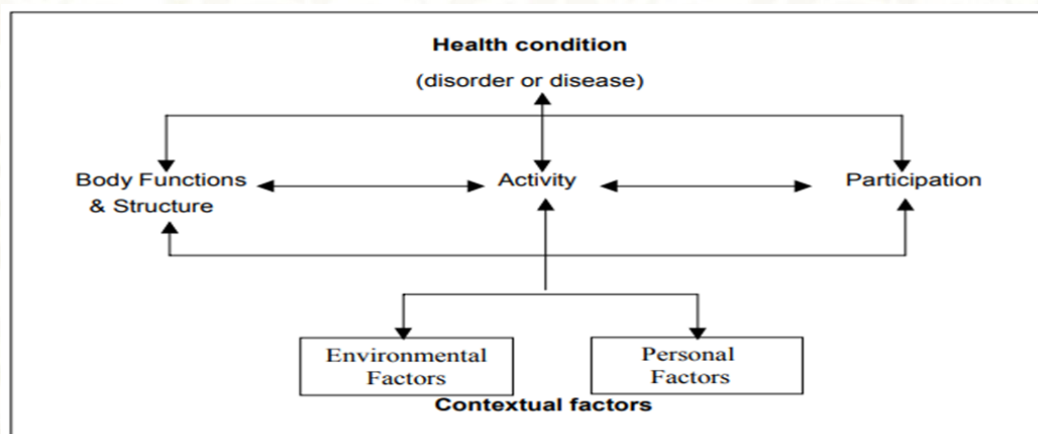


Figure 1: ICF Model of Health and Disability



intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others."Therefore now it is globally accepted notion that there exist social factors too in disability. Although this shift of perspective has helped people with disabilities a lot but still the condition is below satisfactory. For example statistics have shown that disabled people are more prone to poverty (it is estimated that some kind of disability is associated with 20 per cent of the poorest population around the globe), violence (researches indicate that the rate of violence against disabled children is 1.7 times higher than against children without disability and also disabled persons are at a higher risk of rape and other kinds of violence but are less likely to seek legal intervention and protection) and education deprivation (The data from developing countries shows that Ninety per cent of disabled children skipped school)(United Nation, n.d). Women with disability are even more vulnerable among the disabled persons. Disabled women face multiple disadvantages, first on the grounds of gender and second on the grounds of disability. In a society where the gender divides leads to higher levels of violence against women, women and young girls with disabilities are more prone to abuse. A small scale study based in Orissa, highlighted that all the women battling with disability faced physical violence at home, the study also found that 25 per cent of women with mental disabilities were the victims of rape and 6 per cent of women with disabilities were forcibly sterilized. (United Nation, n.d) In developing country like India there has been a minimal rise in the disabled populace from 21.9 million in Census, 2001 to 26.8 million in Census, 2011(Ministry of Statistics and Programme Implementation in India, 2021). Despite such huge population battling from disability the education and employment statistics shows our failure as a society. In India 55% of the disabled population is literate but only 5% of the people belonging to the disabled population are graduates and above. This low education rate is

again reflecting in employment deprivation with only one third of the total disabled population to be the part of work force, i.e; 1.7 Cr. disabled non-workers(Ministry of Statistics and Programme Implementation in India, 2016). These statistics shows the vulnerability of the disabled population. With no education and employment they are bound to get marginalized. In the words of Stephen Hawking the vulnerability of persons with disability is due to the attitudinal, physical, and financial barriers and it is the moral duty of society to address the issue. When PWD are denied opportunities due to these barriers they are not just denied their basic human rights but society also loses a valuable resource. Keeping this in mind and to fulfill State's duty to provide PWD access to health, education, employment and rehabilitation, legal framework at both national and international level is developed.

At the international level numerous international instruments were drafted to address the hardships faced by the PWD population. The most important of them is the UNCRPD, 2008. This convention objectives at building an inclusive society and puts an obligation over its State parties to ensure that all the laws and practices pertaining to discriminate against a person with disability should be revoked and the States should also ensure the full realization of the fundamental and human rights of the person with disability. Before this convention a declaration was made by the countries in the Asia Pacific for addressing the problems of people suffering from disability in the region under the name of Declaration on the Full Participation and Equality of People with Disabilities in the Asia Pacific Region, 2000. In 2002 ESCAP also adopted the Biwako Millennium Framework which aims to take actions for "*an inclusive, barrier-free and rights-based society for persons with disabilities in Asia and the Pacific.*"The Biwako Millenium Framework was further strengthened in 2007 by Biwako Plus Five. To further strengthen the regional framework for Asia Pacific the Incheon Strategy was adopted in 2012. The Aim was to

“Make the Right Real” for People with Disabilities in Asia and the Pacific. India being a part to all the above mentioned international instruments has an obligation to fully abide by these. Apart from this The Sustainable Development Goals (2015) also work on the principle of inclusion by “*leaving no one behind*”. The Goal 3 which is Good Health and Well-Being when read with Goal 10 which is Reduced Inequalities of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development is of importance for PWD.

Along with these international instruments Indian legal framework for PWD is also supported by the Municipal laws in terms of various statutes made in compliment with the Indian Constitution. The India's Constitution ensure through Preamble and Part III to every citizen justice (social, economic and political) equality (of status and opportunity) and dignity. The Constitution also ensures the right to self-determination and bodily autonomy. Nowhere it is indicated or can be reasonably argued that these Rights can be denied to Persons with disability. Apart from these rights the Constitution of India also imposes a duty over the State to ensure welfare of PWD under Article 41, which states that “*State shall within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.*” Article 46 also lays down an responsibility on the State “*to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people.*”

Apart from these constitutional provisions there are various statutes for the welfare of PWD, these include:

- The Rehabilitation Council of India Act, 1992: This Act provided for Rehabilitation Council of India which framed policy parameters for the various facets of training and education in the arena of Rehabilitation and all institutions have to seek recognition from RCI as per provision of this Act.
 - The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999: The Act establishes a trust to provide total care to people with mental retardation and cerebral palsy and also cope the properties bequeathed to the Trust.
 - The Mental Health Care Act, 2017: It provides for the safeguard of Rights of people with mental illness and ensures their welfare.
 - The RPWD Act, 2016: This Act replaces the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. The Act is in line with the CRPD, to which India is a signatory and likewise the Act establishes a more inclusive definition of disability helping more PWD people to have access to the government welfare systems and facilities made for them. The Act pays attention to the institutional development for the welfare and also ensures remedy in case of violation of rights of disabled people by setting up of Special Courts in each sub district and district.
- The law in India has failed to create an inclusive society. The statistics quoted from the data of Indian government are evidence of it. A hope for an inclusive society is seen if people with disability are empowered in true sense i.e, from being disabled in the sense of their restricted capabilities due the societal and environmental factor if they are made abled by the use of assistive technology. Artificial Intelligence can work wonders in this regard. The next part of this chapter explores the same possibility.

4. AI Powered Model For Empowering Persons With Disability: LEST MODEL

AI is a big leap forward in the computer technology. AI systems can perform even in situations which are not previously mapped out in the system because of their capabilities to learn



from the surroundings, previous experiences, etc. This model of computer is analogous to human learning and because of this reason it is often called as 'cognitive computing'. In cognitive computing or machines with artificial intelligence bulks of data is processed to identify patterns, which are further used to create entirely new patterns, permitting the machines to test hypotheses and find solutions to a situation for which machine was not previously versed with. The capabilities of an AI system to learn from bulks of data and past experiences makes AI a very dynamic as well as disruptive technology of today.

More than one billion people suffer from some kind of disability that limits their functionality but with AI having cognitive tendencies like humans and being capable to see, hear or comprehend things there is a great deal of untested potential in which these one billion people can be helped out. AI can truly empower them and give them a dignified life. For example: with AI a visually impaired person can be helped out by having things like road signs or books read to them. Microsoft's initiative named AI for Accessibility is providing assistance to people with disability with the help of AI technology in various fields like education and employment. Governments and various institutions can also learn from this initiative of Microsoft. To employ the use of AI in building a more inclusive society a model has been developed by the authors which is discussed below.

LEST MODEL:

The LEST Model is the model developed by the authors of this chapter and this is the least we can do for the people with disability. The Model stands on four pillars as indicated in the Fig 2. Working on these four pillars a more inclusive society can be build for PWD. There are various suggestive changes and policies that the government should pay attention to in different aspects of this model. These suggestive changes and policies are indicted below.

• LAW & POLICY:

In India, although we have a legal framework for the protection of rights of PWDs in the form of Indian Constitution and statutes like RPD Act 2016 but the enforcement of this legal framework is good only in books. The enforcement of the legal framework for the protection of Rights of PWD needs to be strengthened with the active synergy of government with public, private and social sectors at all the levels local, state and national. For a standardized and effective framework we need more intensive policies and dedicated human resource to implement these policies because AI alone cannot do everything neither it should be allowed to, a human supervision should always be kept. The society needs changes as well and what is more impactful tool of social transformation than law. The major problem in forming law and policies for disabled people is their lack of representation and also a lack of systematic data and studies on their problems and issues. After collecting the necessary data, this data can be analyzed by the help of AI to form more impactful policies. Not only this, this data might also be helpful in teaching AI.

It is believed that if the needed assistive technology is given to people with disability their life can be truly transformed. It is believed that a very less percentage (10% or below) of people battling with disability are provided with the access to essential assistive technology. Assistive products can transform an individual's life, as well as that of families and the entire communities. Who can be a better example of this then Stephen Hawking? The assistive technology not only gave him a chance to shine but gave society much more than it gave Hawking. Ever thought how many Stephen Hawking never get a chance to shine because they are denied any assistive technology. Without any access to assistive technology the impact of disease and disability is escalated on the person suffering from it. This not only impacts him but also the care givers, his/

her family and society. People thus affected are being denied fundamental human rights required for dignified human life and not just an animal existence. So the very first policy change that the government needs to ensure is that people with disability get proper access to the required assistive technology. AI can play a magnificent role in designing these assistive technologies. Government could incentivize the use of AI in these assistive technologies by raising more funds in the R&D or by making these kinds of research and development activities an integral part of CSR activity of the companies which have the necessary resources needed.

Another aspect related with assistive technology after making it accessible is the awareness. Government can use various mass communication means to raise awareness. Along with raising awareness for these technologies government should also raise awareness through mass communication and counseling among the care givers belonging to the health care and the family of the PWD on how to use the technology and what can be the practical hardships and also on various myth busting. Stigmatization of PWD should be made a severe offense and social awareness should be raised against stigmatization through various schemes of the government. References index of this paper cites a work of Accenture which explains Accenture's model of making AI based technologies on the "R(AI)S Principles {Responsible, Accessible, Inclusive, Secure}", the government can also learn from this and develop a legal system to check AI based assistive technology to full fill all these grounds. For example: if any technology is seen to be less inclusive or discriminatory or biased against PWDs the developers and the manufacturers should be held liable. Not just AI based assistive technologies but all technologies, especially the ones used in the admission process in educational institution or employment should be tested for any possible biasness against PWD.

EMPLOYMENT:

To save any community from being marginalized the very first step is to make them economically empowered. A study shows that there is an overreaching barrier in the employment of disabled people because there exists a strong biasness against people with disabilities in the work dynamics due to the existence of a wrong perception that having people with disability would not just be difficult for the organization in terms of accommodating them but shall not be worth of the effort and resources that organization has to offer (Microsoft, 2020). Although, the truth is quite opposite. Another study had revealed that people with disabilities are an asset to the organization due to their loyalty, exceptional perseverance and problem-solving skills. People with disabilities are found to be with high morale and enthusiasm for work (Accenture, 2020). Since the misguided perception is highly persistent and common it leads to high unemployment rates among disabled people. In fact the rate of unemployment among disabled people is double than that among people without disability. As a result the disabled people are not only marginalized but humanity also misses out on what people with disabilities can contribute to society if proper assistance is being made. A large portion of the productive population is never utilized. If we are successful in utilizing this portion this isn't just going to make people with disability empowered but is also going to help business grown and ultimately would lead to nation building.

Work cited of Accenture in the references index has suggested three foundational steps for the organizations to use AI and create a more inclusive workplace (Accenture, 2020), these steps are:

- Number one, "expanding the executive awareness of the power of AI to foster disability inclusion";



- Number two, “Focusing on the myriad benefits of AI while screening for and eliminating the possibility of unintended consequences”; and
- Number three, “Using the R(AI)S guiding principles to inform decision-making about using AI to improve inclusion”.

Apart from making a more inclusive workplace the law should also ensure that qualified individuals with disabilities are not denied employment on the grounds of disability, unless any undue hardship is caused to the organization. The RPD Act, 2016 and the rules of 2017 made under it are truly a welcome step in terms of providing better employment opportunities to people with disability because it puts an obligation on the private establishment to reserve jobs for persons with disability. The term ‘private establishment’ is defined in wide connotation to include almost all establishments excluded from government functionaries. Also the step of legislature to put an obligation over these private establishments to prepare and publish an Equal Opportunity Policy for persons with disabilities which shall contain details about facilities and posts identified for persons with disabilities and other details of how the workplace has been made more inclusive, is a progressive one and should be appreciated.

SOCIAL /DAILY LIFE :

As discussed above the disability exist due to a discriminatory society. So if we make a more inclusive society the disability, if it doesn't cease to exist might be reduced to a great(er) extent.

The very first step shall be of an inclusive education. Most disabled people are thrown into poverty because of the lack of education. Microsoft's initiative claims that there exist great opportunities in building modern solutions for people with disabilities by making software and devices smarter and more contextually relevant. Communication which is the very basic pre-requisite for providing equal access

to information and opportunities can be made more inclusive with the technologies that can create new possibilities regardless of how a person listens, speaks, or writes.

The second step shall be to build more inclusive buildings, transport and infrastructure which shall have inclusive designs to accommodate the differently abled people.

Initiatives like Paralympics and having models for fashion shows belonging to differently abled category are some wonderful steps taken in recent past and should be encouraged. Programs of Makeathon could also help in breaking the social stigma and might also result in an innovative design for assisting people with disabilities.

TECHNOLOGICAL :

Although it might seem that AI is the answer to all problems but it isn't so. Since AI is the replica of human brains and cognitive tendencies, just like human brains it can also suffers from biasness. There is a need to address the ethical issues associated with AI helping people with disability to make the empowerment of disabled people to the full extent. Even when there is no biasness attached to AI sometimes the use of AI can be very frustrating for the person with disability. The work cited in the reference lists indicates how Microsoft uses “*independent algorithmic assessments and auditing and adoption of inclusive design principles. This principle ensures that AI solutions are designed—and their underlying data are assessed—as rigorously as possible to prevent unintended consequences such as bias and discrimination.*” If proper caution is not taken in the design, development, and testing of an AI, it might actively discriminate against disabled people (Guo, A et al, 2019).

The solution to this ethical problem with AI is somewhat narrowed down by the 2019's European Union's High-Level Expert Group report on AI: Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence, as cited in the reference

lists. The guidelines states that a trustworthy AI should be:

- “Lawful”, respecting all applicable laws and regulations
- “Ethical”, respecting all ethical principles and values,
- “Robust”, from both technical and social environment perspective.

These guidelines can be the guiding principles for the manufacturers of assistive technology including AI, and law should also permit the usage of AI models that are trustworthy.

5. The Final Thought : Conclusion

Artificial intelligence (AI) is the most disruptive technology of the century. It has the capabilities to learn on itself from the given data and experiences. Unlike traditional computers, these cognitive computer technologies can perform tasks that were explicitly limited to humans and human intelligence. The capability of AI to learn and perform tasks like human do can open the doors of accessibility to people with disabilities. AI can be a blessing for people with disabilities and powerful enough to foster inclusion in society as well as nation. AI that Facilitate the needs of disabled people can often also better meet the needs of nondisabled, therefore everyone can be benefitted from AI. Although it should be understood that the utility of AI doesn't rules out the numerous challenges for AI to be completely inclusive and supportive of disabled people. Since AI can have a massive impact on the lives of people with disabilities it should be made sure that it has a positive impacts on them and helps them enjoys their rights. The AI should be trustworthy, i.e. it should fulfill all the parameters of being lawful, ethical, etc, as explained in the chapter. Policy makers should build up a legal framework to

ensure that ever AI which is developed and used is inclusive and does not suffers from any sort of biasness and as quoted above from the work of Accenture, also cited in the reference index, Accenture's inclusive principles; “R(AI)S (Responsible, Accessible, Inclusive, and Secure)” can be the guiding model for developing AI. A detailed legal framework should be developed to test an AI based assistive technology on these grounds before making it accessible to the public and severe liabilities should be imposed on the manufacturers of the technology if any negligence is seen. The law can check that whether all these requirements are fulfilled or not at the time of giving IPR protection to the AI, whether under copyright or patent. If the AI fails on these parameters or is not trustworthy, it should not be given any protection in IPR and it should also be made illegal. The law should also be vigilant about any futuristic complains with regard to the malfunctioning of any AI causing any biasness or danger to any person. If during the use any malfunctioning is caused the developer of AI should be given a notice and he should act on the notice within a reasonable period, say one month. In cases the developer doesn't attend to the notice he should be liable for legal actions and also violation of fundamental right to equality, in case of any biasness found in AI. The developers of AI should also abide by these principles during the manufacturing or developing process as a moral obligation.

The government should also take necessary steps to ensure proper distribution of funds for research and development of assistive technologies that can make the society more inclusive. Government can also organize various Makeathons with the IITs, NITs and other engineering institutions of the country with the aim of building more inclusive assistive technologies of persons with disabilities. This would not only break the social stigma



associated with persons with disability but also introduce participants to the type and level of problems and hardships people with disability face and who knows may be the young minds are able to develop a prototype to make the world more accessible to PWD in these makeathons.

Notes & References:

- World Health Organization. (2004). Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health ICF. <https://www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf>
- Ministry of Statistics and Programme Implementation in India. (2021). Persons with Disabilities (Divyangjan) in India - A Statistical Profile: 2021. http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Persons_Disabilities_31mar21.pdf
- Smith, P., Smith, L. Artificial intelligence and disability: too much promise, yet too little substance?. AI Ethics 1, 81-86 (2021). <https://doi.org/10.1007/s43681-020-00004-5>
- Accenture. (2020). AI for disability inclusion. https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-155/Accenture-AI-For-Disability-Inclusion.pdf
- Microsoft. (2020) Empowering people with disabilities through AI. https://futureofwork.wbcds.org/wp-content/uploads/2020/02/WBCSD-FoW-Case-Study_Microsoft_2020_final.pdf
- Ministry of Statistics and Programme Implementation in India. (2016) Disabled Persons in India A Statistical Profile 2016. http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Disabled_persons_in_India_2016.pdf
- United Nations. (n.d.). Factsheet on Persons with Disabilities. Retrieved on July 26, 2021 from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html>
- Ghosh, R., & Raman, L. (Eds.). (2019). Proceedings of National Conference on Assistive Technology for All 2030. https://at2030.org/static/at2030_core/outputs/Proceedings-of-National-Conference-on-Assistive-T_JqOHslJ.pdf
- Priestley, M., & Finkelstein, V., & Davis, K. (Eds.). (1997). Fundamental Principles of Disability. <https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/UPIAS-fundamental-principles.pdf>
- Guo, A., Kamar, E., Vaughan, J.W., Wallach, H., Morris, M.R: Toward Fairness in AI for People with Disabilities: A Research Roadmap (2019). arXiv:1907.02227
- European Union's High-Level Expert Group report on AI: Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence (2019).



सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ/शुल्क; वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 200 / डिमांड ड्राफ्ट

नम्बर दिनांक..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट 'डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र' के नाम नई दिल्ली के नाम पर हो

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता

..... पिन

फोन/मोबाईल न. ई. मेल :

इस कूपन को काटिए और डिमांड ड्राफ्ट सहित निम्न पते पर भेजिए:

डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र:

15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001



Guidelines for Submission of Manuscripts

Dr. Ambedkar International Centre (DAIC), located at 15, Janpath, New Delhi is a premier International Centre of Excellence of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India <http://daic.gov.in/about.html>. DAIC at 15 Janpath, Delhi was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India on 7th December 2017. DAIC has been envisaged to be the Centre of Excellence for study, research, analysis and policy briefs in the field of Dr. B.R. Ambedkar's vision, theories, philosophy and policies; socio-economic transformation and inclusive sustainable development and livelihoods; Buddhist studies; thought, culture and philosophy; social wellbeing.

The DAIC is conducting international level reputed research, documentation, database development, publications, knowledge dissemination, publicity, networking, collaboration with national and international institute/university. DAIC is organizing capacity building programme, training, seminar, conferences and symposium etc. on various interdisciplinary and multidisciplinary issues.

Samajik Nyay Sandesh is the official Quarterly Bilingual Peer Reviewed Journal publication of Dr. Ambedkar International Centre. The aim to publish this journal is to disseminate policies and research work for the upliftment of the marginalized group of the society. This is multi-disciplinary perspective, the journal publishes the best scholarship emanating from multidisciplinary research from demography, sociology, economics, political studies, anthropology, economics and psychology and other discipline of social sciences. The journal is published as a hard copy, print ISSN number being: 2455-6681.

Manuscripts from distinguished scholars are inviting in the form of original research paper, articles, review article, reviews (book/policy/research project) and success stories of the applied action oriented work related to the theme of the journal for the upcoming issue of the Samajik Nyay Sandesh.

The journal has a peer review process, which is fair, unbiased, and timely. The research articles are reviewed by an external and independent reviewer, and wherever necessary the editor seeks an additional opinion.

Ethics Policy

Only original work not published elsewhere, in whole or in part, is published. Authors are required to give a certificate to this effect at the time of submission for publication. The contributions are screened carefully to detect any regional, political, religious, and social or gender bias. The conclusions drawn are expected to be based only on processed data. The journal is particularly averse to any kind of plagiarism/plagiarized material.

Instructions to Authors for manuscript preparation Submission of Manuscripts: Manuscripts can be submitted through email as an attachment at Chief Editor **email: snsdaic123@gmail.com**

Manuscripts should be typed and double-spaced with maximum 3500 words. Manuscripts should be carefully checked before submission and must be preceded by a cover page, listing the title of the paper, full name(s) of the author(s), and their mailing address.

The manuscript should be prepared in English using "MS Word" and "Times New Roman" font and in Hindi 12 font size Kruti Dev. The pages should be numbered consecutively, starting with the title page and through the text, reference list, tables and figure legends.

The title page should contain Title, Authors, Affiliations, and Corresponding author and address. The title should be brief, specific and amenable to indexing. Not more than five keywords should be indicated separately; these should be chosen carefully and must not be phrases of several words.

Page number and caption of the figures and diagram are need to be placed properly. Page number are to be placed in the upper right hand corner of every page.

References The list of References at the end of the text should be in the MLA 7th style. Reference should be arranged in alphabetical and chronological order. In the text, author's surname, followed by year of publication and relevant page number.



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

वर्ष : 18

अंक : 3

सामाजिक न्याय संदेश

जुलाई-अगस्त-सितंबर 2022

समता, समानता और समरसता का वाहक

Forthcoming Issue
January-February-March 2023

सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास एवं सबका विश्वास
के अन्तर्गत परिवर्तनकारी सामाजिक व आर्थिक नीतियां

1. Socio-Economic Transformation of Marginalised Groups
2. Government Efforts for Equal Educations
3. Creating better Health Infrastructure to all citizens
4. Ensuring Equal Opportunity and Promoting Entrepreneurship
5. Equal acces all to the national resources
6. Linking, Connecting and Integrating Bharat

April-May-June 2023

ट्रांसजेन्डर पर्सन : दशा और दिशा

1. Identity and Social Acceptance
2. स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन
3. पुर्नवास
4. विधि, नीति, योजना और क्रियान्वयन
5. सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका

ISSN No. 2455-6181

RNI No. DELIN/2000/9036

₹ 50/-



डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
15 जनपथ, नई दिल्ली - 110001